ISSN 2454-504X 16-31 मई, 2025 राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका RNI No. DELHIN/2002/08663 ₹ 15

दूसरा मत

www.doosramat.com YOUTUBE DOOSRA MAT जहां सच बोलते हैं शब्द

सोफ़िया-सिंह का शौर्य

दूसरा मत

पढ़ें और पढ़ाएं,
एक शुभचिंतक, दिल्ली

दूसरा मत वार्षिक सदस्यता

व्यक्तिगत एक वर्ष स्पीड पोस्ट सहित 2500 रुपए
संस्थागत एक वर्ष स्पीड पोस्ट सहित 5000 रुपए
पीडीएफ प्रतिवर्ष 500 रुपए

विगत 23 वर्षों से देशहित में समाज-निर्माण के संकल्प के साथ

न हम डरते है न डराते हैं
हम देशप्रेम की भावना जगाते हैं

अगर आप में है जोश और देश से प्यार

तो आइए दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका

दूसरा मत के साथ

अगर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो तो हमेशा एक ही काम करोगे लेकिन पत्रकार बनते हो तो दुनिया समझने को मिलेगी, दुनिया समझाने को मिलेगी। दुनिया को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा, दुनिया को पढ़ाने का मौक़ा मिलेगा

हम आपके हाथ में देते हैं क़लम

समाज-निर्माण की ताक़त के साथ।

योग्यता
खबरों की समझ
और देश के साथ
सच्ची प्रेम-भावना

सोचो, समझो और दूसरा मत से जुड़ो

संपर्क : +91-9643709089

दूसरा मत
जहां सच बोलते हैं शब्द

RNI No. DELHIN/2002/08663

वर्ष: 24, अंक: 10
16-31 मई, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

संपादकीय सलाहकार
मन्त्रेश्वर झा (IAS R.)
(पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार)

प्रमुख परामर्शी एवं प्रमुख क़ानूनी सलाहकार
न्यायमूर्ति राजेन्द्र प्रसाद
(अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय)

प्रमुख सलाहकार
जियालाल आर्य (IAS R.)
(पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व चुनाव आयुक्त बिहार)

ब्यूरो प्रमुख
रुफी शमा

राजनीतिक संपादक
देवेंद्र कुमार प्रभात

बेगूसराय ब्यूरोचीफ सह ब्यूरो बिहार
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: doosramat@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आज़ाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं शालीमार ऑफसेट प्रेस, 2622, कूचा चेलान, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित।
संपादक-ए आर आज़ाद

पत्रिका में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। पत्रिका में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी।
सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा।
**उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

सुप्रीम कोर्ट 06
गवई बने नए चीफ़ जस्टिस

हलचल 08
अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री

ग़ौरतलब 10
चीन को रास नहीं आया सीजफायर

प्रसंगवश 14
आदमपुर एयरबेस की अनकही कहानी

दृष्टिपथ 35
सीजफायर सियासत शुरू

ज़रूरी सलाह 68
समाधान पर हो नज़र

तकनीक 54
...तौर तरीक़े बदले एआई ने

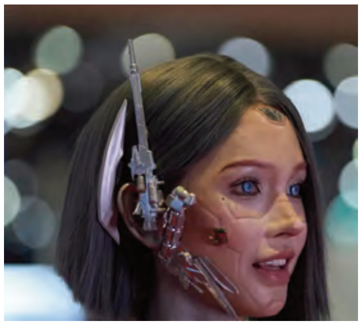

यक्ष प्रश्न: क्या सचमुच लक्ष्य प्राप्त हुआ? 30
सवाल: ... अब भी संशय है? 32
विचार: क्यों कहा 'गीदड़'? 44
मुद्दा: अमेरिका बनाम चीन 48
हस्तक्षेप: समरसता और जातीय गणना 60
समाज: व्हाट्सअप का एक सच 64
खेल-खिलाड़ी: कोहली का टेस्ट संन्यास 74

ज़रा याद करो क़ुर्बानी

ए आर आज़ाद

भारत-पाक संघर्ष बेनतीजा रहा। दोनों तरफ़ की आर्थिक बर्बादी इस लड़ाई का नतीजा निकला। प्रदूषण और दोनों ओर की तबाही सिर्फ़ सबक़ दे गएं। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। भारत उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचाता, इससे पहले ही उसके आक़ा ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन पर आंख दिखाकर शांत कर दिया। नतीजे में नतीजा कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान अपनी सोच और राह से एक रत्ती इधर से उधर नहीं हुआ। जीत के मुहाने पर आया हुआ कोई देश, कैसे क़दम पीछे करके देश के जज़्बात को ठेस पहुंचाता है, इसका ये युद्ध सबसे बड़ा उदाहरण रहा।

वाक़ई यह संघर्ष विराम एक भद्दा मज़ाक़ बनकर रह गया। कुछ बेशर्म और बेग़ैरत मीडिया घराने ने तो बेहयाई की हद को लांघते हुए इस्लामाबाद पर क़ब्ज़ा तक का ऐलान कर दिया था। ऐसा स्टूडियों में भले संभव हो, लेकिन सरहद पर आज के युग में कोई भी जीत इतनी आसानी से संभव भी नहीं है। आज के युग की लड़ाई रूस और यूक्रेन सबके सामने जीती जागती मिसाल है। आप इसके बरअक्स महाशक्तिशाली इस्राइल को देख सकते हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ इस्राइल ने जिस तरह की क्रूरता दिखाई, वैसी क्रूरता भारत किसी के साथ नहीं दिखा सकता है। भारत के ख़ून में इंसानियत की गंगा और जमुना बहती है। भारत आज भी दुनिया में मर्यादित देश के तौर पर स्वीकार्य है।

ये एक विडंबना है कि जिस देश के अधिकांश नागरिक सभ्य, सुशील, मानव-प्रेमी और देशभक्त हैं, उसी देश के अधिकांश नेता राष्ट्र को गन्ना की तरह निचोड़ने वाले, मानवता विरोधी हरकतों में संलिप्त रहने वाले और देश की आंतरिक शांति के लिए ख़तरा पैदा करने वाली सोच और मानसिकता के रोगी हैं। इस देश के लोग जितने देशप्रेमी और ईमानदार हैं, अगर इसी तरह देश के रहनुमा भी इतने ही ईमानदार हो जाएं, तो ये देश फिर से सोने का चिड़िया हो सकता है।

भारत संसाधन में अग्रणीय है। यहां एक मुंह और दो हाथ हैं। यहां के लोग अपनी जांबाज़ी के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में यहां के लोगबाग अपने पराक्रम और अपनी क़ाबलियत से अपना लोहा मनवाते रहे हैं।

भारत का सबसे काला पक्ष हिन्दू-मुस्लिम घृणा है। इस काला पक्ष की कला में माहिर सूरमाओं की आज जय बोली जा रही है। इसी जयजयकार ने इस देश को कई बार अंतराष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक शर्मिंदगी का एहसास कराया है। लेकिन इस देश के अधिकांश नेताओं की चमड़ी थोड़ी मोटी है, इसलिए उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता है।

भारत हिन्दू-मुस्लिम खेला के लिए अभिशप्त है। लेकिन एक शाश्वत सच्चाई भी यही है कि जब-जब देश पर दुश्मन देशों की कुदृष्टि पड़ी है, यहां तत्काल हिन्दू-मुस्लिम भेद भाव और नफ़रत देशप्रेम में बदल जाता है। और देश के दोनों समान नागरिक समान रूप से देश के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। यही क़ुर्बानी मुसलमानों पर लाख लांक्षणों के बावजूद देश के मुसलमानों को सर उठाकर और सीना तानकर जीने का सबब बनता है। वीर अब्दुल हमीद की शहादत से कौन इंकार कर सकता है? उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए देश के लिए अपने प्राण की आहुति देकर देश का क़द आसमान से भी ऊंचा कर दिया।

अभी-अभी इस जंग का नेतृत्व करने वाली जांबाज़ कर्नल सोफ़िया कुरैशी ने भी वीर अब्दुल हमीद के नक़्शे क़दम पर चलते हुए दुश्मन देश को तबाही का मंज़र दिखा कर ही दम लिया। इसलिए अब देश की जनता को धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण और गोरे-काले के भेदभाव जैसे उकसावे को शिरोधार्य करने से गुरेज़ करना चाहिए। और अपने महान देश को महानतम की श्रेणी में ले जाने के लिए सबके साथ एक समान नागरिक, एक समान शहरी और एक समान इंसान होने के भाव के साथ व्यवहार करना चाहिए। ●

जय हिंद! जय भारत!!

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का पद संभाल लिया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो बीते दिन ही सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के

52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी।

परंपरा के अनुसार, वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने सीजेआई जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी।

16 मार्च, 1985 को वकालत

शुरू करने वाले न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त, 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी। 17 जनवरी, 2000 को उन्हें नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर, 2003 को वे बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर, 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 24 मई, 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसी संविधान पीठों में शामिल रहे, जिनके फैसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। दिसंबर 2023 में, उन्होंने पांच जजों की संविधान पीठ में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा।

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आरएस गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई देश के दूसरे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन साल 2010 में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

तमिलनाडु सरकार को वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था।

जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4:1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और यह 'अनुपातिकता की कसौटी' पर खरा उतरता है।

जुलाई, 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया और उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था।

2024 में, जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते, अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।

अन्य फैसले

1.मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी थी। उन्हें इस केस में दो साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य करार दिया गया था।

2.सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत दी।

3.दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी।

4.दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को भी जमानत दी।

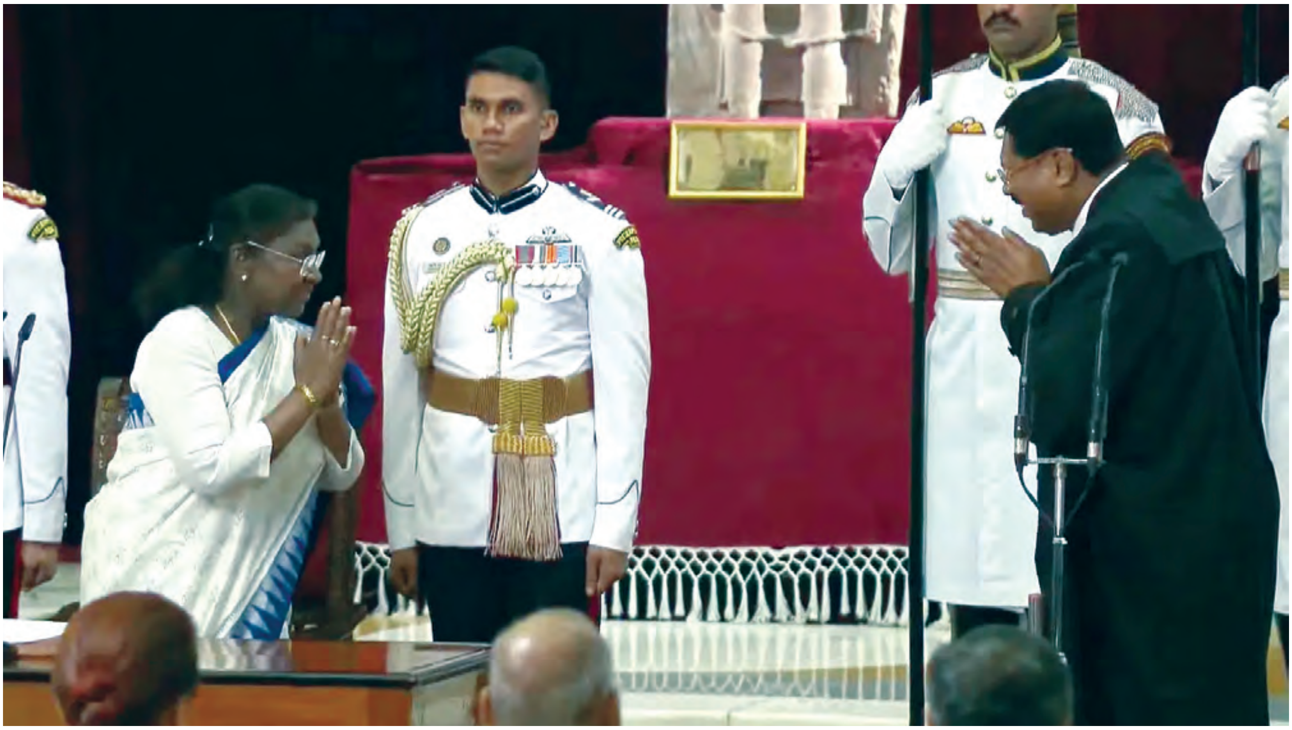

कनाडा सरकार में विदेश मंत्री

कनाडा की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। मार्क कार्नी की कैबिनेट में अनीता आनंद को विदेश मंत्री का पद दिया गया है। लिबरल पार्टी की वरिष्ठ नेता अनीता इससे पहले भी कनाडा की सरकार में रक्षा मंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अब वे मेलिनी जॉली की जगह लेंगी। मेलिनी जॉली को नई सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया है। कनाडा की 58 वर्षीय राजनेता अनीता आनंद ने हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। पूर्व में भी जब अनीता आनंद कनाडा सरकार का हिस्सा बनीं थी, तब भी अनीता ने भगवद गीता पर हाथ रखकर ही पद और गोपनीयता का शपथ ली थी।

विदेश मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनीता आनंद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'कनाडा की नई विदेश मंत्री बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अपनी टीम के साथ मिलकर सुरक्षित, निष्पक्ष दुनिया का निर्माण करने और कनाडा के लोगों की सेवा करने की तरफ देख रही हूं।' मार्क कार्नी की कैबिनेट में 28 मंत्री हैं। मार्क कार्नी ने दिखाया है कि वह जस्टिन ट्रूडो युग का अनुसरण करने के बजाय नई शुरूआत करना चाहते हैं। कैबिनेट में अनुभव और विविधता का पूरा ख्याल रखा गया है। कैबिनेट में आधी महिलाएं हैं।

भारतीय मूल की अनीता आनंद का जन्म 20 मई 1967 को कनाडा के नोवा स्कोटिया के कैंटविले इलाके में हुआ था। अनीता के माता-पिता सरोज डी राम और एसवी आनंद 1960 के दशक में भारत से कनाडा आकर बसे थे और दोनों पेशे से डॉक्टर थे। अनीता की मां का ताल्लुक पंजाब से और पिता का तमिलनाडु से है। अनीता की दो बहनें गीता और सोनिया भी हैं।

साल 1985 में अनीता आनंद ओंटारियो शिफ्ट हो गईं, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद अनीता ने डलहौजी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर की डिग्री हासिल की। अनीता आनंद ने कानून, शिक्षा और जनसेवा जैसे क्षेत्रों में काम किया। अनीता आनंद ने साल 1995 में जॉन नोल्टन से शादी की, जो एक कनाडाई वकील हैं। दोनों के चार बच्चे हैं और फिलहाल वे ओकविले में रहती हैं। कनाडा की सरकार में सेवाएं देने वाली अनीता आनंद पहली हिंदू नेता हैं। कनाडा की रक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिनके चलते उन्हें खासी लोकप्रियता मिली।

चीन को रास नहीं आया पाकिस्तान का सीजफायर सरेंडर

भारत-पाक सीजफायर को लेकर चार देशों- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने अलग-अलग बयान दिए, जिससे मामला और उलझ गया। वहीं पाकिस्तान के सीजफायर के तरीके से चीन की नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और सेना के सहयोगियों पर एक सटीक और तीखा हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था 'ऑपरेशन सिंदूर'। इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर ड्रोन और गोलीबारी जारी रही।

सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीजफायर की मांग की। भारत ने इस फोन कॉल की पुष्टि की और सीधा साफ कहा कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों ने बातचीत कर युद्धविराम का फैसला किया। ट्रंप ने कहा, 'हमने रात भर बातचीत की और अब भारत-पाकिस्तान में फुल और इमी-डिएट सीजफायर हो गया है। बधाई हो!' भारत ने इस दावे से साफ इंकार किया और कहा कि यह फैसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, और ट्रंप का कोई रोल नहीं है।

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

पाकिस्तान हमेशा चीन को 'ऑल वेदर फ्रेंड' कहता है। लेकिन इस बार जब संकट आया, तो पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से संपर्क किया, चीन से नहीं। इस बात से बीजिंग बहुत नाराज हुआ। सूत्रों के अनुसार, चीन को बुरा लगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को प्राथमिकता दी और उसे दरकिनार कर दिया।

जब ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की, उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन भेजे और भारतीय सीमा में घुसपैठ की। इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ बातचीत की एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि चीन ने पाकिस्तान की 'संयम और जिम्मेदार रवैये की तारीफ की। इसके बाद ही पाकिस्तान ने ड्रोन भेजना बंद किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चीन को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया था।

इसके दो दिन बाद चीन ने बयान जारी किया और दावा किया कि उनके विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की और यह बातचीत सीजफायर में अहम रही। चीन की तरफ से कहा गया, 'हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शांति बनाए रखें, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं और क्षेत्र को स्थिर बनाएं। चीन दोनों

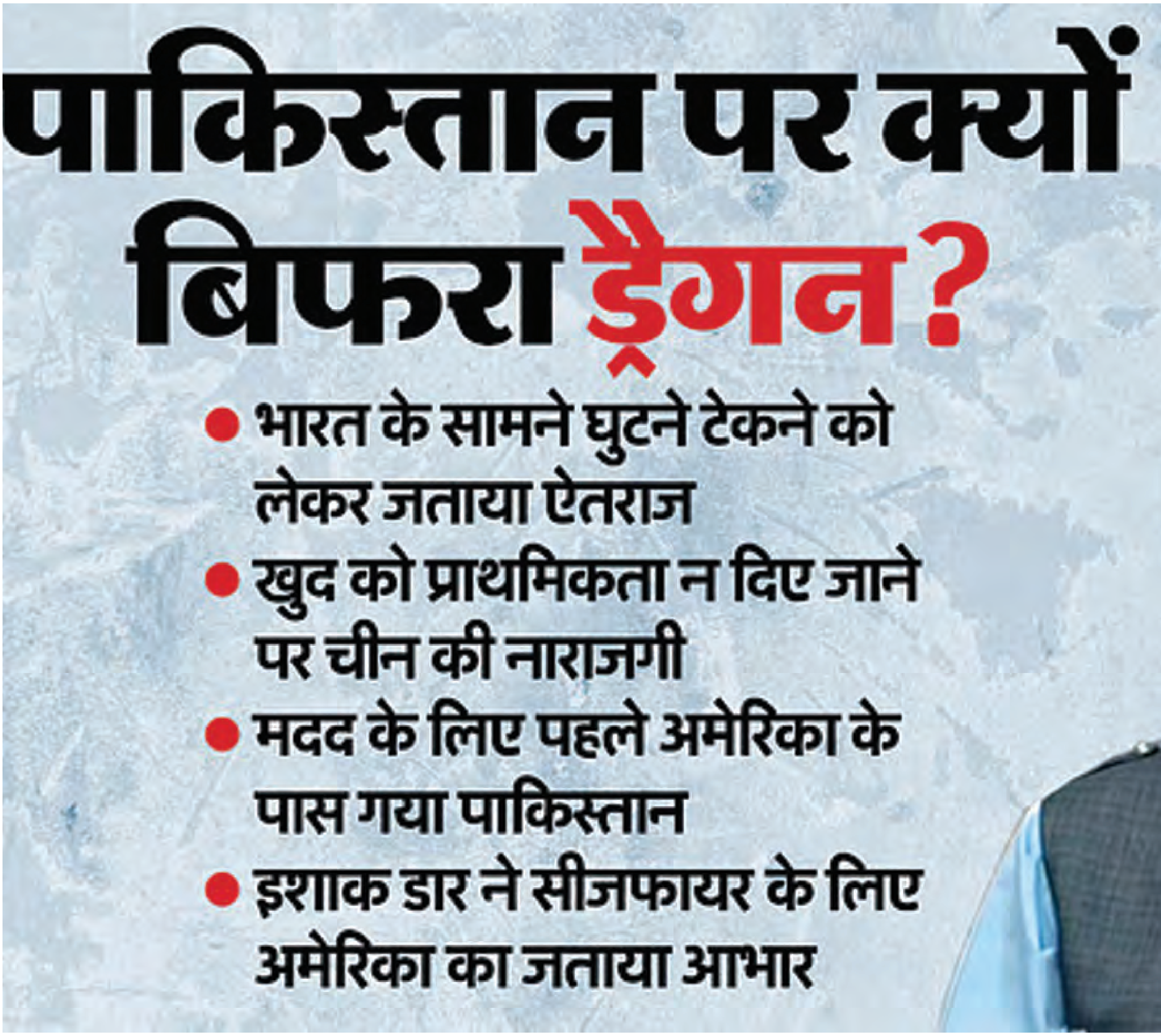

देशों से संपर्क बनाए रखेगा'। इसके बाद चीन ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की, हमारी कोशिशों से ही टकराव रुका और स्थायी शांति बनी। कुल मिलाकर अमेरिका के बाद चीन ने भी सीजफायर का श्रेय लेने की कोशिश में दिखा।

इधर, भारत ने साफ-साफ कहा कि वह सिर्फ आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था और पाकिस्तानी सेना की किसी भी हरकत का जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीजफायर की मांग पाकिस्तान ने की थी, और यह फैसला द्विपक्षीय स्तर पर हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संक्षिप्त बयान में कहा- पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज

दोपहर 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। दोनों देशों ने 5 बजे से सभी सैन्य का-र्रवाइयां रोकने का फैसला किया। वहीं 11 मई को ट्रंप ने एक और दावा किया कि उन्होंने व्यापार के जरिए दबाव बनाकर भारत और पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर किया। ट्रंप बोले, 'मैंने कहा, अगर सीजफायर नहीं हुआ तो कोई व्यापार नहीं होगा और फिर सबने कहा झ ठीक है, हम रुकते हैं।' हालांकि भारत ने इसे भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अमेरिका से बातचीत में कहीं भी व्यापार का जिक्र नहीं हुआ।

भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई और आतंकी हरकत हुई, तो जवाब और भी सख्त होगा। सीजफायर की शर्तों में यह भी जोड़ा गया कि कोई आतंकी घुसपैठ नहीं होगी, सीमा पर शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई थमेगी, लेकिन राजनयिक और रणनीतिक दबाव जारी रहेगा।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और दो दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद, भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिए। इससे घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर लिया। हालांकि, इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया।

आदमपुर एयरबेस की अनकही कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 मई, 2025 को जब जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें पंजाब पर आ टिकी। पीएम ने यहां से दुश्मन को करारा जवाब दिया। मोदी के दौरे से पाकिस्तान के झूठ का भंडाफोड़ तो हुआ ही, दुनिया ने भारतीय वायुसेना का शौर्य स्थल भी देखा।

जिस आदमपुर सैन्य हवाई अड्डे पर मोदी जवानों में जोश भर रहे थे,

उस बेस ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

छह सितंबर, 1965 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा में भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। आदमपुर और हलवारा पर हमले विफल रहे। स्ट्राइक ग्रुप आदमपुर पहुंचने से पहले ही वापस लौट गया।

7 सितंबर 1965 को, पाक एयरफोर्स ने 135 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पैरा कमांडो को तीन भारतीय हवाई अड्डों (हलवारा, पठानकोट और आदमपुर) पर पैराशूट से उतारा। यह साहसी प्रयास एक पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुआ। केवल दस कमांडो ही पाकिस्तान वापस लौट पाए, बाकी को युद्ध बंदी बना लिया गया (जिसमें ऑपरेशन के कमांडरों में से एक मेजर खालिद बट भी शामिल थे। आदमपुर में ये सैनिक रिहायशी इलाकों में उतरे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पश्चिमी मोर्चे पर 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के साथ शुरू हुआ। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद आदमपुर से इंटरसेप्टर से पठानकोट को कवर किया गया, जबकि ग्राउंड क्रू को रनवे की मरम्मत करनी थी।

1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान आदमपुर एएफबी से उड़ान भरते हुए, नंबर 7 स्क्वाड्रन आईएएफ के मिराज ने टाइगरहिल, मुंथो ढालो और टोलोलिंग पर हमला किया। आदमपुर बेस देश का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय वायुसेना बेस है और यहां दो फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन हैं। तीसरा मिग-29 फाइटर स्क्वाड्रन का मुख्य केंद्र है।

पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को बार-बार बनाया निशाना, नाकाम रहा

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान आदमपुर एयरबेस पड़ोसी मुल्क के निशाने पर रहा, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण कोई भी मिसाइल या ड्रोन यहां नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर हमले की तीन तरफ से कोशिश की, क्योंकि उसे सबसे अधिक खतरा इसी एयरबेस से है।

सेना के जवानों का हौंसला बढ़ाने सीमावर्ती आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम

निमिष कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस से सशस्त्र बलों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सलामी देते हुए कहा, 'जब हमारे ड्रोन और मिसाइलें दुश्मनों को निशाना बनाती हैं, तो 'भारत माता की जय' की गूंज उनके कानों तक पहुंचती है।'

पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कअब भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंक का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा।त उन्होंने तीन स्पष्ट बिंदुओं को सामने रखाः

1.भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ, तो जवाब भारत अपने तरीके, अपनी जगह और अपने समय पर देगा।

2.भारत अब किसी भी परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

3.जो सरकारें आतंक को समर्थन देती हैं और जो आतंकवादी मास्टरमाइंड हैं, उन्हें अब अलग नहीं देखा जाएगा।

मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत दिखा दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर में इस ऑपरेशन की सफलता की गूंज सुनाई दे रही है।

पाकिस्तानी वायुसेना केआदमपुर एयरबेस पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के दावे को पीएम मोदी ने मजाक में उड़ाते हुए उसी सिस्टम के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के झूठे दावों और वीडियो पर कहा कि 'झूठ का जवाब सच्चाई और साहस से दिया जाता है।'

पीएम मोदी ने भारत की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण को रेखांकित करते हुए कहा, 'आज भारत केवल ड्रोन से नहीं, डेटा से भी अपने आसमान की रक्षा कर रहा है। हमारी सेनाएं आधुनिक तकनीक और प्रतिभाशाली योद्धाओं से लैस हैं।'

कुरैशी- सिंहः धर्म से परे नया भारत

गजेन्द्र सिंह
वरिष्ठ स्तंभकार

हर दौर में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो इतिहास की दिशा मोड़ देते हैं – और नए भारत की कहानी में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऐसे ही दो नाम बनकर उभरे हैं ।पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब देश शोक और आक्रोश से भर गया था, तब इन दो जांबाज महिलाओं ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के संकल्प से न केवल राष्ट्र को भरोसे की नई भाषा दी बल्कि भारत की चुप्पी को एक शक्तिशाली हुंकार में बदल दिया। आज ये दोनों मिलकर 'कुरैशी-सिंह' के नाम से जानी जाती हैं – एक ऐसी जोड़ी जो भारत की एकता, ताकत और आशा की सच्ची प्रतीक बन चुकी है।

कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह – दो अलग पृष्ठभूमियों से आने के बावजूद, इन दोनों की भावना एक ही हैः मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का जुनून। गुजरात की धरती से निकली कर्नल कुरैशी भारत की पहली महिला अधिकारी बनीं जिन्होंने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया। संयम, साहस और रणनीति की मिसाल बन चुकीं कुरैशी के परिवार में देशभक्ति विरासत की तरह है जिसे वह गर्व से जीती हैं। वहीं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह – 'आकाश की बेटी' – बचपन से ही उड़ान भरने का सपना लेकर बड़ी हुईं और भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनकर उन्होंने इसे सच कर दिखाया। जब-जब वो उड़ान भरती हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की उम्मीदें उनके पंखों में सवार हो जाती हैं।

इनकी कहानी सिर्फ.दो महिलाओं की नहीं है बल्कि वह प्रतीक है उस नए भारत की, जहां बेटियां सिर्फ.सीमाओं की रक्षक नहीं, बल्कि देश की आवाज बनकर खड़ी होती हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ ह्यऑपरेशन सिंदूरह्न भारत की सैन्य शक्ति के साथ-साथ उसकी नैतिक दृढ़ता का परिचायक बना। इस अभियान के तहत आतंकवादी ठिकानों पर

सटीक जमीनी हमले, वायुसेना की अद्भुत हवाई कार्रवाइयाँ, दुश्मन के संचार और वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना और आतंकवाद के केंद्रों को पूरी तरह निष्क्रिय करना शामिल था। ह्यसिंदूरह्न नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति के सम्मान, पहचान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है – और यही भावना इस पूरे अभियान में स्पष्ट रूप से झलकती है।

साउथ ब्लॉक में हुई ऐतिहासिक प्रेस वार्ता में कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने देश को आश्वस्त करते हुए न सिर्फ.रणनीति का खुलासा किया बल्कि भारत की एकता को एक नई परिभाषा दी। कर्नल कुरैशी ने स्पष्ट कहा, ह्नयह बदला नहीं है, यह एक संदेश हैः आप भारत को तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, और इसकी आवाज को कभी दबा नहीं सकते।ह्न वहीं विंग कमांडर सिंह ने कहा, 'हम यह वर्दी नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा के लिए पहनते हैं। पर अगर चुनौती मिले, तो हम इसकी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।' यह क्षण सिर्फ सैन्य नेतृत्व का नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व का भी एक नया आयाम बन गया।

एक मुस्लिम महिला कर्नल और एक हिंदू महिला वायुसेना अधिकारी का मिलकर नेतृत्व करना, अपने आप में एक क्रांतिकारी दृश्य था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में नेतृत्व न जाति से तय होता है, न धर्म से – बल्कि हिम्मत, काबिलियत और देशभक्ति से तय होता है। भारत की बेटियाँ अब सिर्फ.इंतजार नहीं करतीं – वो सामने आती हैं, नेतृत्व करती हैं और देश को गौरव दिलाती हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम भी उतने ही प्रेरणादायक रहे । प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान में प्रमुख आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, सीमा पार के प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त किया गया, और अत्याधुनिक निगरानी के जरिए कई संभावित हमलों को पहले ही रोक दिया गया। इस अभियान ने भारत की सैन्य, कूटनीतिक और सामाजिक शक्ति को नई ऊँचाई दी है।

'कुरैशी-सिंह' अब सिर्फ.एक नाम नहीं बल्कि एक नए भारत की पहचान बन चुका है – ऐसा भारत जो सत्यनिष्ठा, समावेश और साहस से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में लोकतंत्र लड़खड़ा रहे हैं और समाजों में बंटवारा बढ़ रहा है, भारत ने एकता, ताकत और अटल मूल्यों की राह पर चलना चुना है। और इस राह की अगुआई कर रही हैं दो महिलाएं, जो अपने रैंक से नहीं, अपने कर्मों से भारत का भविष्य गढ़ रही हैं।

अब भारत की बेटियां दरवाजों पर दस्तक नहीं देतीं – वे दरवाजे खोलती हैं और सबसे आगे खड़ी होती हैं।

'न भयम्‌ कर्तव्ये, न च मोहः प्रयोजनम्‌।
धर्मो रक्षति रक्षितः, वीरता हि साधनम्‌॥'

डीएस हुड्डा
ले.जन. (से.नि.)

पाक को चेतावनी देते रणनीतिक बदलाव

छह-सात मई की रात, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ शृंखलाबद्ध सैन्य हमले किए गए। नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, जिनमें से पांच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और चार उसके पंजाब प्रांत में थे। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में मुरीदके और बहावलपुर रहे। लाहौर के नजदीक मुरीदके लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और उसके प्रमुख संगठन जमात-उद-दावा का मुख्यालय है। द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), जिसने पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ली, एलईटी से संबंधित बताया जाता है। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है। इसके बाद दो दिन और यह ऑपरेशन चला जिसमें दोनों ओर से सीमा पर गोलाबारी हुई। भारत ने दुश्मन के कई शहरों पर मिसाइलें गिराई वहीं पाक की ओर से भी ऐसी कोशिशें हुई। अब 10 मई को सीजफायर का ऐलान हुआ।

ऑपरेशन सिंदूर 2016 और 2019 में सीमा पार किए गए सैन्य हमलों की तुलना में झ पैमाने और दायरे में झ काफी बड़ा रहा। इसका संदेश कहीं अधिक तगड़ा और स्पष्ट है। जिसमें, पाकिस्तान से निबटने के लिए भारत की भविष्य की रणनीति में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव झलकते हैं।

प्रथम, बड़े आतंकी हमलों का दंडात्मक प्रतिकर्म होगा। चूंकि 2016 और 2019 के सीमित हमले पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को एक औजार की भांति इस्तेमाल किए जाने वाली अपनी राष्ट्रीय नीति त्यागने में असरदार नहीं रहे, इसलिए उन लोगों को दर्द महसूस करवाना जरूरी बन गया, जो आतंकवादी करतूतों को नियंत्रित कर रहे हैं। यदि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी नेतृत्व पर लगाम लगाने को तैयार नहीं, तो भारत सैन्य संसाधन का उपयोग करके ऐसा करेगा।

भारत ने रणनीतिक और सामरिक कारणों से लंबे समय तक संयम मुद्रा अपनाए रखी। हालांकि, बदलते सुरक्षा परिवेश, विशेषतः पहलगाम हमले ने, पुनसंर्तुलन में उत्प्रेरक का काम किया। 6-7 मई की रात बहावलपुर और मुरीदके जैसी अंदरूनी जगहों को निशाना बनाना संकेत है कि भारत अब सरसरी जवाबी कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानता। नया दृष्टिकोण सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए लागत-लाभ वाली गणना बदलने का प्रयास करता है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के प्रवक्ता की दी गई प्रस्तुति में, सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद से हुई क्षति को रेखांकित करने के वास्ते पिछले आतंकी हमलों (2001 में संसद पर हमले से लेकर मुंबई 2008, उड़ी 2016, पुलवामा 2019 और पहलगाम हमले) का लेखा-जोखा दिखाया गया, जिसके अंत में 'अब और नहीं' स्क्रीन पर चमका। भले ही यह प्रस्तुति नाटकीय दिखाई दे, लेकिन यह भारत के संकल्प को रेखांकित करती है कि वह पाकिस्तानी धरती से निकल रहे आतंकवाद को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

द्वितीय, सीजफायर के बाद पाकिस्तानी सेना के सामने दो विकल्प हैं। या तो वह स्वयं द्वारा लंबे समय से पोषित सैन्य-जिहाद परिसर को खत्म करे या फिर देश को भारत के साथ विनाशकारी संघर्ष में डुबाने का जोखिम उठाए। जो पाकिस्तान को और अधिक अस्थिरता और संकट में धकेल सकता है। दशकों से, पाकिस्तानी सेना ने जिहादी समूहों को अपनी रणनीतिक संपत्ति के रूप में माना है, उनका उपयोग भारत को जख्म देने के लिए किया जाता है, जबकि आधिकारिक रूप से इंकार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत वे स्पष्ट किया कि राज्य और उसकी प्रायोजित छद्म स्वरूपों के बीच कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान में कई अंदरूनी जगहों को निशाना बनाकर भारत ने संकेत दे दिया है कि सुरक्षित पनाहगाहें भी अब उतनी सुरक्षित नहीं रही।

प्रेस ब्रीफिंग में 6-7 मई की कार्रवाई पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत की 'कार्रवाई नपी-तुली, चीजों को और आगे न भड़काने वाली, आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी। इसके निशाने का केंद्र आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना और भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था'। यह पाकिस्तान के लिए संदेश था कि अगर वह किसी भी सैन्य जवाबी कार्रवाई से परहेज करे और आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के दीर्घकालीन उपाय करे, तो बढ़ते तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना

ने प्रतिक्रिया में युद्ध जैसे हालात रखे, जिसकाभारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया।

तृतीय, भारत इस बारे स्पष्ट है कि परमाणु युद्ध की नौबत बनने से जरा पहले तक, सीमित पारंपरिक संघर्ष के वास्ते गुंजाइश मौजूद है। जब भी भारत-पाकिस्तान संकट बनता है, तो पाकिस्तान सबसे पहले अपना परमाणु कार्ड लहराने लग जाता है। मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकता है, तो इस्लामाबाद परमाणु हथियारों से हमला करने को तैयार रहेगा। पाकिस्तान के राजदूत ने भी ऐसी धमकी दी। पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग से भारत अब खुद को बंधक नहीं मानता। पारंपरिक बलों के इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ढांचे को निशाना बनाने में वाले तौर-तरीके में धीरे-धीरे बदलाव आया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी पंजाब समेत कई आतंकी गढ़ों पर धावा बोलने में, हवाई हमले की उपयोगिता के रूप में नया मानक स्थापित हुआ है।

चतुर्थ, भारत में हुए आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध करवाने की कुछ अंतरराष्ट्रीय हलकों की मांग अब जाती रही है। भारत दशकों से पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और जब भी वह कहता है कि आतंकवाद का स्रोत पाकिस्तान है, तो यह बात सही है। समस्या यहां हमले करने वाले की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उस सैन्य नेतृत्व की है, जो आतंकवाद को पाल-पोस रहे हैं। अकाट्य सबूत की मांग छद्म युद्ध की प्रकृति को नजरअंदाज करती है। आतंकी संगठनों का ढांचा ही इस प्रकार तैयार किया जाता है कि सिद्ध करना मुश्किल हो जाए। भारत में आतंकी हमलों की निरंतरता, अपराध करने वालों की पहचान, प्रशिक्षण केंद्र और फंडिंग स्रोत- ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करते हैं जो राज्य के संरक्षण बिना काम नहीं कर सकता।

पंचम, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक संदेश है। आतंकवाद को शह-मदद करने वाले पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने में संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की अक्षमता को लेकर भारत में निराशा है। बेश-क,भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत और कूटनीतिक समर्थन जुटाना अहम है किंतु पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देने में, भारत के लिए विकल्पों पर निर्णय लेते वक्त अड़चन बनने में ये कारक अहम नहीं रहे। इस बार उकसावे के बावजूद संयम बरतने का आह्वान करने वाली बातों को भारत ने नजरअंदाज किया। तीन दिन चले ऑपरेशन सिंदूर ने नए सैद्धांतिक मानदंड स्थापित किए हैं कि आतंकी ढांचे पर हमला किया जाएगा; कि परमाणु हमले का डर दिखाना छिपकर करतूतें करने वालों को नहीं बचा पाएगा; कि वैश्विक समुदाय की नैतिक दुविधा भारत की संप्रभुता के विकल्पों को नजरअंदाज नहीं कर सकती; कि पाकिस्तानी सेना को जिहादी समूहों के साथ लंबे समय से जारी अपने गठजोड़ के परिणामों का सामना करना होगा।

यह स्थिति दक्षिण एशिया को कम स्थिर क्षेत्र बनाती है। यदि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को राज्य नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की राह पर बढ़ता रहा, तो उसे भविष्य में कठोर सच्चाई का सामना करना होगा।

(लेखक थल सेना की उत्तरी कमान में कमांडर रहे हैं।)

वैश्विक षड्यंत्रों को समझ पाएगा भारत?

कमलेश पांडेय
वरिष्ठ स्तंभकार

पहले अमेरिका और सोवियत संघ, फिर अमेरिका एवं रूस और अब अमेरिका व चीन के बीच जो दुनिया का थानेदार बनने की होड़ मची है, उससे गुटनिरपेक्ष देश भारत के हित गहरे तक प्रभावित हुए हैं। यह हमारे देश के नेताओं और अधिकारियों की गलत और पक्षपाती नीतियों का ही दुष्परिणाम है कि भारत को न चाहते हुए भी कभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तो कभी आंतरिक भूभाग पर युद्ध जैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, जिसमें धन-जन की भारी हानि होती है।

दरअसल, हमारे देश में बढ़ते साम्प्रदायिक विवाद, जातीय विवाद, क्षेत्रीय विवाद आदि का मौलिक कारण यह है कि विदेशी तिकड़मों के चलते आजादी से पहले हमारे 'मानवीय मूल्यों' से 'सियासी बलात्कार' हुए हैं, और उसके बाद उपजे पक्षपाती 'संवैधानिक मूल्यों' से भी 'अनैतिक प्रशासनिक व न्यायिक बलात्कार' हुए हैं! जहां प्रशासनिक और न्यायिक विवेक का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन यह कहते हुए किया गया कि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है अथवा उसकी मूल भावना यह है। यहां पर जीवन एवं प्रशासनिक मूल्यों का भी घोर अभाव महसूस किया गया है।

तल्ख अनुभव बताता है कि जब जब कोई 'राजा या उसका मंत्री' व्यवहारिकता की जगह परंपरा की दुहाई देता है और 'जनता या पड़ोसी राजाओं' से उसका तालमेल नहीं बैठता तो वह नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बाह्य आक्रमणकारियों को असंतुष्ट जनता का साथ मिल जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई वृतांत भरे पड़े हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों या ब्रिटिश कंपनियों को यहां के हिन्दू राजाओं ने एक दूसरे को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचकर बुलाया। और जब वो हिन्दू भारतीयों की कमजोरी पकड़ लिए तो यहां का शासक बन बैठे। जिससे लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय गुलामी का दंश झेलते रहे। और बमुश्किल आजाद हुए। लेकिन हमारे नेताओं की रस्साकशी ने फिर उसी विभाजनकारी घृणित सोच का सहज शिकार बना दिया, जो आज भी

जारी है।

वहीं, कांग्रेसियों, वामपंथियों, समाजवादियों, जातिवादी क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रवादियों के जनतांत्रिक सत्ता संघर्ष में ये तमाम दुर्गुण मसहूस किए जा सकते हैं। इसी बीच वर्ष 1990 के दशक से भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की आड़ में जो हिंसक-प्रतिहिंसक पूंजीवादी एजेंडा सियासी आवरण में चलवाया जा रहा है, उसके पीछे निहित उद्देश्य वश इतना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के नेतृत्व में जो उपनिवेश बनाए गए थे, वो अब सूचना व तकनीकी क्रांति के बाद अमेरिका के नेतृत्व में तथाकथित नए उपनिवेश में शामिल हो जाएं।

हालांकि इस बीच पूर्वी देशों के साम्यवादी रूस और चीन के उभार ने अमेरिका-इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देशों की जोड़ी के लिए 'भस्मासुर' का कार्य किया, जिससे निपटने के लिए भारत का पश्चिमी खेमे या पूर्वी खेमे से जुड़ना पहली शर्त है जबकि गुटनिरपेक्ष भारत सभी धड़े से समान दूरी बनाकर रखता आया है और तीसरी दुनिया के देशों को नेतृत्व देता है। इसके बावजूद समाजवादी सोच वाली कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस से और पूंजीवादी सोच वाली भाजपा के प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी ने अमेरिका से मजबूत रिश्ते कायम किए।

वहीं, पहले वित्तमंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर डॉ मनमोहन सिंह ने अमेरिकी शह पर व भारत के कारोबारियों की कीमत पर, चीन से कारोबारी संबंध मजबूत किए, जिसकी हवा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही निकलनी शुरू हो चुकी थी, जो 2014 में उनपर और उनकी पार्टी पर भारी पड़ी। इस प्रकार देखा जाए तो कभी भी अखंड भारत और मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद नहीं रखी गई। और अल्पमत-बहुमत के जनतांत्रिक हिसाब से भारतीयों को परस्पर लड़ाया गया, जिसकी भारी कीमत अब हिंदुस्तानी अवाम चुका रही है।

वहीं, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने अतीत की गलतियों को नए सिरे से सुधारने की एक पहल की। उन्होंने रूस, अमेरिका, जापान, इजरायल, फ्रांस आदि देशों से मजबूत संबंध स्थापित किए। और भारत के पड़ोसियों की नकेल कसी। यही वजह है कि पहले अमेरिका और अब चीन की मार्फत पाकिस्तान को साधकर भारत के खिलाफ भड़काया गया।

एक तरफ रूस, अपने पड़ोसी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ इजरायल, अपने पड़ोसी फिलिस्तीन के साथ संघर्षरत है। और तीसरा मोर्चा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खोल दिया है। वो भी ऐसे समय में जबकि भारत के दो मजबूत सहयोगी और शुभचिंतक अपनी अपनी सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे हैं।

(लेखक के अपने विचार हैं)

नागरिक-सैन्य सहयोग की बढ़ी अहमियत

अजय कुमार

सरकार के लिए नागरिक एवं सैन्य अंग दोनों ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों अंगों के बीच आपसी जुड़ाव और सहयोग जैसे पहलू काफी अहम हैं। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में नागरिक-सैन्य सहयोग अलग-अलग रूपों में दिखते हैं।

स्वेच्छाचारी या अधिनायकवादी शासन में सेना का दबदबा दिखता है जबकि लोकतांत्रिक प्रणाली में नियंत्रण लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के हाथ में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नागरिक-सैन्य संबंधों का विकास शुरू हुआ और कमांड आधारित ढांचे से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थागत तालमेल आधारित प्रणाली की तरफ कदम बढ़ाया गया। 1957 में आई नागरिक-सैन्य संबंधों पर सैमुअल

हंटिंगटन की चर्चित किताब में लोकतांत्रिक प्रणाली में सैन्य स्वायत्तता की वकालत की गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन में इसी बात का जिक्र किया था और नागरिकों के नियंत्रण वाली प्रणाली में पेशेवर सेना की भूमिका पर जोर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 100 से अधिक देश स्वतंत्र हो चुके है मगर उनमें 70 से अधिक देश सैन्य शासन के अनुभव से गुजर चुके हैं। इसके उलट भारत में चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक सरकार एवं नागरिक नियंत्रण के साथ नागरिक-सैन्य संबंधों में संयोजन स्थापित करने में सफलता हासिल हुई है। किसी प्राकृतिक आपदा के समय या कानून एवं व्यवस्था के पालन के उद्देश्य से नागरिक प्राधिकरणों को मदद करने में नागरिक-सैन्य नागरिक तालमेल भारत में उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है।

नागरिक-सैन्य के मिले-जुले प्रयास पूरी रफ्तार से होते हैं और उनमें , अनुशासन के साथ ही सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु) से जुड़ी आपात स्थितियों जैसी क्षमताओं में गजब का सामंजस्य नजर आता है। आपदा के समय मदद पहुंचाने और बचाव कार्यों में यह बात विशेष रूप से नजर आती है। उनकी भूमिका सीमा से परे भी दिखती है जब वे संकट के समय अपने लोगों को बाहर निकालते हैं और क्षेत्रीय मानवीय प्रयासों में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर साझा प्रतिबद्धता के बावजूद नागरिक और सैन्य अंगों के बीच अंतर साफ दिख रहा है। सेना के अधिकारी व्यक्तिगत विचारों से अलग कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली, मूल्य पदानुक्रम, रफ्तार और एकरूपता के लिहाज से प्रशिक्षित होते हैं। यह बात सिविल सेवाओं में नहीं दिखती है। सेना में कार्यकाल कम होने से निरंतरता सीमित हो जाती है जबकि नागरिक सेवाओं में कार्यकाल अधिक लंबे होते हैं। खरीद सौदों से जुड़े क्षेत्रों में भी नागरिक और सैन्य अंगों के बीच मतभेद साफ नजर आता है। सेना संचालन एवं ठोस प्रदर्शन को अधिक तवज्जो देती है जबकि जबकि रक्षा मंत्रालय कम बोली देने वाली इकाइयों का चयन करता है। जब रक्षा प्रतिष्ठानों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण की बात आती है तो वहां भी आपसी तालमेल का अभाव दिखता है।

जमीन, स्पेक्ट्रम और एयरस्पेस को लेकर भी मतभेद दिखते हैं। सेना

उन्हें अपनी तैयारियों के लिए अहम मानती हैं जबकि नागरिक प्राधिकरण उन्हें वृहद विकास के लिए राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में देखते हैं। तीनों सेनाओं में लॉजिस्टिक, प्रशिक्षण एवं बुनियादी ढांचे के दोहराव को संयुक्त योजना के अभाव के रूप में देखा जा सकता है। इसे सरकार अक्षमता के रूप में देखती है। इन सभी कारणों से नागरिक-सैन्य संबंधों में पिछले कुछ वर्षों से विश्वास का अभाव बढ़ गया है।

वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान आपस में संयोजन का गंभीर अभाव दिखा था। इस युद्ध के बाद संयुक्त योजना तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय (आईडीएस) स्थापित किया गया। इसके साथ ही खुफिया जानकारियां साझा करने के लिए रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआ-ईए) की स्थापना भी की गई। कारगिल युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेवाओं का अंडमान निकोबार कमांड स्थापित किया गया। उसी समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का नया पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया गया था मगर उस समय इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका।

राष्ट्रीय सलाहकार की नियुक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अधिक ताकत दिए जाने के बाद रणनीतिक नीति निर्धारण में तेजी आई। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन ने तकनीकी खुफिया क्षमताओं को मजबूत बनाया। सीमावर्ती इलाकों के विकास पर पहले अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था मगर यह रवैया बदल कर सीमा प्रबंधन विभाग की शुरूआत की गई। इसके साथ ही सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट जरूरतें पूरी करने के लिए एक नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) की शुरूआत की गई।

इन सुधारों से सुरक्षा को लेकर भारत का दृष्टिकोण बदल गया। इन सुधारों के माध्यम से आधुनिकीकरण, तकनीक के इस्तेमाल पर जोर और सीमा के विकास पर अधिक ध्यान दिया। मगर इन सुधारों में नागरिक-सेना के बीच आपसी विश्वास में कमी दूर करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि, आईडीएस, डीआईए और अंडमान निकोबार कमांड कमजोर संवैधानिक समर्थन और सीमित परिचालन प्रभावों के कारण अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं। डीपीपी भी रक्षा उपकरणों की खरीदारी में तेजी लाने में सफल नहीं हो पाई। वर्ष 2019 में सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के गठन के बाद नागरिक-सैन्य संबंधों में सुधारों के दूसरे चरण की शुरूआत हो गई। सीडीएस, डीएमए के सचिव और रक्षा मंत्रालय के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं और तीनों सशस्त्र सेनाओं के काम-काज पर नजर रखते हैं। इनके अलावा संचालन, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण एवं मदद में तालमेल

को भी बढ़ावा देते हैं।

डीएमए के गठन के बाद रक्षा विभाग से कुछ कार्य दूसरे विभागों को सौंपने की शुरूआत आसान हो गई। वर्ष 2023 में इस जुड़ाव को अंतर-सेवा संगठन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक समर्थन भी मिल गया। 2019 में किए गए सुधारों से प्रशिक्षण एवं लॉजिस्टिक में जुड़ाव में काफी मदद मिली। थिएटर कमांड स्थापित करने पर भी बात चल रही है जो आगे होने वाले सुधारों की तरफ इशारा कर रहा है।

वर्ष 2021 में भू-स्थैतिक सूचनाओं और ड्रोन से संबंधित नीतियों से रक्षा पाबंदियों में काफी कमी आ गई। तेल की खोज के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र खोले गए। सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का काम तेज हो गया और सेना नियंत्रित हवाई क्षेत्र नागरिक इस्तेमाल में लाए जाने लगे। अब जमीन स्थानांतरण के कार्य अधिक आसानी से हो जाते हैं। पूंजीगत व्यय में भी तेजी आई है जिससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। अग्निवीर योजना के जरिये भर्ती एवं प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी सुधार अभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं मगर उनके दूरगामी प्रभाव अभी से दिखने लगे हैं।

आधुनिक युद्ध कौशल के कारण के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिक-सैन्य संबंधों में आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना और अहम हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण के सुधारों का उद्देश्य और अधिक एकीकरण है। साइबर हमले, भ्रामक सूचनाएं और छद्म युद्ध के कारण नागरिक-सैन्य उपायों की जरूरत और बढ़ गई है। दोहरे इस्तेमाल यानी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए बन रही तकनीक जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रणाली के क्षेत्र में त्वरित विकास के बाद असैन्य उद्यमियों के साथ सहयोग करने की जरूरत बढ़ गई है।

मौजूदा समय में चीन का बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव, चीन और रूस के बीच बढ़ते आपसी संबंध, वैश्वीकरण के घटते प्रभाव, अति महत्त्वपूर्ण खनिजों पर सभी देशों के ध्यान, साइबर हमले जैसी चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। 21वीं शताब्दी के इन पेचीदा जोखिमों से निपटने में असैनिक और सैन्य दोनों अंगों के बीच आपसी सहयोग और हरेक मोर्चे पर उनके बीच तालमेल स्थापित करने की जरूरत काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए नागरिक-सैन्य संबंधों में सुधारों को और प्राथमिकता देना होगी।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव और आईआईटी कानपुर में अतिथि प्राध्यापक हैं।)

भारत-पाक तनाव

पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी

निमिष कुमार

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न सैन्य टकराव को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को संसद की स्थाई समिति को जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि यह ब्रीफिंग सोमवार 19 मई को होगी।

विदेश सचिव मिस्री समिति को 'भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा विदेश नीति घटनाक्रम' पर जानकारी देंगे। यह बैठक उस पृष्ठभूमि में हो रही है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई दिनों तक सैन्य झड़पें होती रहीं।

हालांकि, 10 मई को दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति जताई।

मिस्री पहले भी समिति को बांग्लादेश, कनाडा और अन्य पड़ोसी देशों से संबंधित विदेश नीति मामलों पर नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं।

भारत की संसद की विदेश मामले पर स्थायी समिति , विदेश मंत्रालय की नीतियों और कार्यों की निगरानी करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। समिति की अध्यक्षता वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कर रहे हैं।

यह समिति विदेश मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों और विदेश नीति से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है। समिति के सदस्य विदेश मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और मंत्रालय को सुझाव प्रदान करते हैं। समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। और विदेश सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं।

इस समिति में लोकसभा सदस्य (21):

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्रीमती डी. के. अरुणा
3. श्री विजय बघेल
4. श्री मितेश पटेल बकाभाई
5. श्री अभिषेक बनर्जी
6. श्री अरुण गोविल
7. श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा
8. श्री नवीन जिंदल
9. श्री नवास कानी के
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला
12. श्री असदुद्दीन ओवैसी
13. श्री सनातन पांडे
14. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
15. श्री रवि शंकर प्रसाद
16. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
17. श्रीमती अपराजिता सारंगी
18. श्री अरविंद गणपत सावंत
19. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
20. सुश्री बंसुरी स्वराज
21. श्री अक्षय यादव

राज्यसभा सदस्य (10):

22. डॉ. जॉन ब्रिटास
23. श्रीमती किरण चौधरी
24. श्रीमती सागरिका घोष
25. डॉ. के. लक्ष्मण
26. सुश्री कविता पटिदार
27. श्री सतनाम सिंह संधू
28. श्री राजीव शुक्ला
29. श्री ए. डी. सिंह
30. श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह
31. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

क्या सचमुच लक्ष्य हासिल हुआ?

अजीत द्विवेदी

वैसे तो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम नरसंहार, छह-सात मई की दरम्यानी रात को शुरू हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' और 10 मई की शाम को हुए सीजफायर को लेकर कई सवाल हैं। कई ऐसे पहलू हैं, जिनके बारे में स्पष्टता नहीं है।

सेना की लगातार हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनके बारे में नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच भारत को अपना लक्ष्य हासिल हो गया? जिस मकसद से 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू हुआ था क्या वह पूरा हो गया?

क्या पहलगाम में मारे गए बेकसूर भारतीय नागरिकों की मौत का बदला सचमुच ले लिया गया? यह सूत्र वाक्य बार बार बोला जा रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य पूरा हो गया है। सवाल है कि क्या लक्ष्य था?

क्या भारत की सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय या प्रशिक्षण शिविर की इमारत को मिसाइल मार कर ध्वस्त कर देना था? अगर इतना ही लक्ष्य था तब तो कह सकते हैं कि यह लक्ष्य काफी हद तक हासिल हो गया।

लेकिन तब बड़ा सवाल है कि क्या भारत सरकार और युद्ध के रणनीतिकार बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, मुजफ्फराबाद आदि शहरों में स्थित आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय या प्रशिक्षण शिविर की इमारतों को ही आतंकवाद का नेटवर्क मानते हैं? और उन इमारतों को ध्वस्त करके समझ रहे हैं कि आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया?

पहलगाम हमले के बाद भारत का तात्कालिक लक्ष्य 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर 26 हिंदुओं की हत्या कर देने वाले पांच आतकंवादियों की पहचान करके उनको सजा देने का था। सजा देने का मतलब है कि या तो मुठभेड़ में वे मारे जाते या पकड़ कर कानून के कठघरे में खड़ा किए जाते। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हो पाया।

पांचों आतंकवादी 26 लोगों के नरसंहार के बाद गायब हो गए। खुफिया और सुरक्षा मामलों की जितनी बड़ी विफलता पहलगाम में हुई थी उससे बड़ी विफलता आतंकवादियों का पता नहीं लगा पाना है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवान तैनात हैं।

फिर भी आतंकवादी 20 मिनट तक लोगों से धर्म पूछ कर और कपड़े उतार कर धर्म की पहचान करके उनकी हत्या करते रहे और एक भी सुरक्षाकर्मी इतनी देर तक पहलगाम की बैसरन घाटी में नहीं पहुंचा। आतंकवादियों के खिलाफ एक भी गोली नहीं चली। होना तो यह चाहिए था कि 20 मिनट की उनकी फायरिंग के दौरान सुरक्षा बल उनको चारों तरफ से घेर लेते।

लेकिन इसका उलटा हुआ। उन्होंने 20 मिनट तक मौत का खूनी खेल खेला और फिर जंगलों में लापता हो गए। 20 दिन बाद तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है। पहलगाम कांड के बाद बताया गया कि हाशिम मूसा इसका मास्टरमाइंड है, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। इस मास्टरमाइंड का भी कोई अता पता नहीं है।

लश्कर का संस्थापक हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का सलाहुद्दीन पाकिस्तान की किसी पनाहगाह में सुरक्षित हैं। सो, पहलगाम कांड को अंजाम देने वाले आतंकवादी, उनका हैंडलर और उनके आका किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

पहलगाम कांड के बाद एक दीर्घकालिक लक्ष्य था आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने का। इसके लिए ही 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू हुआ था। इस सैन्य अभियान के तहत छह और सात मई की दरम्यानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमीं पर स्थित आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया।

इस हमले में जैश ए मोहम्मद के चार, लश्कर ए तैयबा के तीन और हिजबुल मुजाहिदीन के दो ठिकाने नष्ट किए गए। इसके बाद अगले चार

दिन तक जो हुआ वह पाकिस्तान की ओर से हुई प्रतिक्रिया का जवाब देने की कार्रवाई थी। उसमें पाकिस्तान को जितना भी नुकसान हुआ हो उससे भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के पूरा होने का कोई लेना देना नहीं है।

अगर पाकिस्तान का रहीम यार खान या नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हुआ है तो उससे आतंकवाद का नेटवर्क कमजोर पड़ जाएगा यह कोई ऐसा ही व्यक्ति सोच सकता है, जिसकी आंखों पर परदा और अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ है। आतंकवाद का नेटवर्क एक जटिल संरचना है, जिसके खिलाफ दुनिया भर के देश और एजेंसियां काम कर रही हैं।

भारत अगर आतकंवाद से सर्वाधित पीड़ित देश है तो इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर इतना कहा जा सकता है कि इस नेटवर्क को सिर्फ खरोंच लगाई गई है। उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका है।

पाकिस्तान ने माना है कि 30 साल से वह आतंकवादियों को पाल पोस रहा है और उनको प्रशिक्षण दे रहा है। ऐसा वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर करता रहा है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सामरिक जानकार भी मानते हैं कि भारत के काउंटरवेट के तौर पर पाकिस्तान को मदद करने का काम अमेरिका करता रहा है।

भारत को हजार घाव देने की रणनीति पाकिस्तान की अपनी है लेकिन अलग अलग कारणों से अमेरिका, रूस और चीन भी इसमें उसकी मदद करते रहे हैं। यह अनायास नहीं है कि जम्मू कश्मीर में मारे जाने वाले आतंकवादियों के पास से अमेरिकी और चीनी हथियार मिलते हैं।

हो सकता है कि ये देश सीधे उनको हथियार नहीं मुहैया कराते हों लेकिन पाकिस्तान के जरिए ही अगर उनका हथियार आतंकवादियों तक पहुंच रहा है तो क्या उस पर काबू करने का काम उनका नहीं है? लेकिन ये देश इस पर ध्यान नहीं देते हैं।

जब तक आतंकवादियों को मिलने वाली सैन्य मदद, हथियार और प्रशिक्षण का ढांचा नष्ट नहीं होता है और सप्लाई चेन नहीं बंद होती है तब तक उसकी एकाध इमारत नष्ट करने या सौ पचास आतंकवादियों को मार देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा।

इसके लिए पहली जरुरत यह है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए और दुनिया के देशों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वे पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्टरी मान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

लेकिन इस लक्ष्य में भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक इजराइल को छोड़ कर किसी ने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के बेकसूर नागरिकों की हत्या की फिर भी चीन ने उसे सदाबहार दोस्त बता कर उसका समर्थन किया और कहा कि वह उसकी संप्रुभता की रक्षा करेगा।

तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब चीन, अमेरिका और तुर्की के हथियार से दिया। अमेरिका ने आगे बढ़ कर सीजफायर कराया तो सऊदी अरब, ईरान जैसे देश सीजफायर कराने के लिए आगे आए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की सैन्य कार्रवाई के बीच पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर यानी 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया। इस तरह पाकिस्तान कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक किसी भी मोर्चे पर अलग थलग नहीं हुआ, बल्कि नई विश्व व्यवस्था में वह ज्यादा बेहतर ढंग से समायोजित हो गया।

फिर भारत क्यों सीजफायर पर सहमत हुआ? भारत कोई गुरिल्ला वॉर करने वाला देश नहीं है जो यह कहा जाए कि चार दिन की लड़ाई में उसने कई इमारतें उड़ा दीं और कई आतंकवादियों को मार दिया इसलिए अब उसको पीछे हट जाना चाहिए।

भारत को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी है। जैसे हमास को खत्म करने के लिए इजराइल लड़ रहा है वैसे ही भारत को लड़ना है आतंकवाद का ढांचा और पाकिस्तान के छद्म युद्ध को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां भारत प्रतीकात्मक कार्रवाई कर रहा है।

पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की प्रतीकात्मक कार्रवाई हुई। फिर 2019 में एयर स्ट्राइक की प्रतीकात्मक कार्रवाई हुई और अब 2025 पहलगाम कांड के बाद ह्यऑपरेशन सिंदूरह्न की प्रतीकात्मक कार्रवाई हुई है।

इससे भारत का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और न कुछ हासिल हुआ। उलटे यह संदेश गया कि अमेरिका ने भारत व पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। यह भी मैसेज हुआ कि जम्मू कश्मीर के दोपक्षीय मामला होने का स्थापित सिद्धांत समाप्त हो गया और अमेरिका के रूप में तीसरा पक्ष उसकी मध्यस्थता कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने यह मैसेज बनवा दिया। उधर पाकिस्तान को चीन, तुर्की जैसे देशों का खुला समर्थन प्राप्त हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने का बयान दिया। इसका मतलब है कि अगर भारत ने पीओके को हासिल करने की कोई कार्रवाई की तो उसे चीन से भी भिड़ना होगा।

क्या पाक को भारत की ताकत पर अब भी कोई संशय है?

रामस्वरूप रावतसरे

रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय के जनरल पाकिस्तान को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। जनरल असीम मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने जो रास्ता पकड़ा है, उसकी मंजिल सिर्फ तबाही है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बाद लगा कि पाकिस्तान की सरकार भी तनाव बढ़ाने को तैयार नहीं है लेकिन पिछले दो दिनों से जो कुछ हो रहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तानी जनरलों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने आतंकी ठिकानों के सफाए का बदला लेने की ठान ली और पाकिस्तान सरकार को अपने इशारे पर चलने पर मजबूर कर दिया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद पाकिस्तानी सरकार की प्रतिक्रिया और उसके बाद पाकिस्तानी फौज की करतूत में जमीन-आसमान का अंतर नजर आ रहा है।

22 अप्रैल को पहलगाम हमले में पाकिस्तान में पले-बढ़े आतंकियों का हाथ है। उसके बाद से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर पहले युद्ध-विराम का उल्लंघन शुरू किया। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली लगातार दो रातों 7-8 और 8-9 मई को ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशें की हैं। भारतीय सशस्त्र सेना उसकी हर हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो रहा है क्योंकि भारत के पास कहीं बेहतर हवाई सुरक्षा प्रणाली है। भारत ड्रोन बनाने का केंद्र बन रहा है जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। भारत के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा संसाधन हैं। चीन भी पाकिस्तान के इस लफड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसलिए, पाकिस्तान एक हारने वाला खेल खेल रहा है। भारत को आर्थिक और सैन्य तौर पर बड़ी बढ़त हासिल है। भारत लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर हरगिज नहीं।

ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला बयान इसी ओर इशारा कर रहा था कि वह कोई भड़काऊ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा जबकि, पहले वाले इनके बयान काफी भड़कीले रहे थे लेकिन मुनीर की सेना अपनी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और शहबाज शरीफ की सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है और सेना जो कहती है, वही होता है।

दुनिया में भारत आज कहां खड़ा है, इसे स्वीकार करने के लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है। जब भारतीय सशस्त्र सेना लाहौर में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानें पर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही थी, तब इस्लामिक सहयोग संगठन के दो महत्वपूर्ण देशों के मंत्रियों की विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में मेजबानी कर रहे थे। ये देश हैं सऊदी अरब और ईरान। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और सऊदी अरब के मंत्री आदिल अल-जुबेर से अलग-अलग बैठकें कीं। ईरान तो पाकिस्तान का पड़ोसी भी है। भारत ने दोनों मुस्लिम देशों के मंत्रियों को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जानकारी दी। भारत ने बताया कि ये ऑपरेशन, पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में किए गए आतंकी हमलों के बाद किया गया। सऊदी अरब और ईरान दोनों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। विदेश मंत्री ने अपने मेहमानों को समझाया कि भारत की प्रतिक्रिया ''नपी-तुली, सटीक और किसी तरह से भड़काने वाली नहीं'' थी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे स्थिति और बिगड़े।

पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बेकाबू न हो, इसकी भी जिम्मेदारी उसी की है, यानी अब जो कुछ हो रहा है, उसे रोकने की पहल पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी और अमेरिका भी बिना कहे, इसी ओर संकेत दे रहा है। भारत ने हमेशा सीमा पार से होने वाली हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी देता रहेगा। पाकिस्तान को यह याद रखना जरूरी है कि तनाव की शुरूआत उसी ने की है। भारत ने सिर्फ आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ एक सटीक और लक्षित कार्रवाई की; और भारत ने दुनिया भर के देशों को अपना रुख स्पष्ट रूप से बता दिया है और दुनिया भर से मिल रही प्रतिक्रियाएं भी भारत के रुख की पुष्टि कर रही हैं।

इसके बावजूद, पाकिस्तान की फौज ने ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश करके और उकसाने की कोशिश की। हालांकि, भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें टॉप-ऑफ-द-लाइन एस-400 भी शामिल है, ने उन सभी को हवा में ही मार गिराया है यानी इस मामले में पाकिस्तान फिर से भारत के सामने बौना साबित हुआ है। पाकिस्तान को 8 और 9 अप्रैल की रात को भी पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सशस्त्र बलों से इसी तरह का करारा जवाब मिला है। दरअसल, 2019 में बालाकोट के बाद से भारत ने अत्याधुनिक हवाई रक्षा ग्रिड बनाने पर काफी पैसा खर्च किया है। चाहे वह रूस से खरीदा गया एस-400 हो या फ्रांस से मंगवाए गए अचूक राफेल लड़ाकू विमान भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को लगभग अभेद्य बना दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बुधवार और गुरुवार की रात अंतरराष्ट्रीय सीमा

(आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर कई जगहों पर भारतीय सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पास भारत की बराबरी का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की जिसके जवाब में भारतीय सेना ने इजरायल में बने हारोप और हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी हवाई रक्षा प्रणालियों को भेद दिया और लाहौर में हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया।

ड्रोन भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत ड्रोन बनाने का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है जबकि इस्लामाबाद के पास ऐसा कोई औद्योगिक आधार नहीं है और वह शायद सिर्फ तुर्की और चीन के ड्रोन पर ही निर्भर रह सकता है। इन सब बातों को देखते हुए, इस्लामाबाद के लिए नई दिल्ली के साथ लंबी लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं। अगर वह तनाव बढ़ाता है, तो उसके पास गोला-बारूद भी खत्म हो सकता है। भारत के पास गोला-बारूद का मजबूत भंडार है, इसलिए उसे ऐसी कोई चिंता नहीं है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान का 'आयरन-ब्रदर' चीन भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, जो पाकिस्तान को बिना कुछ कहे सब कुछ बता रहा है।

इसलिए, पाकिस्तान एक हारने वाला खेल खेल रहा है। भारत की आर्थिक शक्ति, संघर्ष के प्रभाव को झेलने की क्षमता और कहीं ज्यादा मजबूत सैन्य ताकत उसे स्पष्ट बढ़त दिलाती है। भारत लगातार तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जनरलों को अब यह समझ जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। उन्हें आत्महत्या का रास्ता छोड़ देना चाहिए।

पहलगाम में 26 निर्दाष जिंदगियों को निगलने वाले आतंकी हमले के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त और बुलंद है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति भी तेज कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल दुनियाभर के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में पल रहे आतंक के सच को हर देश तक पहुंचाया जाए। यूएनएससी के सदस्य देशों से लेकर बड़े मुल्कों के शीर्ष अधिकारियों तक, भारत ने सभी को इस ऑपरेशन की जानकारी दी है।

बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक विशेष कूटनीतिक मिशन में जुट गए। डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई, जापान और फ्रांस के शीर्ष नेताओं व सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर ऑपरेशन की कार्रवाई को स्पष्ट किया जिसमें केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, न कि पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठानों को। दूसरी ओर, जयशंकर ने वैश्विक मंच पर भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को रेखांकित करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया। यह समन्वित प्रयास भारत की स्थिति को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए था।

सुबह के सन्नाटे में, जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया। 1.05 बजे से 1.30 बजे तक, सिर्फ 25 मिनट में, नौ आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के 90 से ज्यादा आतंकी इस कार्रवाई में ढेर हो गए। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि मानो भारत ने आतंक की रीढ़ ही तोड़ दी! विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे 'बढ़ावा नहीं, बल्कि जवाब' करार दिया। उन्होंने साफ कहा, ''हमने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसका एकमात्र मकसद था, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना।''

दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 विदेशी राजदूतों के साथ एक हाई-प्रोफाइल ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन की पूरी कहानी बयां की। ब्रिटेन के एक सवाल पर कि क्या भारत ने मस्जिदों को निशाना बनाया, मिस्री ने दो टूक जवाब दिया, ''हमने एक ऐसे परिसर को निशाना बनाया, जहां आतंकी कैंप चल रहा था।'' यह जवाब न सिर्फ भारत की पारदर्शिता दिखाता है, बल्कि उसकी सटीकता भी दिखाता है।

पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के हमलों में आम नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मिस्री ने कहा, ''हमने ठिकानों को इतनी सावधानी से चुना कि कोई नागरिक या गैर-सैन्य ढांचा प्रभावित न हो।'' विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी ने भी यही भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन में नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह भारत की सैन्य ताकत के साथ-साथ उसकी नैतिकता को भी दर्शाता है।

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है - आतंकवाद को पनाह देना अब महंगा सौदा साबित होगा। भारत ने बार-बार कहा है कि वह अपनी जमीन पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कार्रवाई ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंक के खिलाफ उसकी अग्रणी भूमिका को भी मजबूत किया।

भारत अब इस ऑपरेशन को वैश्विक मंच पर ले जाकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विदेश मंत्रालय और एनएसए की गहन कूटनीतिक कोशिशों से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। यूएनएससी के सदस्यों और बड़े देशों के साथ भारत की बातचीत इस बात का सबूत है कि वह आतंक के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।

ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर पाकिस्तान ने आतंक को समर्थन जारी रखा तो भारत और सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।

युद्धविराम के पीछे

डॉ.सत्यवान सौरभ

युद्धविराम पर चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश का प्रमुख उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होता है। जब कोई युद्धविराम होता है, तो उसके पीछे केवल सैन्य कारण नहीं, बल्कि कई कूटनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय कारक भी काम कर रहे होते हैं।

कुछ आलोचक पिछले कुछ दिनों से युद्धविराम के फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि लोग भावनात्मक रूप से आहत हों, खासकर जब हाल ही में पहलगाम में हुए हमले जैसे घटनाक्रम सामने आए हों। लेकिन क्या यह उचित है कि केवल आवेश में आकर किसी निर्णय की निंदा की जाए? आइए, इस पूरी स्थिति को थोड़े गहराई से समझते हैं।

1. परमाणु हमले का संभावित खतराः पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में लगातार भूकंप जैसी गतिविधियों की खबरें आईं। क्या यह केवल भूगर्भीय घटना है, या उस कायरता का प्रतीक, जो निराशा में अपना अंतिम दांव चलने को मजबूर है? अगर यह सत्य है, तो यह संकेत है कि पाकिस्तान, भारत के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी में था। यह केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं, बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष है, जो मानवता की नींव को हिला सकता है।

2. मिसाइल परीक्षण और सिरसा घटनाः 9 मई की रात को हरियाणा के सिरसा के ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। यह केवल एक धातु का गोला नहीं, बल्कि भय और बबार्दी का संदेश था। क्या यह संभव है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल के परीक्षण की कोशिश की थी, जो केवल विनाश की गूंज पैदा कर सकता था?

3. अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिः ऐसे समय में केवल तलवारें खींचना ही पर्याप्त नहीं होता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे पर भारत से संपर्क किया, और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए युद्धविराम की सलाह दी। यह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि सभ्यताओं के संघर्ष से बचने की एक गहरी कूटनीतिक चाल थी।

4. भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाईः पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकी कैंपों पर हमला कर सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह दशार्ता है कि भारत ने अपने घावों का जवाब दिया, लेकिन साथ ही उसने पूरी दुनिया को विनाश की आग में झोंकने से भी रोका।

5. संतुलित रणनीति का महत्वः भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता। केवल आवेश में आकर परमाणु युद्ध की ओर बढ़ना आत्मघाती हो सकता है। इसलिए, मोदी सरकार ने एक संतुलित और रणनीतिक कदम उठाया, जो केवल युद्ध का समाधान नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा का प्रण था।

निष्कर्षः युद्धविराम का निर्णय केवल कायरता या दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ, मानवीय संवेदना और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। यह निर्णय केवल भारत की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में केवल व्यक्तिगत आलोचना से परे जाकर व्यापक दृष्टिकोण से इस निर्णय का मूल्यांकन करना चाहिए।

अगले समय में भी ऐसे कई मौके आएंगे जब दुश्मनों का निर्णायक अंत किया जा सकेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब हम संयम, समझ और रणनीति के साथ आगे बढ़ें।

अजीत द्विवेदी
वरिष्ठ स्तंभकार

सीजफायर सियासत शुरू

'लोग कभी भी इतना झूठ नहीं बोलते, जितना शिकार के बाद, युद्ध के दौरान और चुनाव से पहले बोलते हैं'। यह उक्ति ओटो वॉन बिस्मार्क की बताई जाती है। हालांकि कई जानकार इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी जर्मन ने यह बात कही थी। सोचें, कितनी सही बात है! अभी हम लोगों ने एक बेहद संक्षिप्त युद्ध देखा। आजाद भारत के इतिहास का सबसे छोटा। महज चार दिन का। इससे पहले पाकिस्तान से 1965 में 22 दिन का युद्ध हुआ था। 1971 में भी युद्ध 13 दिन चला था और कारगिल की लड़ाई तो 85 दिन चली थी। 'ऑपरेशन सिंदूर' महज चार दिन यानी 96 घंटे चला। लेकिन दावा किया जा रहा है कि, 'जिन्होंने भारत की महिलाओं का सिंदूर मिटाया, उनको मिटा दिया गया'। चार दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई की शाम को सीजफायर हुआ और 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने आए उससे पहले उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई थी और मंगलवार, 13 मई से पूरे

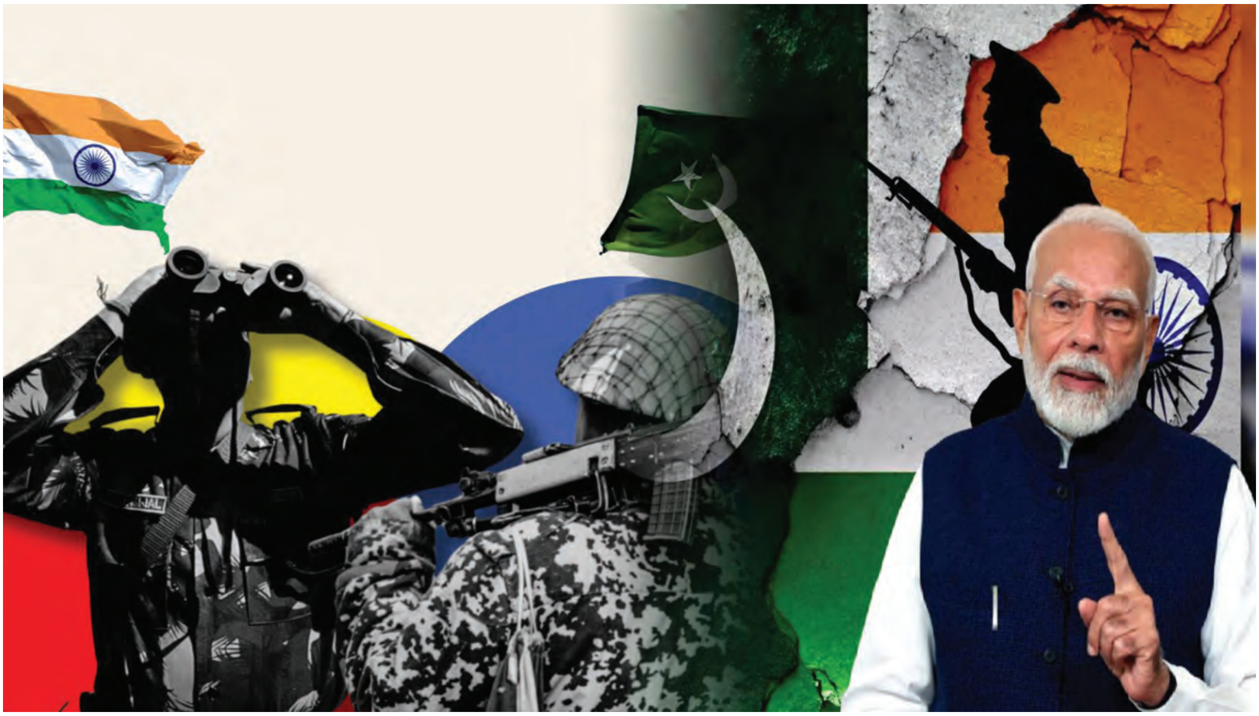

देश में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला हुआ था। भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने बैठ कर विचार किया था कि इस यात्रा से क्या नैरेटिव तय करना है। उसी नैरेटिव को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वर दिया। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले लगातार दो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने हर बात देश को बता दी थी। उन्होंने इस सैन्य अभियान से जुड़े बारीक से बारीक तथ्य भी देश के सामने रख दिए थे। लेकिन वह एक पेशेवर सेना के नजरिए से की गई प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें राजनीति का तत्व नहीं था या सोशल नैरेटिव क्रिएट करने की सोच नहीं थी। उस कमी को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पूरा किया। प्रधानमंत्री ने एक व्यापक सोशल व पोलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया, जिसे लेकर उनकी पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। अगले 10 दिन यानी 23 मई तक देश भर में प्रधानमंत्री की बातों को पहुंचाया जाएगा कि कैसे भारत ने महिलाओं का सिंदूर मिटाने वालों को मिटा दिया। कैसे आतंकवाद का ढांचा तहस नहस कर दिया गया। कैसे भारत ने तय किया कि वह पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनेगा। कैसे चार दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और गुहार लगाने लगा। आदि-आदि।

यह दुनिया के इतिहास में संभवतः पहली बार है कि युद्ध लड़ने वाले दोनों देश जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन 'बुनयान अल मरसूस' की सफलता का दावा किया जा रहा है और 'यौम ए तशक्कुर' मनाया जा रहा है तो भारत में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के बाद सिर्फ भारत में जश्न मनाया गया था। एक पुरानी कहावत है, 'हर बात पर यकीन मत करो। हर कहानी के तीन पहलू होते है; एक तुम्हारा, एक उनका और एक सचा-ई'।

बहरहाल, भारत में इस संक्षिप्त युद्ध के दौरान ही राजनीति शुरू हो गई थी। ऐन युद्ध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कांग्रेस की सरकारों के समय हुए आतंकवादी हमलों खास कर मुंबई का हमला और उसके बाद सरकार की चुप्पी दिखाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीरों और वीडियो के साथ इसे बनाया गया था और कहा गया था कि अब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार चुप नहीं रहती है, बल्कि ईट का जवाब पत्थर से देती है। भारत अब नया देश है, जो घर में घुस कर मारता है। सोचें, जिस समय सेना युद्ध लड़ रही थी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी थीं उस समय सत्तारूढ़ दल ने एक वीडिया जारी करके युद्ध का श्रेय लेने की राजनीति की। अनेक तटस्थ और निरपेक्ष सोच रखने वालों ने भी कहा कि भाजपा के इस प्रचार अभियान की टाइमिंग ठीक

नहीं है। लेकिन राजनीति जब जंग का रूप ले लेती है तो उसमें सही और गलत का आकलन किसी नैतिक पैमाने पर नहीं होता है, बल्कि सफलता के आधार पर होता है।

इसके बाद जब अचानक सीजफायर हुआ तो सभी स्तब्ध रह गए। विपक्षी पार्टियों और राजनीति से निरपेक्ष लोगों ने भी याद दिलाया कि कैसे भाजपा के नेता कहते रहे थे कि सेना युद्ध जीत रही हो तो युद्धविराम नहीं किया जाता है और खुद सेना को रोक कर सीजफायर कर दिया! टाइमिंग और उपलब्धि दोनों लिहाज से सीजफायर का नैरेटिव भाजपा के खिलाफ बन गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि सीजफायर की घोषणा किसी तीसरे देश ने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि उन्होंने सीजफायर कराया है। इस पर राजनीति करने का मौका कांग्रेस को मिला। उसने पार्टी मुख्यालय के आगे इंदिरा गांधी का बड़ा होर्डिंग लगवाया और लिखा, 'इंदिरा होना आसान नहीं है'। असल में इंदिरा गांधी को भी 1971 में अमेरिका ने युद्ध रोकने को कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखी थी उसकी भी कॉपी कांग्रेस ने जारी की। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने 1971 की लड़ाई के अंत में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और 90 हजार से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में साझा कीं। हालांकि कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने यह कह कर इस नैरेटिव को कमजोर किया कि 1971 की स्थिति अलग थीं और आज की स्थिति अलग है। उन्होंने जो कहा वह उनकी निजी और केरल विधानसभा चुनाव की राजनीति से जुड़ा है।

अगर ट्रंप सीजफायर को लेकर बार बार बयान नहीं देते और उसका श्रेय नहीं लेते तो भाजपा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ट्रंप की वजह से भाजपा को थोड़ी समस्या हुई। तभी राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजफायर को लेकर अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि चार दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के सामने गुहार लगाने लगा। मोदी ने आगे कहा कि चूंकि तब तक भारत अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था और आतंकवाद के ढांचे को नष्ट कर चुका था इसलिए उसने सीजफायर पर सहमति दे दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को सैन्य और कूटनीतिक दोनों सफलता की कहानी बताई। अब यही कहानी भाजपा के नेता देश भर में सुनाएंगे। तिरंगा यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वे भारतीय सेना के शौर्य, नए भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व की गाथा देश के लोगों को सुनाएंगे। देशभक्ति का उबाल लाने का प्रयास करेंगे। इस साल के अंत में बिहार में और अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी में विधानसभा के चुनाव हैं। वहां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की महान विजय की कहानियां सुनाई जाएंगी। दूसरी ओर कांग्रेस दुविधा में है क्योंकि उसकी सहयोगी पार्टियां इस महान विजय गाथा को चुनौती देने के मूड में नहीं दिख रही हैं। उनकी कोशिश इस उफान को चुपचाप उतर जाने देने की है। हालांकि भाजपा आसानी से ऐसा होने देगी, इसकी उम्मीद कम है।

आरटीआई प्रसंग
मुश्किल में बेगूसराय डाक अधीक्षक
सुनवाई से गैरहाजिरी पर विभागीय कार्रवाई का आदेश

केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक अहम फैसले में आर.टी.आई. की सुनवाई से गैरहाजिर रहने के मामले में बेगूसराय प्रमंडल के डाक अधीक्षक श्रीमती अर्चना कुमारी के विरुद्ध आरटीआई अधिनियम की धारा- 20 के तहत मामले में कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए को लेकर एक लिखित प्रस्तुतियां 30 दिनों के भीतर आयोग तक पहुंच जाने का आदेश दिया है। अन्यथा मामले में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सीपीआईओ को इस आदेश की प्रति संबंधित विभागीय प्रथम अपील प्राधिकारी (एफ ए ए) को भेजने का निर्देश भी दिया है।

मालूम हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा-20 में अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के आरोप में राज्य एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभाग में लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह भी विदित हो कि बेगूसराय प्रमंडल की डाक अधीक्षक श्रीमती अर्चना कुमारी केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारी (सीपीआईओ) भी हैं।

अपीलार्थी शोकहारा निवासी आर.टी.आई. एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता ने बताया की प्राप्त आदेश अनुसार गत 7 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्रीमती आनंदी रामलिंगम की एकल पीठ की बेगूसराय के एनआइसी स्टूडियो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, जिसमें उनका डाक विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों का 9 द्वितीय अपील अर्जियों की सुनवाई की गई थी। उस सुनवाई में बेगूसराय प्रमंडल के डाक अधीक्षक -सह-सीपीआईओ श्रीमती अर्चना कुमारी स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने कार्यालय के डाक सहायक संतु कुमार और डाक निरीक्षक अनुज कुमार को भेजा था। जहां आयुक्त के पूछे गए कई सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया कि मामले के तथ्यों की जानकारी उन्हें नहीं है। आयोग ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। और कहा कि आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने तथा कानून के तहत सीपीईयों को सौंप गई जिम्मेदारियां को पूरा करने में विफलता के कारण आयोग ने श्रीमती अर्चना कुमारी सीपीईयों को कड़ी फटकार लगाई। और उन्हें उचित लिखित स्पष्टीकरण भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही आरटीआई अधिनियम धारा 20 के तहत मामले में कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए की चेतावनी भी दी है। ऐसा इसलिए कि इसे उनका कृत कर्तव्य के प्रति स्पष्ट लापरवाही माना गया है। ऐसा आचरण न केवल आरटीआई अधिनियम की भावना का उल्लंघन है, जो सार्वजनिक अधिकारियों की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य करता है, बल्कि आयोग की,की गई कार्यवाही की अखंडता और प्रभावशीलता को भी कमजोर करता है। साथ ही आयोग के अधिकार के प्रति उपेक्षा और कानून के तहत सीपीईयों को सौंपी गई जिम्मेदारियां को भी निभाने में विफलता को दर्शाता है।

गिरीश प्रसाद गुप्ता, *आरटीआई एक्टिविस्ट*

मालूम हो कि आयोग ने सीपीईयों को यह भी निर्देश दिया है कि आरटीआई आवेदनों में पूछे गए सवालों पर संशोधित उत्तर 30 दिनों के भीतर अपील कर्ता को भेजा जाए।

बेगूसराय से एस आर आज़मी की रिपोर्ट

जो निरंतर प्रयास करता है, वही वास्तव में सफल होता है: जी के सिंह

12वीं एवं 10वीं में दून पब्लिक स्कूल के छात्रों ने किया कमाल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली कीआयोजित कक्षा 12वीं एवं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में बेगूसराय के रमजानपुर स्थित 'दून पब्लिक स्कूल' के छात्र एवं छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। पिछले 10 वर्षों से विद्यालय ने बोर्ड परीक्षा में सत्र दर सत्र नए कीर्तिमानों को छुता आ रहा है।

विद्यालय की ओर से कक्षा 12वीं से कुल 41 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें जीव विज्ञान वर्ग से सूरज कुमार ने मुख्य विषय में 97.5 % अंक प्राप्त करके पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मानविकी वर्ग से अनुश्री कुमारी (96%), आदर्श कुमार (94%) और सौरव कुमार (87.8%) ने विद्यालय में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए।

विज्ञान (जीव विज्ञान वर्ग) में सूरज कुमार (97.5%), अवनी भारती (86%), सृष्टि चौबे (83.8%) ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। विज्ञान (गणित वर्ग) में शुभम कुमार (84%), शालिनी भारद्वाज (79.6%) एवं मिहिर सिन्हा (70%) ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए।

कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय की ओर से कुल 72 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इनमें रूद्र प्रीय ने 96 प्रतिशत अर्थात (96%) अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आशुतोष कुमार एवं अदिति सहाय ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए। विद्यालय के कुल 40 प्रतिशत बच्चों ने 90 प्रतिशत (90%) से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय का संपूर्ण परीक्षाफल शत-प्रतिशत रहा। अलग-अलग विषयों के अनुसार विज्ञान, संस्कृत एवं हिंदी विषय का परिणाम सराहनीय रहा, जिनमें बच्चों ने 98 % से अधिक अंक प्राप्त किए।

विद्यालय के प्राचार्य जी के सिंह एवं प्रबंधक पंकज कुमार ने सभी बच्चों को उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य जी के सिंह ने बच्चों के नाम संदेश में कहा,- ''परीक्षा में प्राप्त सफलता हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में सहायक होती है। इस परीक्षा में जिन बच्चों ने अपनी आशा के अनुरूप अंक अर्जित किए हैं, उन्हें इसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिन्हें अपनी आशा के अनुरूप अंक नहीं प्राप्त हुए हैं, वे निराशा में न डूबें, बल्कि दुगने उत्साह के साथ अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढें। तीन घंटे की परीक्षा के आधार पर किसी की योग्यता का निर्धारण करना सही नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो निरंतर प्रयास करता है,वही वास्तव में सफल होता है। एक विद्यार्थी की सफलता उसकी अपनी कामयाबी के साथ-साथ उसके परिवार, विद्यालय एवं अध्यापक की कामयाबी होती है।''

इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य ने बच्चों को मिठाई खिला कर उनका उत्साहवर्धन किया। पूरे विद्यालय में उत्सव का माहौल रहा। विद्यालय परिवार के सभी लोगों ने बच्चों की सफलता के लिए उन्हें बधाइयां दीं।

ब्यूरो रिपोर्ट दूसरा मत

College of Commerce, Arts and Science
कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्टस एंड साइंस

A Constituent Unit of Patliputra University, Patna

College of Commerce, Arts & Science, Patna (est. 1949) is a constituent unit of Patliputra University, Patna. Re-accredited by NAAC with “A” grade, the college continues to Impart quality education since it’s inception.

Vocational Courses offered

- Bachelor of Computer Application (B.C.A.)
- Master of Computer Application (M.C.A.)
- B.Sc. (Information Technology)
- M.Sc. (Information Technology)
- M.Sc. (Electronics)
- Library and Information Sciences.
  - B.L.I.S.
  - M.L.I.S.
- Journalism & Mass Communication
- B.Sc. & M.Sc. (Bio-Technology)
- M.B.A.
- B.B.M.
- B.Com (Self Financing)

Add-on Courses

- Nutrition & Dietetics
- Clinical Psychology
- Medical Lab Technology
- Mass Communication
  (Certificate & Diploma)

Kankarbagh, Main Road, Patna- Bihar- 800020

principalcocaspatna@gmail.com www.cocaspatna.ac.in

The Glory of College of Commerce

College of Commerce, Arts & Science, Patna-20 is a constituent unit of Patliputra University, Patna (Bihar) duly recognized by University Grants commission. New Delhi under 2(f) and 12(B). The college was estabilished in 1949 by Pt. Indu Shekhar Jha, the founder principal of the college, a man of great vision, and the fater of commerce education in Bihar Coming from a small village called Sabour in Bhagalpur district of Bihar, Pt. Jha was a post graduate in Commerce from Calcutta University. On the advice of the assistance from the late Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, Pt. Jha translated his long-cherished dream of starting Commerce edution in Bihar from Rajendra College Chapra (Bihar) as a department of the college. But, not satisfied with this small beginning, and having a dream of launching an institution on the pattern of London School of Commerce or Sydendam College of Commerce and Economics, Bombay. Pt. Jha soon started campaigning, door to door at the same time, contacting some eminent people in Patna like Late Justice Khalil Ahmad, Late Nageshwar Prasad (Advocate), Late H.B. Chandra, Late Indiraj Bahadur and Late Babu Shyam Nandan Sahay to explain his ideas and seek their help to establish a Commerce College at patna the capital of Bihar. His herculean efforts bore fruit, and in 1949, he successfully launched his cherished institution, College of Commerce, at P.N. Anglo Sanskrit School Campus, Naya Tola, Patna in a rented house. Initially, only I.Com. programme was started with hardly a dozen of students and six faculty member. Later on, in 1953, Raja of Pali graciously donated lands to start the college at the place where it is today. The college was affiliated to Bihar University, Muzaffarpur a new university launched in 1952 in Bihar. In 1957, Science education was introduced in the college on the advice of the then Vice Chancellor of Bihar University Muzaffarpur. Babu Shyam himself, followed by Arts faculty 1960 and Law in 1963.

Prof. (Dr.) Indrajit Prasad Roy
Principal, College of Commerce, Arts and Science

सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहदरपुर का रिजल्ट रहा सौ फीसदी

सीबीएसई बोर्ड के नतीजे ने बेगूसराय के बहदरपुर स्थित सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए ख़ुशी का पल लेकर आया। छात्रों की उत्कृष्ट सफलता से पूरा स्कूल ख़ुशी के अनुभव में सराबोर हो गया। दर-असल इस स्कूल का परीक्षाफल सौ फीसदी रहा। दसवीं की परीक्षा में शिवांगी ने 95% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हर्ष कुमार ने 94.6% अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। नमन 93.8% प्राप्त कर तीसरे पर और रौनक गुप्ता ने 93.6% अंक लाकर चौथा स्थान प्राप्त किया।

गौरतलब है कि 90% से 100% तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है। 80% से 89% तक प्राप्त करने वाले 25 विद्यार्थी हैं। परिणाम अन्य विद्यार्थियों के भी उत्साहबर्धक रहे हैं।

बारहवीं की विज्ञान की परीक्षा में अनुज्ञा प्रकाश ने 90% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिव्या शर्मा ने 87% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पड़ रहीं। और वैष्णवी एवं शिवम शांडिल्या ने 85% अंक प्राप्त किएं।

वाणिज्य में गोविंद राज ने 85% अंक प्राप्त किए। बारहवीं में 80% से 100% अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है। जबकि 70% से 79% अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की तादाद17 है।

अन्य विद्यार्थियों ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्णता हासिल की।

इस अवसर पर विद्यालय के सचिव अमिताभ कुमार ने सफल होने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। और जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर प्राचार्य ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की जमकर प्रशंसा की।

ब्यूरो रिपोर्ट दूसरा मत

मगरमच्छ से भिड़ गया युवक

चंबल नदी के कैंजरा घाट पर नहाते समय गौंसिली गांव के 18 साल के करन को मगरमच्छ नदी के गहरे पानी में खींच ले गया। युवक ने मगरमच्छ से लड़ कर जान बचाई। इस दौरान बांह और सिर जख्मी हो गया।

घाट पर 13 मई की सुबह 9 बजे युवक नहा रहे थे। इस दौरान धारा सिंह के बेटे करन के सिर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करन बचने के लिए भागने लगा। मगरमच्छ ने छलांग लगा कर करन की बांह को जबड़े में जकड़ लिया। वह खींच कर गहरे पानी में ले जाने लगा। करन ने हिम्मत नहीं हारी। वह मगरमच्छ से जूझने लगा। घाट पर मौजूद लोगों की मदद से जान बच सकी। हमले में बांह और सिर जख्मी हुआ है। परिजन करन को निजी अस्पताल में ले गए हैं।

बाह के रेंजर उदय प्रताप सिंह के मुताबिक मगरमच्छ के हमले की सूचना पर टीम मौके पर भेजी थी। हमला कैंजरा घाट पर मध्य प्रदेश के छोर पर हुआ है।

पिछले महीने चंबल में मगरमच्छ की नेस्टिंग हुई थी। अगले माह से हैचिंग है। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक नेस्टिंग के बाद घोंसलों के नजदीक मानवीय गतिविधि से मगरमच्छ को अंडों की सुरक्षा पर खतरे का अहसास होने लगता है। इससे यह हमलावर हो जाते हैं। बाह रेंज के 40 गांवों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

हादसों का एक सिलसिला

28 मार्च : विंडवा के करण वृद्धा के अंतिम संस्कार के बाद चंबल में नहा रहे थे। मगरमच्छ गहरे पानी में खींच ले गया। शव नहीं मिला।

25 अप्रैल : हरपुरा गांव के रामवीर सिंह को बकरियों को पानी पिलाते समय मगरमच्छ नदी के पानी में खींच ले गया। शव नहीं मिल सका।

27 अप्रैल : गौंसिली गांव के धन सिंह चंबल नदी में बकरियों को पानी पिला रहे थे। इसी दौरान मगरमच्छ बकरी को पानी में खींच ले गया।

संदीप सृजन
वरिष्ठ स्तंभकार

क्यों कहा 'गीदड़'?

पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बोखलाए हुए पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। हाल ही में पाकिस्तानी संसद में एक सांसद ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 'गीदड़' कहकर तीखा हमला बोला। यह बयान न केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में अस्थिरता को दशार्ता है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व पर उनके अपने लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान में, बल्कि भारत और वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

बीते दिन पाकिस्तानी संसद में एक सांसद, शाहिद अहमद खट्टक, ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए उन्हें 'गीदड़' कहा। स-ांसद ने यह भी आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरते हैं। यह बयान उस समय आया जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में कऑपरेशन सिंदूरत और कइंडिया-पाकिस्तान वॉरत जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे है। सांसद ने अपने भाषण में कहा, ह्लअगर सरदार गीदड़ हो तो जंग हारते हैं। बुजदिल सरदार सेना को क्या संदेश देगा?ह्व इस बयान ने न केवल संसद में हंगामा मचाया, बल्कि पाकिस्तान की जनता और मीडिया में भी तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया।

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी संसद में इस तरह का विवाद हुआ हो। इससे पहले भी, 2019 में बालाकोट हमले के बाद, एक सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की कथित कमजोरी पर टिप्पणी की थी। उस समय भी सांसद ने दावा किया था कि पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के सामने घुटने टेक रहा था।

इस बार का विवाद इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहबाज शरीफ के नेतृत्व और उनकी सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल उठाता है।पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से अस्थिरता और आंतरिक कलह का शिकार रही है।

पाकिस्तान के सांसद का अपनी ही सरकार के प्रति असंतोष है। जो कि पाकिस्तानी सेना और नागरिक सरकार के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम है, क्योंकि सेना लंबे समय से देश की विदेश नीति और रक्षा नीति पर नियंत्रण रखती है।शहबाज शरीफ को पहले से ही एक कमजोर और समझौतावादी नेता के रूप में देखा जाता रहा है। इस बयान ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान जैसे देश में, जहां राष्ट्रवाद और भारत विरोधी भावनाएं राजनीति का एक बड़ा हिस्सा हैं, 'गीदड़' जैसे शब्द का इस्तेमाल शहबाज की विश्वसनीयता पर गहरा आघात करता है। यह बयान न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), की स्थिति को भी कमजोर करता है।

सोशल मीडिया पर इस बयान ने आग में घी का काम किया। कई यूजर्स ने शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया और उनकी सरकार को 'बुजदिल' करार दिया। यह घटना पाकिस्तान की पहले से ही अस्थिर राजनीति को और जटिल बना सकती है। शहबाज शरीफ की सरकार पहले ही विपक्ष के लगातार हमलों का सामना कर रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार, अक्षमता और सेना के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाती रही है। इस बयान ने विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है, जिसका इस्तेमाल वे शहबाज सरकार को और कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, यह बयान सेना और नागरिक सरकार के बीच संबंधों पर भी सवाल उठाता है। पाकिस्तान में सेना का राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा है। सेना लंबे समय से भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाने की पक्षधर रही है, और अगर शहबाज सरकार इस दिशा में थोड़ी नर्म पड़ती है। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे चल रहा है, दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक तनाव की स्थिति है। ऐसे में पाक सांसद के बयान ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि पाकिस्तान का नेतृत्व भारत के सामने कमजोर पड़ रहा है।

भारत में इस बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ भारतीय नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत का सबूत बताया, जबकि कुछ ने इसे पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी का प्रतीक माना है। वैश्विक स्तर पर, यह घटना पाकिस्तान की छवि को और कमजोर करती है। पहले से ही आर्थिक संकट और आतंकवाद जैसे मुद्दों से जूझ रहा पाकिस्तान अब आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण और चर्चा में है।पाकिस्तानी संसद में शहबाज शरीफ को ह्यगीदड़ह्न कहे जाने की घटना केवल एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गहरी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का प्रतीक है। यह बयान शहबाज शरीफ की सरकार की कमजोरी, विपक्ष के आक्रामक रवैये, और सेना-नागरिक सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभकार हैं)

बन सकता है साइबर अटैक भारत के लिए गंभीर खतरा

संदीप सृजन

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच, हाल के समाचारों और सोशल मीडिया पर प्रसारित चेतावनियों ने एक नए खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पाकिस्तान का संभावित साइबर अटैक। यह खतरा न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है बल्कि आम नागरिकों, सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। हाल के वर्षों में साइबर युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को नया आकार दिया है। परंपरागत युद्ध के साथ-साथ, देश अब डिजिटल क्षेत्र में भी अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं।

साइबर हमले कोई नई घटना नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच डिजिटल युद्ध का इतिहास कई वर्षों पुराना है। विशेष रूप से हाल के वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद, पाकिस्तानी हैकर समूहों ने भारतीय वेबसाइटों और डिजिटल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उदाहरण के लिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि भारत पर 10 लाख से अधिक साइबर हमले दर्ज किए गए। इन हमलों के पीछे पाकिस्तानी हैकर समूह जैसे 'HOA 1337', 'नेशनल साइबर क्रू', और 'पाकिस्तान साइबर फोर्स' का नाम सामने आया।

पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की वेबसाइटों को निशाना बनाया। इन हमलों में संवेदनशील डेटा, जैसे रक्षा कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, चुराने की कोशिश की गई। कुछ मामलों में, वेबसाइटों को डिफेस (विकृत) किया गया, और उन पर पाकिस्तानी झंडे और अल खालिद टैंक की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई उपयोगकर्ताओं ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले की योजना बना रहा है। इन पोस्ट्स में नागरिकों से अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने, संदिग्ध ईमेल्स या मैसेजेस को अनदेखा करने, और किसी भी अनजान ऐप को इंस्टॉल न करने की सलाह दी गई। ये चेतावनियाँ उस समय आईं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इन पोस्ट्स ने न केवल आम जनता में जागरूकता

बढ़ाई, बल्कि साइबर युद्ध के खतरे को भी रेखांकित किया। इन चेतावनियों ने भारत में साइबर सुरक्षा के प्रति गंभीर चर्चा को जन्म दिया है। यह संभावना कि पाकिस्तान साइबर हमलों के माध्यम से भारत की डिजिटल और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करती है जिसके लिए तत्काल और व्यापक तैयारी की आवश्यकता है।

पाकिस्तान से संभावित साइबर हमले विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। हैकर्स फर्जी ईमेल्स, व्हाट्सएप संदेश, या सोशल मीडिया लिंक्स के माध्यम से उपयोगकताओं को धोखा दे सकते हैं। ये लिंक्स मैलवेयर डाउनलोड कर सकते हैं या संवेदनशील जानकारी, जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण, चुरा सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तानी हैकर्स ने फर्जी ईमेल्स के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी।

वेबसाइट डिफेसमेंट एक सामान्य रणनीति है जिसमें हैकर्स किसी वेबसाइट के होमपेज को बदल देते हैं और उस पर प्रचार सामग्री, जैसे पाकिस्तानी झंडे या भड़काऊ संदेश, प्रदर्शित करते हैं। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को डिफेस करने का हालिया मामला इसका उदाहरण है। डेटा चोरी करना,संवेदनशील जानकारी, जैसे रक्षा कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज, चुराने की कोशिशें हो सकती हैं। 'पाकिस्तान साइबर फोर्स' ने दावा किया कि उसने टढ-क्ळ्ञअ और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के डेटा तक पहुंच बनाई है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इन हमलों में हैकर्स किसी वेबसाइट या सर्वर को अनगिनत अनुरोधों के साथ ओवरलोड कर देते हैं जिससे वह डाउन हो जाता है। रैनसमवेयर, यह एक ऐसा हमला है जिसमें हैकर्स डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगते हैं। वैश्विक स्तर पर रैनसमवेयर हमलों ने अरबों डॉलर का नुकसान किया है। इन हमलों के प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होने के अलावा, साइबर हमले आर्थिक नुकसान, सार्वजनिक विश्वास में कमी, और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बैंकिंग सिस्टम या सरकारी पोर्टल्स को निशाना बनाया जाता है, तो आम नागरिकों को तत्काल नुकसान हो सकता है।

भारत की साइबर सुरक्षा की स्थिति पर गौर करे तो भारत ने हाल के वर्षों में अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां, जैसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र सक्रिय रूप से साइबर खतरों की निगरानी करती हैं। पहलगाम हमले के बाद, भारतीय एजेंसियों ने कई साइबर हमलों को समय रहते निष्क्रिय किया। हालांकि, भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 4% कंपनियां साइबर खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा, आम जनता में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। कई नागरिक फिशिंग हमलों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे संदिग्ध लिंक्स या ईमेल्स को पहचान नहीं पाते।

पाकिस्तान से संभावित साइबर हमले से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाया जाए। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर आम जनता के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। नागरिकों को अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने, मजबूत पासवर्ड बनाने, और नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी जानी चाहिए।

सरकारी और निजी संस्थानों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। इसमें फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और नियमित साइबर ऑडिट शामिल हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसियों को रियल-टाइम में साइबर खतरों की निगरानी करनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद, भारतीय एजेंसियों ने कई हैकिंग प्रयासों को समय रहते रोका।

साइबर हमले सीमाओं को पार करते हैं, इसलिए भारत को अन्य देशों, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, और इजराइल, के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहिए। 'फाइव आईज' जैसे गठबंधन साइबर खतरों से निपटने में उपयोगी हो सकते हैं। साइबर अपराधियों को दंडित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। भारत को अपने साइबर क्राइम कानूनों को और सख्त करना चाहिए ताकि अपराधियों को तुरंत सजा दी जा सके।

पाकिस्तान से संभावित साइबर अटैक भारत के लिए एक गंभीर और तत्कालिक खतरा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव और सोशल मीडिया पर प्रसारित चेतावनियों ने इस खतरे को और स्पष्ट किया है। हालांकि, भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने कई हमलों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आम जनता, सरकार, और निजी क्षेत्र को मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

साइबर युद्ध का यह दौर न केवल तकनीकी तैयारी की मांग करता है बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता की भी आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना होगा और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों से बचना होगा। यदि भारत अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करता है, तो वह न केवल पाकिस्तान के संभावित हमलों को विफल कर सकता है बल्कि वैश्विक साइबर युद्ध के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभकार हैं)

अमेरिका बनाम चीन

प्रसेनजित दत्ता
वरिष्ठ पत्रकार

कई टिप्पणीकारों ने इस बात को तवज्जो दी है कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को फायदा हो सकता है। लेकिन इस पर कम चर्चा होती है कि इस अवसर का लाभ हासिल करने के लिए भारतीय नीति निमार्ताओं को बेहद चुनौतीपूर्ण राह तय करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही इन दिनों 'दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन' मानने वाले सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।

अमेरिका एक ऐसा व्यापारिक साझेदार चाहता है जो उन वस्तुओं की आपूर्ति कर सकें जो पहले चीन से आती थीं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह 'सामान के मूल देश' की बहुत बारीकी से जांच करेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन में पूरी तरह से या ज्यादातर बने सामान किसी अन्य देश के माध्यम से अमेरिका के बाजार में अप्रत्यक्ष तरीके से प्रवेश करें। यानी आदर्श स्थिति में अमेरिका यह चाहता है कि उसके व्यापारिक साझेदार चीन के साथ अपना व्यापार करना पूरी तरह से बंद कर दें।

वहीं दूसरी ओर चीन भी उतना ही स्पष्ट है कि वह महत्त्वपूर्ण सामग्री और अन्य सामान की आपूर्ति रोककर अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है। दुर्लभ तत्व ऐसा ही एक उदाहरण हैं। चीन का इरादा किसी ऐसे अन्य देश को दुर्लभ तत्त्वों की बिक्री न करने का है जहां से इन सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किए गए सामान अमेरिका भेजे जा सकते हैं।

खबरों के मुताबिक, उसने पहले ही दक्षिण कोरिया से कहा है कि वह अमेरिकी रक्षा फर्मों को दुर्लभ तत्त्वों से बने उत्पाद न दे। वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अपने प्रभुत्व वाले कई क्षेत्रों में विनिर्माण प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से उन देशों को वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो इन्हें अमेरिका को बेच सकते हैं।

दूसरी ओर भारत, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए इच्छुक है। भारत के लिए अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को छोड़ देना समझदारी नहीं है। वास्तव में, अमेरिका कुछ उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि भू-राजनीतिक मोर्चे पर चीन के साथ अपने अच्छे अनुभव न होने के बावजूद, भारत निकट भविष्य में आयात के मामले में उस पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सकता है।

चीन इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों और सौर पैनलों तक, कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण इनपुट की आपूर्ति करता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर तक बढ़ गया है, क्योंकि लगभग सभी विनिर्माण क्षेत्र, चीन से आने वाले इनपुट पर निर्भर हैं।

लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत इन कई उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला तंत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। हालांकि, कड़वी हकीकत यह है कि इसके पास विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की कमी है और इसे इनकी आपूर्ति के लिए चीन के सहयोग की दरकार है। यही कारण है कि सौर पैनल निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे कई उद्योगों में, भारतीय कंपनियां चीनी विशेषज्ञों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं। समस्या यह है कि व्यापार युद्ध में किसी भी पक्ष के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखने के कारण, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद चीन, भारत को विनिर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी देने से इनकार कर सकता है।

भारत को यह भी समझना चाहिए कि उसे आर्थिक, विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा क्योंकि न तो अमेरिका और न ही चीन को एक स्थिर साझेदार के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने दिखाया है कि वह अपने सबसे करीबी सहयोगियों, कनाडा से लेकर यूरोपीय संघ तक के खिलाफ भी जा सकता है। भारत के पास इस बात पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि उसका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन से अधिक का कोई संबंध होगा।

इस बीच, चीन ने दशकों से भारत के मित्रता के प्रयासों को लगातार ठुकराया है। यह एक ऐसा रुख है जो दोनों देशों में राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद नहीं बदला है। चीन भी भारत को महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हासिल करके एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहता है। भारतीय नीति निमार्ताओं को यह समझने की जरूरत है कि भारत अब तक अपनी आर्थिक वृद्धि को लेकर बेफिक्र रहा है जो काफी हद तक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च के माध्यम से संभव हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण बनाम सेवाओं के समीकरण के बारे में अकादमिक जगत और सरकारी, दोनों हलकों में कई चर्चाएं हुई हैं। समस्या यह है कि आज की दुनिया में, भले ही सेवा क्षेत्र सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र हो फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए विनिर्माण की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से, भारत बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया में रातों-रात विनिर्माण क्षेत्र में महाशक्ति नहीं बन सकता है। महज कुछ क्षेत्रों में भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निमार्ता बनने के लिए भारत को एक स्पष्ट दृष्टिकोण और बहु-दशकीय योजनाओं की आवश्यकता होगी जिन्हें पूरी मेहनत से क्रियान्वित किया जाए।

भारत की कई विनिर्माण समस्याएं अंदरूनी हैं जो अनावश्यक और पुराने जमाने के नियमों और लाल फीताशाही से लेकर बिजली और लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा नीतिगत अस्थिरता और न्यायिक स्तर पर अनुबंधों को लागू करने में देरी जैसी अन्य समस्याएं भी हैं। शिक्षा, कौशल और श्रम उत्पादकता के मुद्दों को भी हल करने की आवश्यकता है और इन्हें रातों-रात ठीक नहीं किया जा सकता है।

इन सबके लिए निश्चित रूप से स्पष्ट सोच वाले नीति निर्माण और दशकों तक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले धैर्य की आवश्यकता है। यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है क्योंकि अगर एक कम्युनिस्ट देश माओ के समाजवादी औद्योगिक शक्ति बनाने के आर्थिक और सामाजिक अभियान तथा सांस्कृतिक क्रांति जैसी नीतियों को सहने के बावजूद इसे सुनिश्चित कर सका है तब भारत जैसे कुछ हद तक उदार अर्थव्यवस्था वाले एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि, इच्छाशक्ति और लगातार फॉलो-अप करने की आवश्यकता है।

(लेखक संस्था प्रोजेक व्यू के संस्थापक हैं)

दवा उद्योग पर दोतरफा मार

सोहिनी दास

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका में पर्चे पर लिखी जाने दवाओं के मूल्य अन्य देशों के बराबर किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने से भारत पर दो तरफा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत सहित अन्य बाजारों में दवाओं का मूल्य बढ़ाएंगी और इससे भारत के मरीजों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, भारत के औषधि निर्यातकों को मध्यम अवधि में अमेरिका में मूल्य का दबाव सहना पड़ेगा।

ट्रंप ने 11 मई को हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की थी। ट्रंप ने इसे ह्यअमेरिका के इतिहास में सबसे प्रभावी कार्यकारी आदेशह्न करार दिया था। इस फैसले का उद्देश्य अमेरिका में पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाओं का मूल्य कम करना और अमेरिका में दवाओं का मूल्य तत्काल प्रभाव से 30 से 80 प्रतिशत कम करना है। ट्रंप ने अन्य देशों की तुलना में अमेरिका के उपभोक्ताओं के दवाओं के लिए अधिक मूल्य अदा करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 'एक ही कंपनी के एक प्रयोगशाला या संयंत्र' में बनाई गई दवा अमेरिका में 'पांच से 10 गुना' अधिक महंगी है।

दिन के कारोबार में भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम होने पर बाजार जब खुशी मना रहा था तब निफ्टी फार्मा का कारोबार दिन में गिरा। हालांकि यह दिन की समाप्ति पर सुधरा और मामूली सुधार के साथ बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार में सन फार्मा, ग्लेन मार्क, अजंता फार्मा आदि गिर गए।

सोमवार के कार्यकारी आदेश में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि व वाणिज्य मंत्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अमेरिका में अन्य देश जानबूझकर दाम बढ़ाने वाले तरीकों में शामिल नहीं हो और वे अनुचित तरीके से दाम नहीं बढ़ाएं। यह आदेश प्रशासन को निर्देश देता है कि वह औषधि निमार्ताओं को मूल्य लक्ष्य के बारे में जानकारी दे। अमेरिका विश्व में पर्चे पर लिखी जाने वाली दवाओं का सबसे बड़ा खर-ीदार और धन मुहैया कराने वाला है। स्वास्थ्य व मानवीय सेवा के सचिव ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि अमेरिका के मरीज बिचौलियों को दरकिनार कर अपने देश में दवा बेचने वाले विनिमार्ताओं से सीधे दवा खरीद सकें। इस सिलसिले में ट्रंप ने पहले कहा था कि इस कदम से अन्य देशों में औषधियों के दाम बढ़ेंगे और दाम का वैश्विक अंतर पटेगा। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के निवासी ब्रांडेड नामों वाली दवाओं के लिए ओईसीडी देशों की तुलना में तीन गुना अधिक मूल्य का भुगतान करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश में कहा गया कि अमेरिका में विश्व की पांच प्रतिशत से कम आबादी है लेकिन वह वैश्विक औषधि के लाभ में करीब 75 प्रतिशत का योगदान देता है।

विश्लेषकों के अनुसार सन फार्मास्युटिक्ल इंडस्ट्रीज सर्वाधिक प्रभावित होने वाली कंपनियों में हो सकती है। इस कंपनी का अमेरिका के बाजार में पर्याप्त बड़ा ब्रांडेड कारोबार है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषक श्रीकांत अकोलकर ने बताया, 'कंपनियां जैसे सन फार्मा का अमेरिका में ब्रांडेड कारोबार 1 अरब डॉलर से अधिक है और वे इस नीति को लागू होने और सख्ती से लागू होने का असर का सामना कर सकती हैं। हालांकि जेनरिक बाजार पर भी मध्यम अवधि में दबाव देखने को मिल सकता है। इसका कारण यह है कि जेनरिक दवाएं भी डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाती हैं।'

सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की शोध व परामर्श कंपनी ग्रांड व्यू रिसर्च

के अनुसार 2024 में अमेरिका का बाजार 634.32 अरब डॉलर होने का अनुमान है और इसका 2025 से 2030 तक सीएजीआर वृद्धि 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 में अमेरिका के फार्मा मार्केट में ब्रांडेड खंड के राजस्व की हिस्सेदारी 66.86 प्रतिशत थी और इसका इस बाजार में दबदबा था।

भारत की कई कंपनियां अपने कुल राजस्व का एक तिहाई अमेरिका से प्राप्त करती हैं। इस क्रम में ज्यादातर भारतीय कंपनियां अमेरिका को जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करती हैं और वे ब्रांडेड उत्पादों को उपलब्ध नहीं कराती हैं। भारत से अमेरिका को आपूर्ति की जाने वाली दवाओं में करीब 50 प्रतिशत जेनरिक दवाएं होती हैं। अमेरिका को आपूर्ति होने वाली जेनरिक दवाओं में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक 36 प्रतिशत है। भारत की कंपनियों ने अमेरिका के 10 अरब डॉलर के मूल्य की दवाओं का निर्यात किया है।

नई नीति ह्यसबसे पसंदीदा राष्ट्रह्व मूल्य निर्धारण मॉडल को लागू करेगी। नई नीति में यह सुनिश्चित होगा कि अमेरिका दुनिया में कहीं भी दवा के लिए वसूले जा रहे न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान नहीं करेगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के मुताबिक ट्रंप के इस कदम से अमेरिका के मरीजों को तत्काल लाभ मिल सकता है लेकिन इससे वैश्विक स्तर पर दवाओं के मूल्यों का पुनः आकलन हो सकता है। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अभी तक भारत विदेशी कंपनियों के मरीजों के कानून में संशोधन के दबाव के खिलाफ प्रमुख रूप से खड़ा था।

उन्होंने बताया, 'भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के साथ इस बदलाव से भारत पहली बार ट्रिप्स समिति की सिफारिशों के परे प्रावधानों पर सहमत हो गया है।' उन्होंने कहा, 'यह रियायत वैश्विक दवा कंपनियों के लिए एक जीत है। और यूरोपीय संघ व अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में आगे की मांगों के लिए द्वार खोलती है।'

काबिलियत और अंक में फर्क समझें

प्रियंका सौरभ

बच्चों की शिक्षा का विषय हमेशा से ही समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। माता-पिता और शिक्षक, दोनों ही बच्चों की सफलता के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन कई बार यह चिंता एक दबाव का रूप ले लेती है। विशेष रूप से अंक या ग्रेड के मामले में, यह दबाव बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। इस लेख में हम इस मुद्दे की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंक और काबिलियत की वास्तविक परिभाषा के बीच के अंतर को समझना और स्वीकारना आवश्यक है।

अंक बनाम काबिलियतः एक बुनियादी भेद अक्सर माता-पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे हर विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करें। वे यह मानते हैं कि अच्छे अंक अच्छे भविष्य की गारंटी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंक केवल एक व्यक्ति की किताबी जानकारी का प्रमाण होते हैं, न कि उसकी असल क्षमता का। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसे कला, संगीत, खेल या तकनीकी कौशल में रुचि है, वह संभवतः गणित या विज्ञान में उतने अच्छे अंक न ला पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कम लायक है। काबिलियत का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, नई चीजें सीखने का जज्बा और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की क्षमता है।

अंक प्रणाली का वास्तविक प्रभाव हमारे शिक्षा प्रणाली का ढांचा अभी भी पारंपरिक मानदंडों पर आधारित है, जहां अंकों को सफलता का एकमात्र पैमाना माना जाता है। इससे बच्चों में असुरक्षा और आत्म-संकोच की भावना विकसित होती है। कई बच्चे अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरे न उतर पाने के डर से मानसिक तनाव का सामना करते हैं। यह मानसिक दबाव उनकी आत्म-छवि और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, यह न केवल बच्चों की पढ़ाई पर बल्कि उनके सामाजिक संबंधों और मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास की भावना तभी विकसित होती है जब उन्हें बिना भय और दबाव के सीखने का अवसर मिले।

कैसे अंक प्रणाली बच्चों की रचनात्मकता को दबाती है अंक प्रणाली न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता और खोज की क्षमता को भी सीमित करती है। वे अपनी मौलिक सोच और रचनात्मकता को छोड़कर केवल अंकों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में देखी जा रही है, जहां छात्रों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम में ढालने का प्रयास किया जाता है, बिना उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को पहचानने की कोशिश किए। इसके परिणामस्वरूप, कई बच्चे अपनी वास्तविक क्षमता और रुचियों को पहचानने में विफल रहते हैं, जो कि उनके जीवन में दीर्घकालिक असंतोष का कारण बन सकता है।

समाज का नजरिया और दबाव समाज का नजरिया भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है। अक्सर माता-पिता अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से करने लगते हैं। यह तुलना बच्चों में हीन भावना और जलन पैदा कर सकती है। साथ ही, यह उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। बच्चों को यह महसूस होने लगता है कि उनकी पहचान केवल उनके अंकों से ही मापी जाती है, न कि उनके चरित्र, कौशल और मानवीय मूल्यों से। बच्चों का मानसिक विकास तभी संभव है जब उन्हें बिना किसी भय और दबाव के सीखने का अवसर मिले।

परिवर्तन की आवश्यकता हमें शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक समझदार, सशक्त और नैतिक नागरिक का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए हमें अंकों से परे जाकर बच्चों की असल काबिलियत को पहचानने और उसे प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अद्वितीय है और उसकी रुचियां, क्षमताएं और सपने भी अलग हैं।

बच्चों को समर्थन दें, दबाव नहीं माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्रेरित करें, न कि उन पर अनावश्यक दबाव डालें। हर बच्चा अनोखा होता है, उसकी सोच, रुचि और क्षमता भी अलग होती है। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की आजादी दें, न कि केवल समाज के तय किए गए मापदंडों पर खरा उतरने का बोझ डालें। बच्चों के साथ संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दें। केवल अच्छे अंक लाने पर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें जीवन के हर पहलू में सफलता पाने का आत्मविश्वास दें।

अंक जीवन का एक छोटा हिस्सा हैं, लेकिन असल काबिलियत और नैतिकता जीवन का असली मूल्य है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को केवल अच्छे अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। बच्चों की पहचान उनके अंकों से नहीं, बल्कि उनके विचारों, कर्मों और चरित्र से होनी चाहिए। बच्चों की असली पहचान उनके भीतर छुपी क्षमताओं, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता में होती है। यही वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से भरा हुआ होना चाहिए।

दूसरा मत
हार्दिक शुभकामनाएं
दूसरा मत
दूसरा मत के 20 साल
बेमिसाल
जीत का जादूगर
पढ़ें और पढ़ाएं
दूसरा मत
एक शुभचिंतक, दिल्ली

डॉ. मनु मिड्ढा
अस्सिटेंट प्रोफेसर एआई

पढ़ने-पढ़ाने के तौर-तरीके बदले एआई तकनीक ने

एआई का उपयोग सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। यह भी कि मानवीय शिक्षकों की भूमिका कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि एआई उन्हें और बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। तो भविष्य की शिक्षा की शुरूआत हो चुकी है इऔर उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कोई नागरिक इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एआई आधारित शिक्षा के अवसरों को अपनाएं और सीखने की इस नई क्रांति का आनंद लें!

इक्कीसवीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एक ऐसी तकनीक जो मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। एआई हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है। जो अब केवल रोबोटिक्स या औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है।

एआई ने न केवल पढ़ाने के तरीके को बदला है, बल्कि सीखने, मूल्यांकन और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतें समझने के नजरिए को भी क्रांतिकारी बना दिया। दर-असल हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता, गति और रुचि अलग-अलग होती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को एक समान तरीके से पढ़ाया जाता था, जिससे कई छात्र पीछे रह जाते थे। जबकि एआई आधारित लर्निंग टूल्स जैसे एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स अब छात्र की सीखने की गति, रुचि, और कमजोरियों को ध्यान में रख उन्हें अनुकूल सामग्री प्रदान करते हैं।

मसलन, बायजूस, खान अकेडमी और कोसेर्रा जैसे प्लेटफॉर्म एआई की मदद से छात्रों को उनके स्तर के अनुसार टॉपिक्स सुझाते हैं और बेहतर समझाने के लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट प्रदान करते हैं। इससे छात्रों को अपनी गति से सीखने का मौका मिलता है, जिससे उनकी समझ और आत्मविश्वास बढ़ते हैं।

एआई आधारित स्मार्ट ट्यूटर और चैटबॉट्स छात्रों को 247 सहायता प्रदान करते हैं। अब छात्रों को हर छोटी-छोटी शंका के लिए शिक्षक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये वर्चुअल असिस्टेंट तुरंत सवालों के जवाब देते हैं, चाहे वह गणित का जटिल फॉर्मूला हो या इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख। वहीं डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म एआई का प्रयोग कर भाषा सीखने की प्रगति ट्रैक करते हैं व उसी मुताबिक नए पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है।

ध्यान रहे, एआई का मतलब यह नहीं कि शिक्षकों की जरूरत खत्म हो गई है। बल्कि, एआई ने शिक्षकों को और अधिक प्रभावी और डेटा-सक्षम बना दिया है। मसलन, अब शिक्षक यह समझ सकते हैं कि कौन-सा छात्र कहां पिछड़ रहा है और उसी के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकते हैं। वहीं एआई तकनीक की मदद से शिक्षक अपने समय का अधिकतम उपयोग पढ़ाने के अलावा मार्गदर्शन, प्रेरणा और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कर पा रहे हैं। एआई शिक्षकों का सहायक बन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रही है।

यह भी कि एआई आधारित ऑनलाइन

परीक्षा प्रणाली अब उत्तरों का त्वरित और सटीक मूल्यांकन कर रही है। कई शिक्षण संस्थान एआई की मदद से क्विज का मूल्यांकन कर छात्रों को तुरंत परिणाम जारी कर सुधार के सुझाव देते हैं। इससे छात्रों को अपनी कमजोरियों का तुरंत पता चलता है जिनमें वे समय रहते सुधार कर सकते हैं। साथ ही, यह शिक्षकों का कीमती समय बचाती है, जिसे वे अन्य रचनात्मक और शैक्षिक गतिविधियों में लगा सकते हैं।

एआई ने शिक्षा को दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम और टूल्स ने उनके लिए नई राहें खोली हैं।

स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी तकनीकों ने दृष्टिहीन और श्रवण बाधित छात्रों को भी शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिया है। इससे शिक्षा समावेशी बन रही है।

एआई केवल पढ़ाई में सहायक नहीं है, बल्कि खुद एक महत्वपूर्ण कैरियर स्किल बन चुका है। आज स्कूलों और कॉलेजों में एआई, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी भविष्य की तकनीकी नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। 'एआई फॉर यूथ' प्रोग्राम इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो युवाओं की एआई के कौशल विकास में मदद करता है।

एआई केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह शिक्षा में एक नई सोच का प्रतीक है। शिक्षा अब केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि समझ, अनुभव और नवाचार का केंद्र बन गई है। छात्र अब जिज्ञासु हैं, सवाल पूछते हैं और खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। एआई इस प्रक्रिया को निरंतर समर्थन प्रदान करता है, जिससे शिक्षा अधिक इंटरैक्टिव, रोचक और प्रभावी बनती है। दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शिक्षा को स्मार्ट, व्यक्तिगत और इंटरेक्टिव बना दिया है। आज शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक के सहारे हर बच्चा, हर उम्र का व्यक्ति अपने समय व तरीके के हिसाब से सीख सकता है।

हालांकि, एआई का उपयोग सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। यह भी कि मानवीय शिक्षकों की भूमिका कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि एआई उन्हें और बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। तो भविष्य की शिक्षा की शुरूआत हो चुकी है ङ्कऔर उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कोई नागरिक इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एआई आधारित शिक्षा के अवसरों को अपनाएं और सीखने की इस नई क्रांति का आनंद लें!

(लेखिका के अपने विचार हैं। लेखिका एआई विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

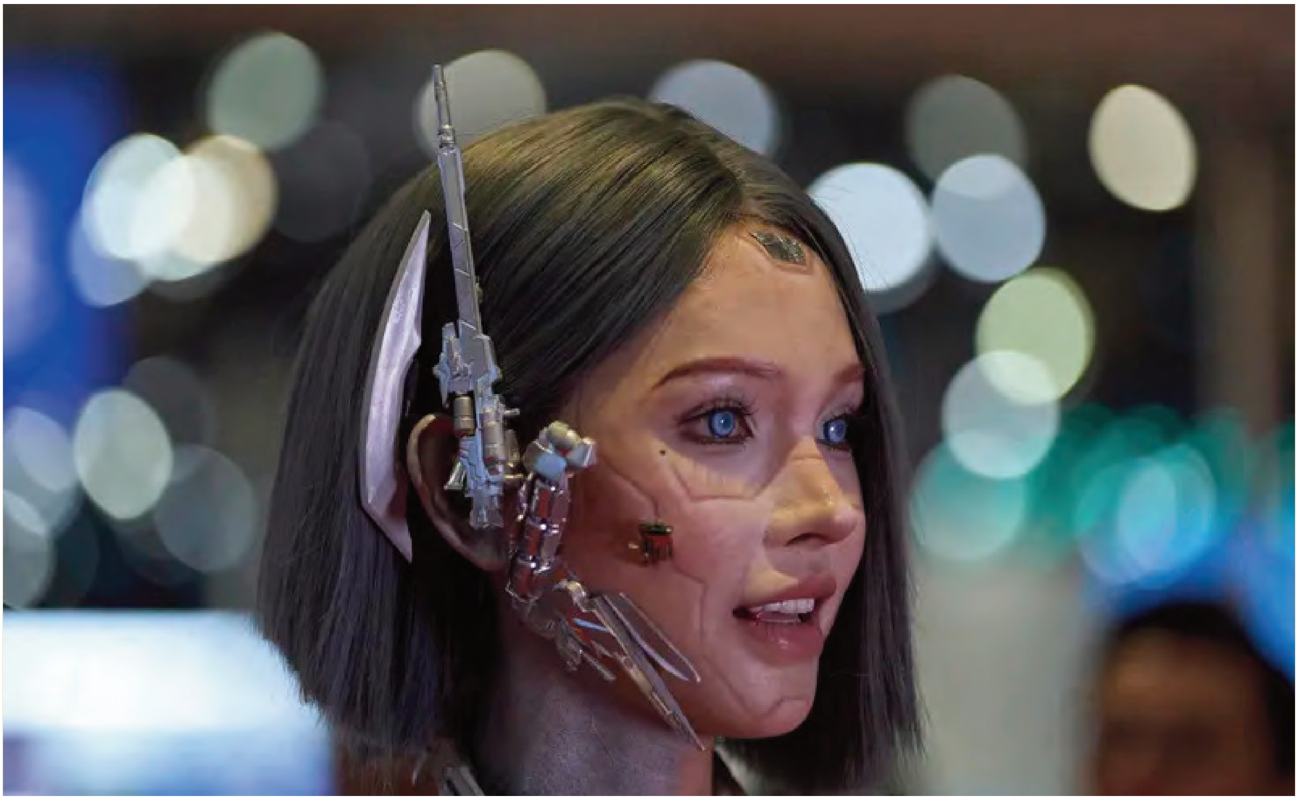

किताबों की दुनिया बदल रही है

विजय गर्ग

किताबों का इतिहास बहुत दिलचस्प है। पहले यह माना जाता था कि मुद्रित पुस्तकों की प्रक्रिया 1448 ई. में शुरू हुई थी। इसकी शुरूआत 1500 में हुई, जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। लेकिन बाद में यह बात गलत साबित हुई। । हालाँकि, पाँच हजार साल पहले भी किताबें थीं, लेकिन वे आज जैसी नहीं थीं। वे प्राचीन पुस्तकें सफेद मिट्टी की पट्टियों पर लिखी गयी थीं। इन प्रारंभिक पुस्तकों के अवशेष सरगान, बोबल आदि स्थानों पर पाए गए हैं। बेबेल, जिसे आज हम बेबीलोनिया कहते हैं, में लगभग ढाई हजार ऐसी छुट्टियां मिली हैं। इन्हें विभिन्न विषयों में वगीर्कृत किया गया है, जैसे ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा आदि। चीन के पहले यात्री फाह्यान ने 399 से 414 ई. तक यात्रा की थी। वह 1920-2000 के बीच भारत आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने शैक्षिक केंद्रों में पुस्तकालयों के अस्तित्व पर प्रकाश डाला था। एक अन्य चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 629 से 645 ई. तक यात्रा की थी। उन्होंने 1811 में मध्य एशिया और भारत का शैक्षिक दौरा किया। उन्होंने रेशमी कपड़े, भोजपत्र, चमड़े और लकड़ी के चौकोर टुकड़ों पर हाथ से लिखी गई पुस्तकों का उल्लेख किया। हालाँकि, तब तक चीन के हान राजवंश के दौरान कागज का आविष्कार हो चुका था। काई लुन नामक व्यक्ति को कागज का आविष्कारक माना जाता है। लेकिन वहां से अन्य देशों तक पहुंचने में काफी समय लग गया। जब कागज अस्तित्व में आया तो इसका उपयोग किताबें लिखने के लिए किया जाता था। गुटेनबर्ग ने 1448 ई. में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। सन्‍ 1811 में उन्होंने अपने मुद्रण-यंत्र से पहली पुस्तक, बाइबल, छापी। लंबे समय तक इस बाइबल को पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता रहा। लेकिन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में यह सम्मान तिब्बत के एक मठ में मिले 'हीरा सूत्र' को दिया गया। यह एक बौद्ध धर्मग्रंथ है, जिसका पाली भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। दरअसल, जोहानिस गुटेनबर्ग से बहुत पहले बौद्ध भिक्षुओं ने मुद्रण की एक विधि का आविष्कार कर लिया था। इस पद्धति में मुद्रित की जाने वाली सामग्री को लकड़ी के चौकोर टुकड़ों पर उल्टा लिखा जाता था। फिर, स्याही वाले भाग को छोड़कर, लकड़ी की शेष सतह को खोखला कर दिया गया और समतल कर दिया गया। एक पुस्तक के लिए ऐसे कई टिकट बनाने पड़ते थे। यह काफी कठिन काम था, लेकिन एक बार टिकट तैयार हो जाने के बाद किताबों की 50-100 प्रतियां छापना आसान हो गया। लगभग बारह सौ साल पहले किताबों की दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डायमंड सूत्र 868 ई. में लिखा गया था। इसे

इसी मुद्रांकन विधि का उपयोग करके मुद्रित किया गया था पुस्तकों की एक लम्बी परम्परा रही है। इसे ज्ञान का भण्डार कहा जाता है। किताबें इस दुनिया को बदलने का एक साधन बन गई हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई गीता की शिक्षाएं आज एक पुस्तक के रूप में संरक्षित हैं। बाइबल, कुरान, रामायण और वेद पवित्र ग्रंथ हैं। लेकिन इसका स्वरूप एक किताब जैसा है। किताबें देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी इतिहासकार और दार्शनिक थॉमस कार्लाइल ने पुस्तकों के बारे में कहा है - मानव जाति ने जो कुछ भी किया, सोचा, हासिल किया या घटित हुआ, यह सब पुस्तकों के जादुई पन्नों में सुरक्षित है। अर्थात् पुस्तकें मानवता के दस्तावेज हैं। पुस्तकें मनुष्य को जीवन का मार्ग दिखाती हैं, जीने के नए तरीके सुझाती हैं। अंग्रेजी लेखिका डोरोथी व्हिपल इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं झ ह्नपुस्तकें समय के विशाल सागर में स्थापित प्रकाश स्तम्भ हैं ह्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुस्तकों के बहुत बड़े भक्त थे। उनका कथन है - मैं अच्छी पुस्तकों का नरक में भी स्वागत करूंगा, क्योंकि उनमें जहां भी वे रहती हैं, वहां स्वर्ग बनाने की शक्ति होती है। - इसका मतलब यह है कि किताबें हमारे जीवन में सच्ची मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत की भूमिका निभाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे - +हम पुस्तकों के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते।4 वास्तव में, पुस्तकें व्यक्तित्व के समग्र परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी विद्वान ने पुस्तकों को सभ्यता की आंखें कहा है।

किताबों से दोस्ती करने का सबसे अच्छा समय बचपन है। इस उम्र में एक बार दोस्ती हो जाए तो वह जीवन भर चलती है। शिक्षाविद् डी.एस. कोठारी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध कराने के बड़े समर्थक थे। उनके शब्दों में - बाल साहित्य पढ़ने से बच्चे का बौद्धिक क्षितिज विस्तृत होता है और वह दृश्यमान परिवेश के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है। यह बच्चों में प्रकृति, पर्यावरण और पर्यावरण के सजीव और निर्जीव तत्वों के प्रति जिज्ञासा और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों से जुड़ने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, वे आपके साथ रहना चाहती हैं। इस कविता में पुस्तकों के महत्व को रेखांकित किया गया है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ! पुस्तक में हर पहलू को शामिल किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि आजकल किताबों की कद्र बहुत कम हो गई है। किताबों से हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हमारे परिवार और पड़ोस के बड़े-बुजुर्ग किताबें पढ़ा करते थे। उन्हें देखकर हम भी किताबों के पन्ने पलटने लगे। फिर एक समय आया जब हम किताबों की दुनिया में उतरने लगे। अब समय बदल गया है. समाज किताबों से दूर हो गया है। बूढ़े से लेकर जवान, यहां तक कि बच्चे भी कर्ण के बाद मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। जिन शब्दों में कभी जिंदगी धड़कती थी, वे अब अलमारी में बंद किताब के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। आजकल किताबों की दुनिया बदल रही है। पहले तो ढेरों किताबें होती थीं - धर्म पर, कर्म पर, ज्ञान पर, कहानियां, कविता, उपन्यास, दर्शन, इतिहास, काव्य से लेकर महाकाव्य तक... लेकिन अब सब कुछ एक फोटो मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप में मिल जाता है। असीमित डेटा की दुनिया अमर रहे! इसका मतलब यह है कि किताबों की दुनिया अब डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। शब्दों की शक्ति किताबों से ऑनलाइन तक पहुंच गई है। अब ई-पुस्तकों का युग आ रहा है। किताबों के मोमबत्ती संस्करण निकलने लगे हैं। इन्हें केवल डिवाइस पर ही पढ़ा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। किताबों की दुनिया तेजी से बदल रही है। इस प्रकार, पारंपरिक पुस्तकों के अस्तित्व और उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले समय में पुस्तकों का स्वरूप अतीत की स्मृति मात्र बनकर रह जाएगा?

जब भी हम किताबों की बात करते हैं तो ज्ञान और साहित्य उसके केंद्र में होते हैं। समाज किताबों से दूर होता जा रहा है। लेकिन क्या ये परिवर्तन, इंटरनेट और उपकरण जो पुस्तक और पाठक के बीच आ गए हैं, प्राकृतिक विकास का हिस्सा हैं? यह गंभीर बहस का विषय है, लेकिन इस नए माध्यम को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में इसके माध्यम से साहित्य, मनोरंजन और ज्ञान का सृजन होगा। विज्ञान का एक नया मार्ग उभरेगा। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते. लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह नया माध्यम ज्ञान, मनोरंजन और संस्कृति प्रदान करने में पुस्तकों की भूमिका का स्थान ले पाएगा। इसका उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है। पुस्तकें न केवल ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ाती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इस माध्यम के साथ गहरी एकता स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए ई-बुक पढ़ते समय हम संवेदना और दृश्यावलोकन की वांछित स्थिति से दूर हो जाते हैं।

विषय-वस्तु हमारी मानसिकता पर गहरी छाप नहीं छोड़ सकती। इससे हमें मनोरंजन और जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन ज्ञान और संस्कृति नहीं। जब कोई पाठ गहन एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता की स्थिति में पढ़ा जाता है, तो वह हमारे मन में काफी समय तक स्थिर रहता है और हमारे विचारों को प्रभावित करता है। यह दृश्य पाठक के पिछले अनुभव को पुनः जीवंत कर देता है। इस पुनःनिर्माण में उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसके आचरण के साथ मिलकर संस्कार का निर्माण करता है। वास्तव में, किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी संस्कृति है। यह पूरी प्रक्रिया ई-पुस्तकों या वीडियो के माध्यम से उतनी आसानी से और व्यवस्थित रूप से नहीं की जा सकती, जितनी पारंपरिक पुस्तकों को पढ़ने से की जा सकती है। यही कारण है कि शिक्षाविद और बुद्धिजीवी समाज से दूर होती जा रही पुस्तकों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यदि पारंपरिक पुस्तकें न होतीं तो मानव आत्मा का विकास अवरुद्ध हो जाता और जड़ता बढ़ जाती। इसलिए, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बच्चों में बाल साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'सक्रिय पुस्तकालय' अभियान शुरू किया गया। वहां प्रशिक्षण था।

भारत की पहली जीनोम–संपादित चावल

सुनील कुमार महला
वरिष्ठ स्तंभकार

भारत विश्व का एक बड़ा कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली जीनोम-संपादित चावल की किस्में कडीआरआर धान 100 (कमला)त और कपूसा डीएसटी राइस 1त जारी की हैं।

देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई ,2025 के दिन आईसीएआर की विकसित देश की पहली जीनोम-संपादित धान की ये दोनों किस्में जारी की है। वास्तव में ये वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार है। इन किस्मों की खास बात यह है कि इनमें विदेशी चावलों की किस्मों या विदेशी डीएनए को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल विदेशी डीएनए शामिल नहीं होने के कारण भारतीय कृषि में इनकी पैदावार ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है, जिस प्रकार से हमारे यहां पारंपरिक रूप से फसलें उगाई जाती रहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन नयी किस्मों का विकास क्रिस्पर-कैस आधारित जीनोम-संपादित तकनीक का उपयोग करके किया गया, जो बिना विदेशी डीएनए को शामिल किए हुए जीव के आनुवंशिक सामग्री में सटीक परिवर्तन लाती है। धान की ये किस्में जहां एक ओर उपज में बढ़ोत्तरी करेंगी, वहीं दूसरी ओर संसाधनों की दक्षता को भी ये बढ़ाएंगी। इतना ही नहीं ये जलवायु की दृष्टि से भी लचीली बताईं जा रहीं हैं। और तो और ये किस्में जल-संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होंगी।वैसे तो भारत विश्व का अनाज उत्पादन में एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है लेकिन आज की वैश्विक परिस्थितियों में हमारे देश में भी अनेक

प्रकार की खाद्य सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। मसलन आज भारत में विश्व की सर्वाधिक आबादी है। जलवायु परिवर्तन भी लगातार हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों के बीच आईसीएआर की विश्व की पहली जीनोम संपादित धान की दो किस्मों का विकास भारतीय कृषि के लिए जहां एक ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, वहीं दूसरी ओर यह खाद्य सुरक्षा की दिशा में भी उठाया गया एक बड़ा और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है।

एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक में उपलब्ध जानकारी कै अनुसार ड-ीआरआर धान 100 (कमला) लोकप्रिय साँबा महसूरी किस्म पर आधारित है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिऐस 1 (एसडीएन1) तकनीक का उपयोग करके साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 (सीकेएक्स2) जीन (जीएन1ए) को लक्षित करके दानों की संख्या में सुधार किया गया। इसके परिणामस्वरूप शीघ्र परिपक्वता (15-20 दिन पहले कटाई), सूखा-सहिष्णुता, उच्च नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता प्राप्त होती है। उल्लेखनीय है कि इस किस्म को आईसीएआर-भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय परीक्षण में डीआरआर धान 100 (कमला) की औसत उपज 5.3 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई, जो साम्बा महसूरी (4.5 टन) से 19% अधिक है।

दूसरी ओर पूसा डीएसटी चावल 1, मारुतेरु(एमटीयू) 1010 किस्म पर आधारित है और सूखे और लवण सहनशीलता को बढ़ाता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि एमटीयू 1010 किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसका दाना लम्बा-बारीक होता है, और दक्षिण भारत में रबी सीजन के चावल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यह सूखे और लवणता सहित कई अजैविक तनावों के प्रति संवेदनशील है। पूसा डीएसटी चावल 1 लवणता और क्षारीयता युक्त मृदा में एमटीयू 1010 की तुलना में 20% अधिक उपज देती है। एसडीएन1 जीनोम-एडिटिंग के माध्यम से विकसित, यह शुष्क और लवणीय सहनशीलता (डीएसटी) जीन को लक्षित करता है । इसके परिणामस्वरूप तटीय लवणता वाले क्षेत्रों में 30.4% अधिक उपज, क्षारीय मृदाओं में 14.66% अधिक तथा अंतर्देशीय लवणता वाले क्षेत्रों में 9.67% अधिक उपज प्राप्त होती है ।इसे आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि एसडीएन-1 विदेशी डीएनए का उपयोग किये बिना छोटे सम्मिलन/विलोपन प्रस्तुत करता है, जबकि एसडीएन-2 विशिष्ट वांछित परिवर्तन प्रस्तुत करने के लिये टेम्पलेट डीएनए (मेजबान के समान) का उपयोग करता है। पाठकों को बताता चलूं कि धान की नई उन्नत विकसित किस्में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में करीब 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इन कि स्मों की खेती की जा सकेगी, जिससे धान के उत्पादन में 4.5 मिलियन टन की वृद्धि होगी। साथ ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 20 प्रतिशत यानि 3200 टन की कमी आएगी। बहरहाल, यहां यह गौरतलब है कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए धान का पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और अब इन किस्मों की खेती से धान के उत्पादन में करीब 45 लाख टन का इजाफा होगा, तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी करीब 20 फीसदी की कमी आएगी। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां संपूर्ण विश्व में जल संकट गहराता चला जा रहा है, ऐसे में इन धान की किस्मों की खेती में कम पानी की खपत होगी और फसल पककर तैयार होने में भी कम समय लगेगा, जिसने किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरूआत 1965-1968 के बीच मानी जाती है और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है ।हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन(गेहूं और चावल के उत्पादन में) अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी ।गौरतलब है कि हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक, उर्वरक और कीटनाशकों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। वास्तव में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरित क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि इसने भारतीय कृषि को पूरी तरह से बदल दिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में यह उम्मीद जताई जा रही है कि धान की ये नई किस्में दूसरी हरित क्रांति की शुरूआत में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। धान की इन दोनों किस्मों की विशेषताओं की यदि हम यहां पर बात करें, तो इन दोनों किस्मों की खेती से उपज में 19 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी आएगी। इतना ही नहीं, सिंचाई जल में 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूखा, लवणता एवं जलवायु तनावों के प्रति यह दोनों ही किस्में उच्च सहिष्णु हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कमी से पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल सकेगा। अंत में यही कहूंगा कि चावल भारत की प्रमुख फसलों में से एक है और भारत में चावल का उत्पादन कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी ।इन दोनों किस्मों के आने से निश्चित ही भारत में चावल उत्पादन में कहीं और अधिक बढ़ोत्तरी सुनिश्चित होगी। कहना गलत नहीं होगा कि आईसीएआर की यह उपलब्धि(चावल की किस्मों का विकास) नई उम्मीदों को जगाती है। इससे भारतीय कृषि और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होगी।

(लेखक फ्रीलांसर हैं)

डॉ. वेदप्रकाश
वरिष्ठ स्तंभकार

सामाजिक समरसता और जातीय गणना

सामाजिक समरसता ही विकसित राष्ट्र का आधार है। आज भारत में जबकि कई अवसरों पर छोटी-छोटी बातें आपसी वैमनस्य का कारण बन जाती हैं, तब समाज जीवन में ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जहां सभी लोग जाति, संप्रदाय, भाषा एवं क्षेत्रीयता आदि के भेदभाव से परे मिलजुल कर रहें। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास की गारंटी के रूप में देखा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मानते हुए इसका श्रेय लेने की होड़ में लगा है। कांग्रेस राहुल गांधी को सामाजिक न्याय की राजनीति का नया नायक बनने में जुट गई है। इसे एक बड़ा अवसर मानते हुए राहुल तत्काल यह घोषणा कर चुके हैं कि अब 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस दबाव बनाएगी। क्या इससे जातीय गणना का मंतव्य और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं दिखाई दे रही है? क्या इस प्रकार की घोषणाओं से समाज में विभाजन नहीं होगा? क्या आपसी झगड़े नहीं बढ़ेंगे? क्या संख्या में अधिक जाति के लोग संख्या में कम जाति के लोगों पर वर्चस्व जमाने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या जातीय आधारों पर योजनाएं और आरक्षण घटने बढ़ने से प्रतिभाशाली लोग उपेक्षित नहीं होंगे?

ध्यान रहे अतीत में ऊंच-नीच और जातियों के भेदभाव के कारण देश ने बहुत कुछ सहा है। विभिन्न संतों और कवियों ने जात-पात को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए घातक बताया है। संत रविदास की पंक्तियां हैं- जात जात में जात है, ज्यों केला में पात...। संत रविदास ने एकता और भाईचारे के लिए जाति को बड़ी बाधा माना था। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है-भारत एक ऐसा देश है, जहां प्रत्येक जाति अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है। स्पष्टत सरकार को जातीय गणना के साथ-साथ सामाजिक समरसता का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। क्या जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए बिना कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती? क्या कई प्रदेशों और क्षेत्रों में धार्मिक आधार पर जनसंख्या असंतुलन के दुष्परिणामों से सरकार अनभिज्ञ है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरंभ से ही सबका साथ- सबका विकास का मंत्र लेकर अनेक योजनाओं के सहारे आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त, 2014 को लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने मां भारती के कल्याण का संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा था- हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए, हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने के संकल्प का यह पर्व है। इसके साथ ही उन्होंने घर-घर शौचालय, जनधन योजना, हर घर नल- हर घर जल, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एवं मुद्रा योजना आदि के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों के कल्याण हेतु अनेक प्रयास किए हैं, यह सराहनीय है। आज विभिन्न योजनाएं जन सामान्य तक पहुंच रही हैं। इसका प्रमाण है कि भारत में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आजादी के बाद पहली बार जनगणना के साथ ही जातीय गणना करवाने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत लोगों की जाति के आधार पर व्यवस्थित तरीके से विभिन्न आधारों पर आंकड़े जुटाए जाएगें। यह भी स्पष्ट है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में अनेक जातियां हैं जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं। जातीय गणना से प्रदेश एवं क्षेत्रीय आधार पर जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, रोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होंगी जिनके आधार पर भविष्य में उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी।

समाचार पत्रों में छपी जानकारी के अनुसार भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। उस समय भारत की आबादी

25.38 करोड़ थी। तब से प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1881 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। उसके बाद जातीय सर्वेक्षण तो करवाए गए लेकिन जातीय गणना नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी. उस समय सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके पीछे उस समय सरकार का तर्क था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। वर्ष 2011 में भी यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना करवाई थी लेकिन जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों?

यह भी ध्यान रहे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में जाति,संप्रदाय, क्षेत्रीयता एवं भाषा लगातार वैमनस्य और दंगों का कारण बन रहे हैं। सामान्य जनगणना के माध्यम से भी सरकार के पास आवश्यक आंकड़े आ जाते हैं, जिससे कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा कि जातीय जनगणना से देश में जातीय विभाजन गहरा हो सकता है जो समाज में आपसी तनाव और वैमनस्य को बढ़ाएगा। आरक्षण की दृष्टि से वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। जातीय गणना के आंकड़े इस संरचना को प्रभावित कर सकते हैं अथवा संख्या बल के आधार पर जातियां सरकार पर अधिक आरक्षण हेतु दबाव बनाएंगी। स्पष्टत आरक्षण की मौजूदा संरचना को घटाना अथवा बढ़ाना फिर से नए झगड़ों को जन्म दे सकता है।

पिछले लंबे समय से देश सबका साथ-सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जातीय गणना हम भारत के लोग अथवा सबका की भावना को ठेस पहुंचा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अनेक अवसरों पर सामाजिक समरसता हेतु आपसी भेदभाव छोड़कर एकजुट होने का आवाह्न कर चुके हैं। विगत दिनों भी उन्होंने कहा है- मंदिर, पानी और श्मशान सबके लिए हों। यह घोड़ी पर चढ़ सकता है वह नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या आज भी प्रतिदिन समाचार पत्रों में डीजे बजाने, ढोल बजाने, शादी के अवसर पर घोड़ी पर बैठने, मंदिर जाने से रोकने आदि के झगड़े व समाचार पढ़ने को नहीं मिलते हैं? आज जातीय गणना शुरू करने से पहले उसके नफे व नुकसान का विश्लेषण करना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, क्या जाति आधारित गणना और तदुपरांत आरक्षण एवं जाति के कल्याण के नाम पर बनाई जाने वाली योजनाएं अन्य जातियों के साथ विभेद पैदा नहीं करेंगे? क्या आज सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए और सभी के कल्याण के लिए जातीय गणना की अपेक्षा वंचित, उपेक्षित और पिछड़े आदि सभी को एक जाति मानकर उनके कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है?

(लेखक के अपने विचार हैं। लेखक किरोड़ीमल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

ये समय

श्रुति व्यास

भारत आज व्हाट्सएप और हैशटैग पर जिंदा है। हम चन्द्रमा पर यान उतरने पर गर्व महसूस करते हैं। मगर चांद से बहुत नजदीक मणिपुर हमें नजर नहीं आता। दरअसल हम अपनी महानता के गीत इतने जोर-जोर से इसलिए गाते हैं ताकि हमारा ध्यान उस दर्पण से हट सके जो हमें हमारी असलियत दिखा रहा है। आज का भारत आधा बना नहीं है और आधा बदहवास, बिफरा हो गया है। व्हाट्सएप पर झुंझला रहा है, हैशटैग्स पर मार्च कर रहा है, और प्रोपेगेंडा ही उसकी देशभक्ति है।

मुझे वह क्षण याद है जब मैंने पहलगाम हमले की खबर सुनी और दिल से निकला–'फिर से?'

शोक, भ्रम, भय के जाने-पहचाने भाव तुरंत मन पर छा गए। मन ही मन कुछ मथने लगा। लेकिन इससे पहले कि दुःख स्थिर हो पाता, कुछ और हुआ–कुछ और अधिक कुरूप। चंद घंटों में ही मानवीय पीड़ा हैशटैगों में तब्दील हो गयी। गुस्सा मीम्स के जरिये जाहिर होने लगा। त्रासदी, तमाशा बन गई। जिस समय धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर, एक राष्ट्र के रूप में साझा शोक का होना चाहिए था, वह कुछ ही देर में शोर में खो गया। उसकी बजाय लौट आया, दहाड़, नाटकीय गुस्सा, तात्कालिक नैरेटिव, और वही पुराने बाइनरी में बंटी हुई मुर्गा छाप बहसें।

मौका राष्ट्रीय शोक का था। लोगों को एक-दूसरे के करीब आना था। जाति और संप्रदाय की सीमाओं के ऊपर उठना था। मगर हुआ उल्टा। वही हिंदू-मुस्लिम, वही शोरशराबा, वही तुरत-फुरत निष्कर्ष।

घटना हुए दो सप्ताह हो गए हैं। इस बीच उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हमें जो बताया जा रहा है उसमें से कुछ सही है, कुछ अनजाने में गलत है और कुछ जानते-बूझते गलत है। सच बेजा तर्कों के शोर में दुबक गया है। जैसा कि किसी ने लिखा है, 'जो असल में जिम्मेदार हैं उनके अलावा सभी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।' मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने की भरसक कोशिश की।

इसलिए क्योंकि इसमें रहते हुए लगातार सुनाई देगा -जंग शुरू हो गई है! यदि सोशल मीडिया की बाढ़ से नहीं बचे तो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करने पर दिमाग जैसे गूंधा हुआ गूदा बन जाता है। सचमुच अब समय अनदेखी और अज्ञानता में जीने का है। यही आत्म-रक्षा का तरीका है।

मैंने हमले पर, कश्मीर पर लिखने से भी परहेज किया। आखिर इसके शोरगुल और हल्ला-बोल में यदि कोई भी ईमानदारी से कुछ कहे, तो वह हो रही 'बकवास' में 'दुश्मन' समझा जाएगा।

जॉर्ज ओरवेल ने कहा था, 'धोखेबाजी की दुनिया में सच बोलना भी क्रांतिकारिता है।' मगर आज के भारत में सच, दरअसल, अप्रासंगिक बन गया है। सच्चाई को झूठ के रेपर में लपेट कर प्रस्तुत किया जाता है। अपने नैरेटिव को सही सिद्ध करने के लिए इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सच केवल और केवल तभी बोला जाता है जब उसका इस्तेमाल हथियार की तरह संभव हो।

और यह हर बार, लगातार होता हुआ है। जाहिर है यह बहुत थकाने वाला है। हर आतंकी हमले, हर प्राकृतिक आपदा, हर विरोध प्रदर्शन टीवी पर बहस का मुद्दा बन जाता है। हर आदमी जज है। कोई चीजों को समझना नहीं चाहता। कोई घावों को भरना नहीं चाहता। टीवी के परदे पर वही जाने-पहचाने चेहरे एक-दूसरे पर चीखते दिखते हैं। स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है। दूसरे को दोषी ठहराओ, उसे शर्मिंदा करो। अगर आप इस भीड़ में शामिल नहीं होते तो आप देशद्रोही हैं, आपको धमकियां मिलेंगी, आपको ट्रोल किया जाएगा और हो सकता कि आप के खिलाफ देश के किसी भी थाने में रपट लिखवा दी जा जाए।

क्या हम सच का सामना कर पाएंगे?

युवाल नूह हरारी कहते हैं मनुष्य जाति पृथ्वी पर अपना राज इसलिए स्थापित कर सकी क्योंकि उसमें काल्पनिक कथाएं गढने और उन्हें फैलाने की क्षमता थी। हम ही काल्पनिक कहानियां, मिथक और विचार रच सकते हैं, उन्हें फैला सकते हैं, और लाखों लोगों को उन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इन कथाओं का मतलब साहित्यिक कथाएं नहीं है। ये कथाएं एक एजेंडा के तरह गढ़ी जाती हैं, इन्हें मुनाफे के लिए, उत्तेजित करने के लिए फैलाया जाता है, और समाज को बाँटने, भड़काने, चिढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। ये लोगों को विभाजित करती हैं, उन्हे गुस्से से भर देती हैं।

ऐसे में 'बकवास' का 'विरोध' करने वाला, उससे अलग लिखने वाला अकेला खड़ा दिखता है। वो नारों में नहीं बहता, वो हर चीज को ए बनाम बी के रूप में नहीं देखता है। वह अपने तरीके से सोचता है। वह जानता है कि सच को जोर-जोर से चिल्लाकर नहीं बताना पड़ता। वह जानता है कि मीनार पर खड़े होकर हमें अपने आप को देशभक्त सिद्ध नहीं करना है। वह यह भी समझता है कि चुपचाप खड़े रहना, सहमत नहीं होना भी देशभक्ति है। असली देशभक्ति अक्सर शांत असहमति में खड़ा होना भी है।

आज 'भारतीय होना' अक्सर इस बात से परिभाषित होता है कि हम क्या नहीं हैं, न कि हम क्या हैं।

इस सिकुड़ी हुई पहचान में भारतीय होना मतलब–मुसलमान नहीं होना, उदार नहीं होना, कश्मीरी नहीं होना, अभिजात्य वर्ग से नहीं होना, और

सबसे अहम, सवाल न पूछना आवश्यक है। आज आप सच्चे भारतीय तभी हैं जब आप मुसलमान नहीं है, आपकी सोच उदार नहीं हैं, आप कश्मीरी नहीं हैं, आप श्रेष्ठी वर्ग से नहीं हैं और आप सवाल नहीं पूछते।

राष्ट्रवाद को हर तरह से अब धर्म के साथ नत्थी कर दिया गया है। हमें अपने आप के हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। मगर यदि हिंदू होना ही भारतीय होना बन जाए तब क्या? इससे क्या करोड़ों लोग आहत नहीं होंगे? क्या उनमें अलगाव का भाव घर नहीं कर जाएगा? क्या राष्ट्रवाद का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम अमृत काल में जी रहे हैं? पर आखिर अमृत काल है क्या है? क्या उसमें पहचानें संकीर्ण होंगीं? क्या उसमें माहौल में खौफ घुला होगा? क्या असहमत होना खतरनाक होना है? क्या अमृत काल में हमें हर समय बतलाते रहा जाएगा कि हमें क्या सोचना है, न कि यह कि हमें कैसे सोचना है?

हमें गर्व से हिन्दू होना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन जब भारतीयता और हिंदू होने के बीच फर्क मिटा दिया जाता है—सांस्कृतिक रूप में नहीं, राजनीतिक रूप में—तब यह न केवल करोड़ों लोगों को बेगाना नहीं बनाता,बल्कि राष्ट्रवाद और आस्था—दोनों को विकृत कर देता है। तब राष्ट्रवाद भूल जाता है कि उसे गर्व किस बात पर करना था।

क्या अमृत काल वो समय है जिसमें तकनीक तो बढ़ेगी, लेकिन आजादी घटेगी? जहां शोर तो बहुत होगा, लेकिन समझ कम होती जाएगी? जहां पहचान और संकुचित, भय एक सामान्य बात, और असहमति और अधिक खतरनाक हो जाएगी? क्या यह वो युग है जिसमें हम सूचना से डूबे रहेंगे, लेकिन ज्ञान से खाली रहेंगे? जहां हमें सोचने के लिए क्या सोचना है, यह बताया जाएगा—मगर कैसे सोचना है, यह नहीं सिखाया जाएगा?

पर यदि यही स्वर्ण काल है? यदि यही 'अमृत काल' है, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, तो पूछना पड़ेगा— किसका अमृत? किसका काल? और किस कीमत पर?

ग्यारह साल पहले जब नई सरकार ने सत्ता संभाली थी तब उसने वादा किया था कि 'दलदल सूखा देंगे' ।उस कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ा जाएगा, दिल्ली के उस जड़ पैंठाए प्रतिष्ठान को उखाड़ फेंकेंगे जिसने तबाही बनाई है। जो कुछ नया होने ही नहीं देता। लेकिन हुआ क्या?

एक नया दलदल खड़ा हुआ—और पहले से ज्यादा आक्रामक, ज्यादा शोरगुल वाला।

लुटियन दिल्ली के नए सत्ता वर्ग और व्यवस्था की कुलीनता अब व्हाट्सएप फारवड्र्स की भाषा बोलती हैं, वह चौबीसो घंटे क्रोध में डूबे हुए होती हैं, और आलोचना को देशद्रोह समझते हैं।

वी. एस. नायपॉल ने भारत को कभी 'जख्मी सभ्यता' बताते हुए लिखा था- एक ऐसा 'दीन देश, जो दिखावटी औसतपन से भरा हुआ है, और जिसका कोई भविष्य नहीं।' यहां अत्यंत औसत लोग अपने आप को ज्ञान का कोष समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का कोई भविष्य नहीं है। उन दिनों ये शब्द चुभते थे।

आज लगता है कि वह एक सटीक भविष्यवाणी थी। भारत आज व्हाट्सएप और हैशटैग पर जिंदा है। हम चन्द्रमा पर यान उतरने पर गर्व महसूस करते हैं। मगर चांद से बहुत नजदीक मणिपुर हमें नजर नहीं आता। दरअसल हम अपनी महानता के गीत इतने जोर-जोर से इसलिए गाते हैं ताकि हमारा ध्यान उस दर्पण से हट सके जो हमें हमारी असलियत दिखा रहा है।

आज का भारत आधा बना नहीं है और आधा बदहवास, बिफरा हो गया है। व्हाट्सएप पर झुंझला रहा है, हैशटैग्स पर मार्च कर रहा है, और प्रोपेगेंडा ही उसकी देशभक्ति है।

समाज ऐसा समाज बन गया है जो अपनी कथित महानता का इसलिए बखान करता है क्योंकि उसमें अब आईने में झांकने का साहस ही नहीं बचा!

भारत के सामने ढेर सारी समस्याएं हैं - आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन, ग्लोबल वार्मिंग, महंगाई, । आर्थिक परेशानियां।

लेकिन इससे भी बड़ा, और कहीं अधिक मौन संकट भीतर घट रहा है! हम सोचने की शक्ति खो चुके हैं, हमने दुख को महसूस करने की क्षमता गंवा दी है, और धीरे-धीरे देख पाने की दृष्टि भी धुंधला रही है। हम सच्चाई को देख नहीं पाते, हम दूसरे के दुःख को साझा नहीं करते। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई गुरु वह सिखा सकता है जो वह स्वयं नहीं करता? क्या जो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, वह क्या नेता कहला सकता है?

तभी सच में सवाल है, हम कैसे समय में जी रहे है?

हम ऐसे समय में हैं जहां प्रोपेगेंडा को देशभक्ति समझा जाता है।

जहां सच से ज्यादा सुरक्षित है चुप रहना।

जहां शोक को बेचने की चीज बना दिया गया है और असहमति को अपराध, और विचार तथा विचारों को अवैध करार दिया गया है।

हम ऐसे समय में हैं जहां संपूर्ण बने रहना मतलब है—अकेला महसूस करना।

फिर भी—हमें सोचना होगा।

हमें सूखे घास में चुभती खरपतवार बने रहना होगा,

बियाबान में उठती एक आवाज बने रहना होगा।

आखिरकार, उम्मीद भी तो एक बारीक ही सही, पर एक हठ होती है,

जो हर बार टूटकर भी फिर से जुड़ने की ज़िद रखती है।

जैसा कि जेम्स बाल्डविन ने कहा थाः- ' हर वो चीज जिसे हम सामने लाते हैं, बदल नहीं जाती। लेकिन कोई भी चीज तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम उसका सामना न करें।'

आईना हमारे सामने है।

अब यह हम पर है—

क्या हम आंखें खोल कर उसमें झांकने का साहस करेंगे,

या फिर बंद आंखों से लगाते रहेंगे नारे!

इसी से फैसला होना है कि भारत आगे किस समय में पहुंचेगा।

व्हाट्सएप की दुनिया का एक सच

मो. ज़ाहिद हुसैन
स्तंभकार

व्हाट्सएप- व्हाट्सएप खेलने का आजकल एक ट्रेंड चल चुका है। इससे लोग चैटिंग धुआंधार करते हैं। आसान है- एक ग्रुप बना लेना। और फिर चलता रहता है खेल- इस खेत का पानी, उस खेत में करने का। कोई भी मनपसंद मैसेज या वीडियो हो, तो लोग धड़ाधड़ लाइक, कमेंट शेयर करने लगते हैं। हां, उन्हें जब कुछ लिखने की बारी आती है तो- आधा तीतर, आधा बटेर। हिंग्लिश में लिखेंगे। ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। MAIN TUMSE PYAR KARTA HUN,उनके ज़हन में ठीक से ग्रामर तो है नहीं।

चैटिंग की भी अपनी भाषा होती है। How r u ? हाउ आर यू ? मैसेजिंग की भी अपनी कूट भाषा होती है, जिसे नौजवान भली-भांति जानते हैं। और उसके जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। है न कमाल की बात? लेकिन भाषा एवं साहित्य का क्या हाल है अभी? उन्हें कुछ भी उत्तर देना होता है, तो एक शब्द में या मीम से ही काम चलाते हैं। वाक्य, वाक्यांश, उपमा, अलंकार एवं संदर्भ देने का चलन खत्म हो रहा है।

लोग मैसेज या वीडियो को दोस्तों या किसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर अपना फर्ज अदा कर देते हैं। दरअसल वे अपनी भड़ास निकालते हैं, या वे फिर समझते हैं कि हम अपने विचार को दूसरों तक फैलने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह एक मानसिक विलासिता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरह तो कुछ लोग मोबाइल चलाते-चलाते मनोरोगी भी बन रहे हैं। उन्हें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, पोस्ट,फॉलो, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते-करते उनकी सोच कुछ अलग हो जाती है, जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उनके लिए तथा समाज के लिए कहीं न कहीं सही नहीं है। कुछ विद्वतजन अच्छा प्रसंग भी पेश करते हैं। नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यूथ है कि थोड़ा-सा लंबा लेख या एक पृष्ठ से ज्यादा कुछ ज्ञान-वान हुआ कि नहीं, उसे पढ़ना पसंद नहीं करते। इस तरह वे बौद्धिक विलासिता का हिस्सा नहीं बन पाते। उन्हें तो बस अनाप-शनाप, उन्मादी तथा मानोविनोदी पोस्ट चाहिए होती है। फेक मैसेज फैलाने वालों का तो एक अलग ही आईटी सेल है, जो नित नवीन कहानी गढ़ता रहता है।

साहित्यकार, इतिहासकार, शिक्षाविद एवं समाजशास्त्री डॉ लक्ष्मीकांत सिंह का कहना है कि सोसल मीडिया प्लेटफार्म सनकी, गालीबाज और नफरती लोगों का सैरगाह बन चुका है। यहां विमर्श कम, वीभत्सता अधिक है। हाल ही में जो 'छावा' फिल्म के बाद धारावाहिक के समान उठा-पटक डिबेट चला, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज,औरंगजेब की औलादें और फिर राणा सांगा की - ; इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि पहले इतिहास विद्वान लोग लिखते थे। अब नेता, छुटभैय्या, टपोरी, अधकपारी, सनकी और अंधभक्त, सभी लोग इतिहासकार बने फिर रहे हैं। और वे व्याख्या कर रहे हैं कि कौन किसके वंशज हैं? उनका क्या कारनामा था? वे जो भी सुनी-सुनाई सामने वाले के मिजाज के मुताबिक बक देते हैं। जैसे वही इतिहास हो गया। कहते हैं लोग कि इतिहास बदल देंगे। इतिहास क्या बदलेंगे? इतिहास तो वही रहेगा। क्या जो घटनाएं पूर्व में घटित हुई, वे बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर इतिहास आप कैसे बदलेंगे? वर्तमान और भविष्य आप बदल सकते हैं। इतिहास नहीं। हां, वर्तमान की विचारधारा के प्रकाश में आप इतिहास लिख सकते हैं, जिसमें भटकाव भी हो सकता है। वह पूर्वाग्रह से प्रेरित भी हो सकता है।

हमें इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चीन के सम्राट किन शी हुआंग ने जो भूल

'हंड्रेड स्कूल ऑफ थॉट्स' को जलाकर की थी, हम भारतवासियों को वैसी भूल नहीं करनी चाहिए। इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, उससे हम सीखते हैं। इतिहास की विरासत को संजो कर रखना चाहिए। और उसे सीखना चाहिए। ऐतिहासिक इमारतों के मौलिक ढांचे बहुत कुछ कहते हैं, स्थानों के समकालीन नाम भी बहुत कुछ कहते हैं; उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वे अतीत की गाथा कहती हुई प्रतीत होते हैं। याद रहे कि विरासतें हमारी संस्कृति की वाहक होती हैं।

आधुनिक आंदोलनकारी बैठे-बैठे ही सबकुछ पाना चाहते हैं। वे सामाजिक परिवर्तन का दम भरते हैं। वे भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। और अपने जैसे विचारधारा वालों को मैसेज भेजते हैं। फॉर-अगेंस्ट चलता है। कुछ लोग ताईद करते हैं, तो कुछ लोग मुखालफत करते हैं। कुछ लोग अपने नवीन विचार भी पेश करते हैं। अच्छे विचार भी आते हैं। लेकिन निर्मूल तब हो जाता है, जब वे कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचत पाते। और उन अच्छे विचारों को कार्यरूप नहीं दे पाते। वे कुछ भी पोस्ट करने को ही अपना फर्ज समझते हैं। वे बैठे-बैठे ही समझते हैं कि हम दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। क्रांति होने वाली ही है। हमारी बात दूर तक जा रही है। हमारा व्हाट्सएप पर पोस्ट करना भी एक आंदोलन है।

'दुनिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों एक हो'। ठीक मार्क्स के स्टाइल में, 'दुनिया के मजदूरों एक हो'। ऐसे विचित्र मंगलग्रह के व्हाट्सएपजीवी प्राणि जो न कभी धरना- प्रदर्शन करते हैं, न सड़क पर उतरते हैं। और नहीं जोशीले नारों के साथ व्यवस्था परिवर्तन की आवाज बुलंद करते हैं। वे कायर आंदोलनजीवी कोई और नहीं, बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थीगण ही हैं, जो फोटो-सोटो खींचते हैं। सेल्फी-वेल्फी लेते हैं। और फोटोजीवी होने गर्व महसूस करते हैं। फेसबुकिया जेनरेशन फिजिकल मूवमेंट में विश्वास नहीं करते। इसमें जोखिम अधिक जो है। इन्हें तो 'लगे हरे न फिटकरी रंग चोखा चाहिए'। चाहे वे आई टी सेल के चक्कर में जॉम्बी ही क्यों न बन जाएं। जिस देश का यूथ अपाहिज हो जाए, उस देश का भला कौन करेगा? वहां क्रांति नहीं हो सकती, जहां के लोग हालात से खुद ही बेखबर हों।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्रिकेट और टेलीविजन धारावाहिकों की टीआरपी

राजेश कुमार सिन्हा

भारत एक ऐसा देश है, जहां क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है। और टेलीविजन धारावाहिक लगभग हर घर में मनोरंजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इन दोनों ही माध्यमों का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव है और दोनों ही अरबों रुपए के उद्योग हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का बुखार चढ़ता है, खास्ाकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे बड़े आयोजनों के दौरान, तो क्या इसका असर अन्य टेलीविजन कार्यक्रमों, विशेषकर लोकप्रिय धारावाहिकों की टीआरपी पर पड़ता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसके दोनों पक्षों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है।एक तरफ, यह तर्क दिया जा सकता है कि क्रिकेट, अपनी रोमांचक प्रकृति और ग्लोबल लोकप्रियता के कारण, निश्चित रूप से दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। आईपीएल के दौरान, शाम के प्राइम टाइम स्लॉट, जो आमतौर पर लोकप्रिय धारावाहिकों के प्रसारण का समय होता है, क्रिकेट मैचों से भर जाते हैं। क्रिकेट के प्रति दीवानगी ऐसी है कि लोग अपने पसंदीदा धारावाहिकों को छोड़कर या बाद में देखने के लिए स्थगित करके मैच देखना पसंद करते हैं। एक आम भारतीय घर में, जहाँ टेलीविजन अक्सर परिवार का साझा मनोरंजन का स्रोत होता है, क्रिकेट मैच की प्राथमिकता अक्सर अन्य कार्यक्रमों पर भारी पड़ती है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सभी क्रिकेट के रंग में रंगे होते हैं, जिससे धारावाहिक देखने वाले दर्शकों की संख्या में कमी आ सकती है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि कई घरों में टी वी सेट एक ही होता है जिस पर पुरूष समुदाय मैच शुरू होते ही कब्जा जमा कर बैठ जाता है ऐसे में महिलाएं टी वी धारावाहिक देखने का मन होने के बावजूद उससे वंचित रह जाती हैं और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका कुछ न कुछ प्रभाव टी आर पी पर जरूर पड़ता होगा।इसके अतिरिक्त, बड़े क्रिकेट आयोजनों के दौरान बड़े बड़े विज्ञापनदाताओं का ध्यान भी स्वाभाविक रूप से क्रिकेट मैचों की ओर ही ज्यादा होता है। उच्च टीआरपी और ग्लोबल दर्शक वर्ग के कारण, क्रिकेट मैचों के दौरान विज्ञापन स्लॉट महंगे होते हैं और कंपनियाँ इन पर भारी निवेश करती हैं। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अन्य टेलीविजन कार्यक्रमों पर पड़ सकता है, जिन्हें विज्ञापनदाताओं की कमी या कम आकर्षक विज्ञापन स्लॉट मिल सकते हैं, जिससे उनकी कमाई और लोगों तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें या ऐसा माइंड सेट बन चुका है कि क्रिकेट मैच एक अलग तरह का उत्साह और जुड़ाव पैदा करते हैं। ऐसे में नेशनल टीम या अपनी पसंदीदा आईपीएल टीम के लिए चीयर करना एक सामूहिक अनुभव होता है, जो लोगों को एक साथ लाता है। इस दौरान, दैनिक जीवन से जुड़ी कहानियों 7और मेलो ड्रामा से भरपूर धारावाहिकों का आकर्षण थोड़ा फीका पड़ सकता है। क्रिकेट का क्षण भर में बदल जाने वाला माहौल और उससे जुड़ी अनिश्चितता दर्शकों को बांधे रखती है, जबकि धारावाहिक अपनी धीमी गति और लंबी चलने वाली कहानियों के कारण इस दौरान कम प्राथमिकता पा सकते हैं।दूसरी ओर, यह भी सच है कि टेलीविजन धारावाहिकों का अपना एक विशेष दर्शक वर्ग होता है जिनका वर्षों से चल रहे धारावाहिकों हैं और उन्होंने अपने दर्शकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बना लिया है। ये दर्शक अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों से गहराई से जुड़े होते हैं और नियमित रूप से अपने धारावाहिक देखना उनकी दैनिक आदत का हिस्सा बन जाता है। ऐसे दर्शक क्रिकेट मैचों के बावजूद अपने धारावाहिकों के लिए समय निकाल सकते हैं, या तो रिकॉर्ड करके बाद में देख सकते हैं या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी धारावाहिकों पर क्रिकेट का समान प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम, जैसे कि समाचार, रियलिटी शो या बच्चों के कार्यक्रम, क्रिकेट की लोकप्रियता से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हो सकते हैं। समाचार देखने वाले दर्शक दिनभर की घटनाओं से अपडेट रहने के लिए निश्चित समय पर टेलीविजन देखते हैं, जबकि रियलिटी शो का अपना एक अलग दर्शक वर्ग होता है जो प्रतियोगियों और ड्रामा में रुचि रखता है। बच्चों के कार्यक्रम अक्सर घरों में अलग समय पर देखे जाते हैं, जब क्रिकेट मैच प्रसारित नहीं हो रहे होते हैं।चैनलों की स्ट्रेटजी भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैनल अक्सर बड़े क्रिकेट आयोजनों के दौरान अपने लोकप्रिय धारावाहिकों के प्रसारण के समय में बदलाव करते हैं या उनका पुनः प्रसारण करते हैं ताकि दर्शकों को जोड़े रखा जा सके। कुछ चैनल क्रिकेट मैचों के दौरान अपने दूसरे चैनलों पर धारावाहिकों का प्रसारण जारी रखते हैं, जिससे उन दर्शकों को विकल्प मिलता है जो क्रिकेट में रुचि नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने दर्शकों को अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम देखने की स्वतंत्रता दी है, जिससे लाइव क्रिकेट मैचों के दौरान छूटे हुए धारावाहिकों को बाद में देखना संभव हो गया है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों का समान प्रभाव नहीं होता। टी 20 लीग जैसे आईपीएल, जो कम समय में अधिक रोमांच प्रदान करते हैं, दर्शकों को अधिक आकर्षित कर सकते हैं और धारावाहिकों की टीआरपी पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) मैच जो पूरे दिन चलते हैं, और टेस्ट मैच जो कई दिनों तक चलते हैं, उनका प्रभाव अलग-अलग हो

सकता है। टेस्ट मैचों का प्रभाव शायद सीमित हो क्योंकि वे आमतौर पर कार्य दिवसों में प्रसारित होते हैं और उनकी दर्शक संख्या टी 20 और ओडीआई की तुलना में कम होती है।क्रिकेट के प्रभाव के संदर्भ में धारावाहिकों की लोकप्रियता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अत्यधिक लोकप्रिय और लंबे समय से चल रहे धारावाहिकों के दर्शक शायद अधिक वफादार होते हैं और क्रिकेट के बावजूद उन्हें देखने की संभावना अधिक होती है। वहीं, नए या कम लोकप्रिय धारावाहिकों को क्रिकेट के कारण दर्शकों की कमी का अधिक सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में क्षेत्रीय विविधता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिकेट और टेलीविजन धारावाहिकों की लोकप्रियता अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में क्रिकेट का क्रेज बहुत अधिक होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय धारावाहिकों का अधिक महत्व होता है। इसलिए, क्रिकेट का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है। सच कहा जाए तो यह कहना मुश्किल है कि क्या आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैच श्रृंखलाएँ निश्चित रूप से टेलीविजन धारावाहिकों की टीआरपी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं या नहीं। एक प्रसिद्ध फि ल्म समीक्षक के अनुसार यह एक जटिल विषय है जो कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें क्रिकेट मैचों का समय, धारावाहिकों की लोकप्रियता, दर्शकों की प्राथमिकताएँ और चैनलों की स्ट्रेटजी शामिल हैं। हालांकि, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़े क्रिकेट आयोजनों के दौरान टेलीविजन देखने के पैटर्न में बदलाव आता है। कुछ दर्शक निश्चित रूप से क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे धारावाहिकों की तात्कालिक दर्शक संख्या में कमी आ सकती है। लेकिन, वफादार दर्शक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धता इस प्रभाव को कुछ हद तक कम करती है। यह भी सच है कि क्रिकेट और टेलीविजन धारावाहिक दोनों ही भारतीय मनोरंजन उद्योग के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों ही अपने-अपने तरीके से दर्शकों को आकर्षित करते हैं। शायद यह कहना अधिक सटीक होगा कि क्रिकेट की लोकप्रियता के चरम समय में धारावाहिकों को दर्शकों के ध्यान के लिए थोड़ी अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी टीआरपी हमेशा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

भविष्य में, जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और अधिक लोकप्रिय होते जाएंगे, दर्शकों के पास अपनी पसंद के कार्यक्रमों को देखने का अधिक विकल्प होगा। इससे लाइव क्रिकेट मैचों और टेलीविजन धारावाहिकों के बीच सीधा टकराव कम हो सकता है, क्योंकि दर्शक अपनी सुविधानुसार दोनों का आनंद ले सकेंगे। यह कहा जा सकता है कि आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैच श्रृंखलाएँ निश्चित रूप से टेलीविजन देखने के पैटर्न को प्रभावित करती हैं और कुछ हद तक धारावाहिकों की तात्कालिक टीआरपी पर दबाव डाल सकती हैं। हालांकि, धारावाहिकों का वफादार दर्शक वर्ग, चैनलों की स्ट्रेटजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता इस प्रभाव को पूरी तरह से नकारात्मक होने से रोकते हैं। यह एक सतत विकसित होने वाली गतिशील व्यवस्था है जिसमें दोनों ही माध्यम बनती है अपनी-अपनी जगह बनाए रखने और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लगातार अनुकूलन करते रहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह संतुलन किस ओर झुकता है और भारतीय मनोरंजन उद्योग किस प्रकार इन दोनों लोकप्रिय माध्यमों के सह-अस्तित्व को प्रबंधित करता है।

(लेखक के अपने विचार हैं)

दूसरा मत

पढ़ें और पढ़ाएं

एक शुभचिंतक

नई दिल्ली

दीप्ति अंगरीश
महिला संबंधी मामलों की वरिष्ठ लेखिका

जल संकट समाधान पर हो फोकस

गर्मी का आगमन होते ही दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में जल संकट की खबरें आम हो जाती हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी टैंकरों की कतारें, टूटे नल, और सूखते जलस्रोतों की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया में छा जाती हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कई क्षेत्रों में पानी के लिए झगड़े, कानून व्यवस्था की समस्या और जनस्वास्थ्य संकट तक उत्पन्न हो जाता है।

इस समस्या को हम वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन इसका स्थाई समाधान खोजने की दिशा में समाज और सरकार की सक्रियता अभी भी अपेक्षित है। भारत एक ऐसा देश है जहां भूजल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण और परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा ने पानी की समस्या को विकराल बना दिया है। देश में उपलब्ध कुल पानी का केवल 2.5 प्रतिशत ही पीने योग्य है, और वह भी लगातार घटता जा रहा है।

दिल्ली जैसे महानगरों में यमुना जैसी प्रमुख नदी प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार बन चुकी है। जल निकायों की अनदेखी और अनियोजित शहरी विकास जल संकट को और बढ़ा रहा है। इस पर तुर्रा यह कि बारिश के पानी को संजोने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं बन पाई है। वर्षा जल संचयन जैसे उपाय अब भी अधिकतर कागजों में ही सिमटे हैं।

समस्या के समाधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है – नीतिगत दृढ़ता और सामाजिक सहभागिता। जल संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर जनभागीदारी के रूप में अपनाना होगा। गांवों से लेकर शहरों तक पारंपरिक जल स्रोतों की पहचान, पुनरुद्धार और संरक्षण जरूरी है। साथ ही, जल नीति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जल उपयोग के प्रति जवाबदेही और मितव्ययिता को बढ़ावा मिले।

इसके अतिरिक्त, स्कूलों और समुदायों में जल शिक्षा को भी प्रमुखता देनी चाहिए, ताकि जल संरक्षण केवल नारा न रहकर व्यवहार बन सके। पुनर्भरण प्रणाली, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, और जल निकायों की निगरानी के लिए तकनीक और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

धरती का 97% भाग पानी से ढका है, लेकिन केवल 2.5% से 2.75% पानी ही पीने योग्य है। भारत वर्ष 2011 में पहली बार जल संकट वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था। यूनिसेफ की 18 मार्च 2021 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 9.14% बच्चे गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। अनुमान है कि

2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी को पानी की भारी कमी झेलनी पड़ेगी।

भूजल संकट और शहरों की स्थिति

देश का 70% भूजल स्रोत सूख चुका है और पुनर्भरण दर 10% से भी कम रह गई है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर तो पहले ही जल संकट की सुर्खियाँ बन चुके हैं।

कानूनों की भरमार, लेकिन जमीनी हकीकत चिंताजनक

भारत में जल से संबंधित कई कानून हैं, जैसे-जल (प्रदूषण रोकथाम) अधिनियम 1974ः जल स्रोतों में अपशिष्ट विसर्जन पर रोक।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986ः जल गुणवत्ता की निगरानी।

वन अधिकार कानून 2006ः जल स्रोतों के संरक्षण की जिम्मेदारी समुदाय को देना।

पंचायती राज अधिनियम (73वां संशोधन)ः पेयजल को पंचायत की योजना में शामिल करना।

बाल अधिकार अधिनियम 1989ः बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल का अधिकार।

हालांकि, 2024 में किए गए संशोधन में जल प्रदूषण के मामलों में कारावास के प्रावधान को हटाकर जुमार्ना लगाने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे इसके दंडात्मक असर पर सवाल खड़े हो गए हैं।

नदी प्रदूषणः गंभीर चेतावनी

2023 की स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार, देश की 603 नदियों में से 279 नदियां प्रदूषित हैं। महाराष्ट्र में 55 और मध्य प्रदेश में 19 नदियाँ सबसे अधिक प्रदूषित पाई गईं।

समाधान की दिशा में पहल

ग्राम सभा को जिम्मेदारी देनाः जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समितियां बनें।

नदी-तालाब पुनर्जीवनः पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाए।

बरसात जल संचयनः बोराबंधान जैसे उपायों से पानी को रोकने की व्यवस्था।

हैंडपंप की मरम्मतः मध्यप्रदेश में 14,191 हैंडपंप खराब हैं, इन्हें तत्काल दुरुस्त करना जरूरी है।

पारिस्थितिकीय विशेषज्ञों की नियुक्तिः जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को समझने वाले लोग निगरानी में शामिल हों।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जल संकट को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी न मानकर इसे समाज की साझी जिम्मेदारी बनाया जाए। पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन है – और इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है।

क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

भारतीय सिविल सेवा यानी भारतीय प्रशासन का एक स्टील फ्रेम

विजय गर्ग
वरिष्ठ शैक्षणिक स्तंभकार

भारत की सिविल सेवा देश की प्रशासनिक प्रणाली की रीढ़ है। भारत जैसे विशाल और विविध देश के प्रशासन को अपने प्राकृतिक, आर्थिक और मानव संसाधनों के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में प्रशासन चलाने की अंतिम जिम्मेदारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की है लेकिन यह मुट्ठी भर प्रतिनिधि यानी मंत्रियों से आधुनिक प्रशासन की कई समस्याओं से निपटने और संभालने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मंत्री नीति निर्धारित करते हैं और यह सिविल सेवकों के लिए इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और पूरा करना है। यही कारण है कि भारतीय सिविल सेवा को 'सरकार का प्रशासनिक अंग' के रूप में भी जाना जाता है।

ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल सिविल सर्विस नामक भारतीय सिविल सेवा को पहली बार भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में लाया। 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने नई भर्तियों के प्रशिक्षण के लिए की थी। और बाद में 1806 में, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना रंगरूटों को दो साल का प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हैली बरी में की गई थी। इसके अलावा, भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर अधिनियम के साथ शुरू की गई थी।

1853 के चार्टर अधिनियम ने सैद्धांतिक रूप से भारतीयों को सिविल सेवाओं को खोल दिया। लेकिन भारतीयों को शुरू से ही उच्च पदों से रोक दिया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान, भारतीयों को ज्यादातर कानून और नीति-निर्माण निकायों से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, भर्ती परीक्षा भी केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। और वह भी केवल अंग्रेजी में और विषयों में ग्रीक और लैटिन भाषाएं शामिल थीं, जिन्होंने भारतीयों के लिए चीजों को बदतर बना दिया। हालांकि, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनने के बाद से ही भारतीयों ने इसे भारतीय सिविल सेवा के प्रतिष्ठित रैंकों में बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन सिविल सेवा में प्रवेश करना अभी भी भारतीयों के लिए एक बेहद मुश्किल काम था।

1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अपने क्षेत्रों के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने अगस्त 1947 में भारत से बाहर किए जाने तक नियंत्रण और अधिकार की स्थिति ब्रिटिश हाथों में रखा।

एक सिविल सेवक कोई भी व्यक्ति होता है, जो संघ या राज्य सरकार के संघ या राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त भारत का नागरिक होता है। और इसमें रक्षा सेवा में एक नागरिक भी शामिल होता है। सिविल सेवा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति की खुशी में सेवा करते हैं। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 311 की राजनीति से प्रेरित हितों या प्रतिशोध की कार्रवाई से अच्छी तरह से परिरक्षित हैं। सिविल सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं; हालांकि, सरकार के सभी कर्मचारी सिविल सेवक नहीं हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार में प्रशासक विदेशी मिशनों / दूतावासों में उत्सर्जन कर संग्राहक और राजस्व आयुक्त सिविल सेवा ने पुलिस अधिकारियों को कमीशन दिया संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों में स्थायी प्रतिनिधि और कर्मचारी अध्यक्ष प्रबंध निदेशक विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य भारत सरकार और उससे ऊपर के संयुक्त सचिव के पद पर सभी नियुक्तियां, और अन्य प्रमुख नियुक्तियां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती

हैं। हालांकि, संयुक्त सचिव से नीचे रैंक में सभी नियुक्तियां सिविल सेवा बोर्ड द्वारा की जाती हैं।

सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक भारतीय गणराज्य के कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कैबिनेट सचिव भी होता है। वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं; भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख और सरकार के अधीन अन्य सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख भी। वह भारत के आदेश के क्रम में 11 वां स्थान भी रखते हैं।

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को आमतौर पर यूपीएससी परीक्षा के रूप में जाना जाता है। आईसीएस परीक्षा को कभी-कभी आईएएस परीक्षा के रूप में जाना जाता है जो विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस के रूप में जानी जाने वाली भारतीय सिविल सेवा की शाखाओं में से एक के लिए आयोजित की जाती है। सिविल सेवकों को न केवल खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है, बल्कि राज्य सरकारों के कुछ अधिकारियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परीक्षा का उपयोग सरकारी कार्यालय के विभिन्न विभागों में उपलब्ध विभिन्न आधिकारिक पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है।

भारतीय सिविल सेवा के लिए भर्ती परीक्षा, निश्चित रूप से, दुनिया भर में कठोर परीक्षाओं में से एक है। समाज में बदलते रुझान, साथ ही अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान और मानवाधिकारों जैसे क्षेत्रों पर अधिक तनाव को अनिवार्य बनाती है। परीक्षा में प्रबंधकीय कौशल के परीक्षण पर भी बहुत कम तनाव है। हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन विभिन्न नौकरियों में विशेषज्ञों की आवश्यकता भी पैदा करते हैं। तेजी से आगे बढ़ने वाली तकनीक और हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की उच्च डिग्री के साथ, देश अब विशेष कौशल की आवश्यकता वाले पदों में सामान्यवादियों को रखने का जोखिम नहीं उठा सकता है। सार्वजनिक सेवा से निजी क्षेत्र में सिविल सेवकों का प्रवेश और निकास और इसके विपरीत सिविल सेवाओं की नौकरियों को अधिक आकर्षक बना देगा, इस प्रकार यह एक नई अर्थव्यवस्था की नौकरी बना देगा। सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

सिविल सेवा भर्ती के लिए पेश किया गया प्रशिक्षण सबसे व्यापक प्रशिक्षण प्रणालियों में से एक है। वे अंतराल जहां प्रशिक्षण सुविधाएं नए रुझानों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें समय-समय पर पहचान करनी होगी ताकि प्रशिक्षण को प्रेरण स्तर पर सही प्रदान किया जा सके।

संविधान में नई अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के लिए दो-तिहाई बहुमत से हल करने के लिए राज्यसभा (भारत की संसद के ऊपरी सदन) को शक्ति देकर अधिक सिविल सेवा शाखाओं को स्थापित करने का प्रावधान है। भारतीय वन सेवा और भारतीय विदेश सेवा इस संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित दो सेवाएं हैं।

(लेखक सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं)

एक युग का अंतः क्रिकेट के महानायकों को सलाम

प्रियंका सौरभ
स्तंभकार

जब भी इतिहास के पन्नों में भारतीय क्रिकेट की बात होगी, कुछ नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेंगे। यह वे नाम हैं जिन्होंने न केवल रिकॉर्ड बनाए, बल्कि खेल को एक नई पहचान दी, एक नया जुनून दिया। हाल ही में, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दो महानायक झ विराट कोहली और रोहित शर्मा झ अपने सफेद कपड़ों में आखिरी बार नजर आए। यह न केवल एक व्यक्तिगत विदाई थी, बल्कि एक युग का अंत भी था।

विराट कोहली और रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट में योगदान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उन पलों में है जब उन्होंने देश को जीत की गर्वित अनुभूति कराई, उन संघर्षों में है जब उन्होंने मुश्किल हालातों में टीम का नेतृत्व किया। ये दोनों खिलाड़ी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को ग्लोबल स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

जब भी बात भारतीय क्रिकेट में आक्रामकता की होती है, विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है। उनका जुनून, मैदान पर उनकी आक्रामकता, और बल्ले से उनके रनों की बौछार ने उन्हें आधुनिक क्रिकेट का 'रन मशीन' बना दिया। 100 से अधिक टेस्ट मैच, 29 शतक और कई यादगार पारियां उनके नाम हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर, उन्होंने भारतीय टीम को वह आत्मविश्वास दिया जिसने हर विरोधी टीम को चुनौती देने की हिम्मत दी।

विराट का मैदान पर जोश और उत्साह हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। उनकी बल्लेबाजी में न केवल शक्ति, बल्कि एक अद्भुत कला भी है। उनका हर शॉट एक बयान है, हर रन एक कहानी है। उन्होंने न केवल अपने बल्ले से, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी क्रिकेट की दुनिया को प्रभावित किया है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने न केवल विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि एक नई पहचान बनाई।

रोहितः हिटमैन की क्लास

दूसरी ओर, रोहित शर्मा का खेल एक अलग ही कला है। उनकी

बल्लेबाजी में वह शांति और संयम है जो उन्हें एक अद्वितीय खिलाड़ी बनाती है। जहाँ विराट आक्रामकता का प्रतीक हैं, वहीं रोहित अपने क्लासिक स्ट्रोक्स से खेल की बारीकियों को दशार्ते हैं। उनका दोहरा शतक और शुरूआती ओवरों में उनका आक्रामक रुख आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के दिलों में बसा हुआ है।

रोहित के कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबी पारियाँ एक अलग ही आनंद देती हैं। उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। उनकी समझ, उनकी तकनीक और उनका आत्मविश्वास, उन्हें क्रिकेट की दुनिया का 'हिटमैन' बनाता है।

इन दोनों महान खिलाड़ियों का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मोड़ है। यह एक ऐसा पल है जब हमें न केवल उनके योगदान को याद करना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करना चाहिए। यह वह वक्त है जब हमें नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि वे भी इसी तरह की विरासत छोड़ सकें।

खेल से परे की कहानियां

विराट और रोहित केवल मैदान के ही नायक नहीं हैं। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगियों में भी अनेक प्रेरणादायक कहानियाँ लिखीं हैं। विराट की फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता और रोहित का धैर्य, दोनों ही हमें जीवन में अनुशासन और संकल्प की महत्वपूर्ण सीख देते हैं।

विराट का संघर्ष एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने का सफर है, जबकि रोहित की कहानी उस प्रतिभा की है जिसने मुश्किल हालातों में भी अपने खेल को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। इन दोनों ने हमें सिखाया है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यदि आपके पास संकल्प और मेहनत है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं।

विदाई का पल

जैसे ही वे मैदान से आखिरी बार लौटे, हर आँख नम थी, हर दिल भारी था। यह उस विरासत का अंत था जिसने करोड़ों दिलों को जोड़ा, जिसे हर भारतीय ने गर्व से देखा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, 'हर अंत एक नई शुरूआत है।' इन दिग्गजों की विदाई सिर्फ एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी के सपनों की शुरूआत भी है।

आखिरी सलाम

तो, सलाम उन पलों को जो हमें गर्व से भरते हैं, सलाम उन कहानियों को जो हमें प्रेरित करती हैं, और सलाम उन महानायकों को जिन्होंने हमें सिखाया कि हार-जीत खेल का हिस्सा है, पर संघर्ष ही असली जीत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा न केवल महान बल्लेबाज हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिल और धड़कन भी हैं। विराट की आक्रामकता और रोहित की क्लासिक बल्लेबाजी ने हमें अनगिनत यादें दी हैं। एक युग का अंत, लेकिन उनकी विरासत हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। सलाम चैंपियंस!

धन्यवाद, चैंपियंस! आप हमेशा दिल और धड़कन बने रहेंगे।

कोहली का टेस्ट संन्यास

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना एक युग का अंत है। उनके योगदान, उनके नेतृत्व और उनके खेल के प्रति समर्पण को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। कोहली के संन्यास के बाद, क्रिकेट की दुनिया उनकी आक्रामकता, उनकी तीव्रता और उनकी शानदार क्रिकेट बुद्धिमत्ता को याद करेगी। लेकिन जो कुछ भी बचा रहेगा, वह यह है कि एक खिलाड़ी ने केवल अपने रन ही नहीं बनाए, बल्कि भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। कोहली ने जो काम किया, वह न केवल आंकड़ों में है, बल्कि उस भावना में है जिसे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में डाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का नाम टेस्ट क्रिकेट में हमेशा सबसे ऊपर रहे।

डॉ. सत्यवान सौरभ
वरिष्ठ स्तंभकार, हरियाणा

विराट कोहली, जिन्हें आधुनिक क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, ने 21वीं सदी में क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। उनके आक्रामक बल्लेबाजी, प्रेरणादायक नेतृत्व और खेल के प्रति निष्ठा ने क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की वह प्रक्रिया है, जहां टीम की मानसिकता, दृष्टिकोण और दृष्टि उनके नेतृत्व में विकसित हुई।

जब विराट कोहली ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे क्रिकेट की दुनिया में इतनी बड़ी छाप छोड़ेंगे। उस समय भारत क्रिकेट के एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। दिग्गज खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के संन्यास के बाद भारत को एक नए नेता की आवश्यकता थी, और कोहली ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया।

कोहली का क्रिकेट में प्रवेश आक्रामकता और सफलता की इच्छा से भरा था। पहले के खिलाड़ियों की तुलना में जो अधिक संयमित और नियंत्रित थे, कोहली का खेल तरीका एकदम अलग था। उन्होंने क्रिकेट के नियमों को तोड़ा और अपने आक्रामक खेल, फिटनेस के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता की आकांक्षा से भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। जल्दी ही भारतीय टीम फिटनेस और आक्रामकता के एक नए युग का प्रतीक बन गई और कोहली इस बदलाव के सिरमौर थे।

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड स्वयं में एक मिसाल है। 27 टेस्ट शतक के साथ, वे वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने

वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। भारत के लिए, वे सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 8,000 से अधिक टेस्ट रन और अद्वितीय औसत के साथ, उन्होंने क्रिकेट के इस सबसे कठिन प्रारूप में खुद को साबित किया है।

लेकिन कोहली की महानता केवल उनके आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को कैसे पुनः परिभाषित किया। उस दौर में जब तेज गेंदबाज और चुनौतीपूर्ण पिचें अक्सर प्रमुख रहती थीं, कोहली ने बिना किसी डर के अपने कौशल का परिचय दिया। चाहे इंग्लैंड की स्विंग करती पिचें हो या भारत की स्पिनिंग पिचें, कोहली ने हर चुनौती का सामना किया।

उनकी यात्रा 2014 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद खुद को और बेहतर बनाने का

फैसला किया। उन्होंने अपने खेल में लगातार सुधार किया और अब वे टेस्ट क्रिकेट के सबसे सशक्त बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। कोहली ने न केवल रन बनाए, बल्कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नया मानक स्थापित किया।

कोहली का व्यक्तिगत प्रदर्शन भले ही अद्वितीय हो, लेकिन उनका नेतृत्व ही उनकी असली धरोहर है। 2017 में, कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली और महेन्द्र सिंह धोनी से यह जिम्मेदारी ली। कोहली के नेतृत्व में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूत और सफल टीम के रूप में पहचान बनाई। उनकी कप्तानी में भारत ने क्छ्उ टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान लंबे समय तक बरकरार रखा।

कोहली की कप्तानी में भारत ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल की, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। उनकी कप्तानी में भारत ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज की धरती हो। उनका नेतृत्व न केवल रणनीतिक था, बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही का भी माहौल बनाया। कोहली का नेतृत्व भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक लेकर गया।

टेस्ट क्रिकेट का असली उद्देश्य धैर्य, तकनीक और मानसिकता की परीक्षा लेना है। यह एक खिलाड़ी की चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। कोहली ने बार-बार यह साबित किया कि उनके पास टेस्ट क्रिकेट में सफल होने की सारी क्षमताएं हैं। उनका समर्पण इस प्रारूप के प्रति हमेशा स्पष्ट था। कुछ क्रिकेटर जहां टी20 लीग और वनडे क्रिकेट की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं कोहली ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी। इस खेल में उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती थी कि भारत हमेशा एक मजबूत बल्लेबाज के साथ मैदान में उतरे।

कोहली के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी कठिन परिस्थितियों में बनाए गए शतक हैं। 2014 में एडिलेड में उनका शतक एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां उन्होंने भारतीय टीम की गिरावट के बीच अपनी अद्वितीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके शतक उनके टेस्ट क्रिकेट में अपार योगदान को दशार्ते हैं।

लेकिन यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खेलने के तरीके में भी बदलाव किया। उनका मानना था कि टेस्ट क्रिकेट को उत्साह और उद्देश्य के साथ खेलना चाहिए। उनका मानसिकता हमेशा यह थी कि टेस्ट क्रिकेट खेल का सबसे शुद्ध रूप है, और उनका लक्ष्य था कि वे इसमें जितना हो सके योगदान दें। यही कारण है कि जब वे अपने टेस्ट करियर से विदाई ले रहे हैं, तो यह उनके खेल के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और सम्मान को दशार्ता है।

जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से विदा ले रहे हैं, तो इसे केवल उनके आंकड़ों में ही नहीं देखा जाना चाहिए। उनका वास्तविक प्रभाव भारतीय क्रिकेट की संस्कृति पर था। जब कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली, तो उन्होंने क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों के दृष्टिकोण में एक क्रांति ला दी। उनकी फिटनेस पर जोर, कड़ी मेहनत की प्रतिबद्धता और हर छोटी-से-छोटी बात पर ध्यान देने का तरीका यह दशार्ता है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनका प्रभाव भारतीय क्रिकेट की युवा पीढ़ी पर गहरा था, जो आज भी उनकी प्रतिबद्धता और आक्रामकता से प्रेरित होकर खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

कोहली केवल एक क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि एक ब्रांड, एक आदर्श और खेल के प्रति एक मिशन के प्रतीक हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल अच्छा क्रिकेट खेलने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपको समर्पित, केंद्रित और महानता की ओर लगातार बढ़ते रहना पड़ता है। उनका मानसिक धैर्य और कार्य नैतिकता भविष्य की पीढ़ियों के लिए मानक बन गया है।

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना एक युग का अंत है। उनके योगदान, उनके नेतृत्व और उनके खेल के प्रति समर्पण को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। कोहली के संन्यास के बाद, क्रिकेट की दुनिया उनकी आक्रामकता, उनकी तीव्रता और उनकी शानदार क्रिकेट बुद्धिमत्ता को याद करेगी। लेकिन जो कुछ भी बचा रहेगा, वह यह है कि एक खिलाड़ी ने केवल अपने रन ही नहीं बनाए, बल्कि भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी।

कोहली ने जो काम किया, वह न केवल आंकड़ों में है, बल्कि उस भावना में है जिसे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में डाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का नाम टेस्ट क्रिकेट में हमेशा सबसे ऊपर रहे।

विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में अलविदा, एक ऐसी धरोहर छोड़ते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

दूसरा मत

हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

47
YEARS OF EXCELLENCE
हार्दिक शुभकामनाएं
!! RADHA SOAMI JI !!
KJ
Kasturi Jewellers®
SINCE 1978
100% HALLMARK JEWELLERY SHOWROOM
#GOLD #DIAMOND JEWELLERY #SOLITAIRES
100% Lifetime Maintenance Free
100% Buy Back Diamond Jewellery
100% Certified Diamond Jewellery
Shop No. 15, 16, 17, 18, SDM Market, Mangal Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110 059
Shop No. 54-55, Main Pankha Road, Opp. Sagar Pur Police Station, New Delhi-110 046
Kasturi Lal Ph. 98186 09444 | Manish (Monu) Ph. 98186 11313

'दूसरा मत' प्रकाशन

'आमने-सामने' अपने-आप में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू-संग्रह है। इस संग्रह में देश की 62 अहम शख़्सियतों एवं हस्तियों के साक्षात्कार शामिल हैं। यह संग्रह देश ही नहीं विदेशों में भी ख़ासा चर्चित रहा है।

देश के जाने-माने प्रकाशन 'राजपाल' के प्रकाशक एवं डीएवी मैनेजमेंट कमिटी के वायस प्रेसिडेंट विश्वनाथ जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है, -"इस तरह के विशाल इंटरव्यू-संग्रह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभी तक नहीं आए हैं।

आमने-सामने (मूल्य 750/)

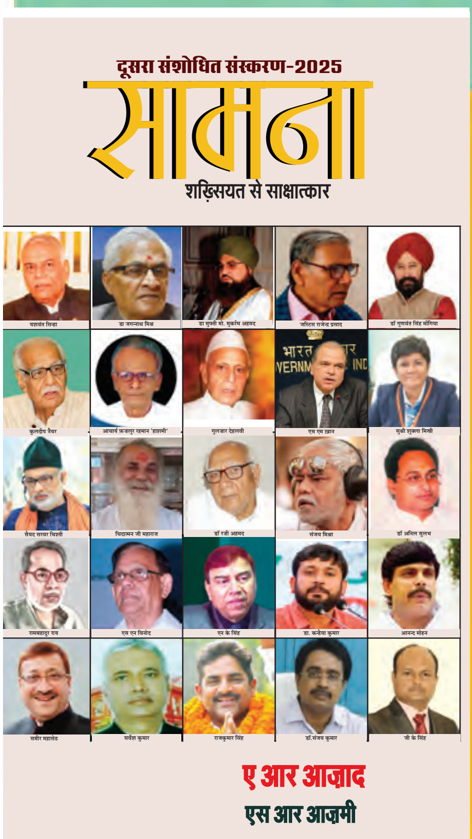

'सामना' भी एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू-संग्रह के तौर पर 'आमने-सामने' की तरह सामने आया है। इसे भी शख़्सियतों एवं साक्षात्कार की कला को क़ुबूल करने वाले लोगों ने हाथों-हाथ लिया है। इस संग्रह में देश की विभिन्न क्षेत्रों की 82 हस्तियों की इंटरव्यू की शक्ल में लेखा-जोखा एवं उनकी हस्ती की पड़ताल है।

अपने-अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले और देश व दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने वाले लोगों के एक समूह विशेष इस अंक में शामिल हैं।

सामना (मूल्य 1100/)